हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

14 जून, 2005

खण्ड–2, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 14 जून, 2005

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3) 20
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव––	(3) 29
नहरों के छोरों तक पानी न बहने संबंधी	(3) 29
वक्तव्य––	(3) 30
राजस्व मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी	(3) 30
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं	(8) 32

मूल्य : '0

पृष्ठ संख्या

सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र (3) 32

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (3) 33

बैठक का समय बढ़ाना (3) 71

अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत (3) 71

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (3) 71

बैठक का समय बढ़ाना (3) 78

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (3) 78

HLS/ਕS/12

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 14 जून, 2005

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस० चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सवाल होंगे।

Criteria Adopted for the Appointment of Members of the H.P.S.C.

***5. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to State —

(a) whether any criteria and qualification has been adopted for the appointment of the present members of Haryana Public Service Commission including its Chairman, if so, the details thereof; and

(b) the names of the present incumbent members of aforesaid Commission who were appointed against the quota of persons as provided in proviso to Article 316 of the Constitution of India alongwith the details of the offices held by them at least for ten years under the State Government at the date of their appointments?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) No qualifications have been prescribed under the Constitution of India for the appointment of Chairman and Members of the State Public Service Commission. No criteria have been prescribed separately for these appointments. The appointment of the Chairman/Members of the State Public Service Commission is made as per the provision of Article 316 of the Constitution of India. This Article provides that the Chairman and Members of the Commission are to be appointed by the Governor of the State. The Governor appoints the Chairman/Members on the recommendation of the Chief Minister who makes these recommendations to the Governor in accordance with the provisions contained in Rule 28 (2) (vii) of Rules of Business of the Government of Haryana, 1977.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

(b) The names of the present Members alongwith details of offices held by them for atleast ten years under the Government of Haryana are as under :—

No.	Name	Post Held
(i)	Sh. Dungar Ram, Member	Lecturer Govt. National College, Sirsa, Education Department. 35 years experience.
(ii)	Sh. Chattar Singh, Member	Distt. Transport Officer, Transport Department, 1978-95.
(iii)	Sh. Om Parkash, Member	District Attorney. 14-1-1991 to 9-8-2004, in Prosecution Department.
(iv)	Mrs. Santosh Singh, Member	Teacher, 1982-2004.
(v)	Sh. Ram Kumar Kashyap, Member	Field Assistant under Economical and Statistical Advisor, Haryana. In Planning Department.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो मेरे सवाल के जवाब में इन्होंने सदन के पटल पर जानकारी दी है उसमें क्या ये बतायेंगे कि पार्ट 'बी' के जवाब में उन्होंने जो नाम लिए हैं क्या इनकी सर्विस कैरियर के दौरान इनके खिलाफ इनको कभी चार्जशीट किया गया या इनके खिलाफ डिपार्टमैंट में क्या कोई शिकायत रही ? पार्ट 'ए' में इन्होंने कहा है कि अपौइंटमैंट की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मंत्री महोदय ने जो मेम्बर सर्विस सैक्टर से हैं उनके नाम दिए हैं क्या ये बतायेंगे कि जो नॉन सर्विस सैक्टर से है उनके नाम क्या हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक इनकी सर्विस कैरियर में कम्पलेन्ट की बात है, उसके बारे में इन्होंने पहले पूछा नहीं था इसलिए यह इन्फर्मेशन इन विभागों से पता करवा कर माननीय सदस्य के पास भेज देंगे। जहां तक सदस्यगण की योग्यता का सवाल है यह इन्फर्मेशन मेरे पास है, यह मैं आपके माध्यम से पढ़कर बताता हूं। श्री मेहर सिंह, सैनी अध्यक्ष; बी०ए०एम०एस०; ये गैर सरकारी सदस्य हैं श्री डूंगर राम, एम०ए० इंगलिश, सदस्य; सरकारी, श्री छतर सिंह, बी०ई० इलैक्ट्रिकल; सरकारी, श्री युद्धवीर सिंह, सदस्य, ग्रेजुएट; गैर सरकारी, श्री सतवीर सिंह, अधिवक्ता, सदस्य बी०ए० ऑनर्स एल०एल०बी०; गैर सरकारी, श्री ओम प्रकाश बी०ए० एल०एल०बी०; सरकारी डॉ० रणदीप सिंह हुड्डा, मैंबर, बी०एस०सी० ऐग्रोनोमी एंड एम०एस०सी० ऐग्रोनोमी, बी०एच०टी० एल०एल०बी०; गैर सरकारी, श्रीमती संतोष सिंह, एम०एस०सी०, बी०एड०; सरकारी और श्री राम कुमार कश्यप, एम०ए० अर्थशास्त्र, एल०एल०बी०; सरकारी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एच०पी०एस०सी० सदस्यों की क्वालिफिकेशन बताई है। जो चेयरमैन हैं इनकी क्वालिफिकेशन बी०ए०एम०एस० बताई है। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच करवाई है कि इनकी ये डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी

की हैं और कौन से कोर्स के इक्विलैंट हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जो नाम इन्होंने लिए हैं। इस बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले कई सालों में एच०पी०एस०सी० की भर्तियों में कई बार अनियमितताये इन मैम्बर्ज और चेयरमैन ने की, जिनके खिलाफ लिखित शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं। यहां तक कि इस बारे में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हुई हैं। आदरणीय मंत्री जी बताएंगे कि संविधान की धारा 317 के मुताबिक जहां पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों के खिलाफ अगर अनियमितताओं की शिकायतें आती हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं ? मंत्री जी जो यह शिकायतें चेयरमैन और मैम्बर्ज के खिलाफ आई हैं क्या उनकी जांच करवायेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन सदन में देंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं उनकी योग्यता को लेकर है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन पर कोई शक है मैं उनको सरकार की तरफ से और इस सदन को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि माननीय सदस्य लिखकर दें तो सरकार उनकी योग्यता की वैधता के बारे में अवश्य जांच करवायेगी। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने सप्लीमैंट्री के रूप में पूछा है कि उनके खिलाफ अनियमितताएं और एलीगेशंज हैं। माननीय सदस्य ने विषयों की चर्चा भी की है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जिस अनियमितता के बारे में, जिस भर्ती के बारे में, कोई गड़बड़ी के बारे में और जिस व्यक्ति विशेष के बारे में माननीय सदस्य कोई मैटीरियल सरकार को देंगे तो टाईम बाउंड फ्रेम के अन्दर इन्क्वायरी करवाएंगे और किसी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। हम उसको लोजीकल कन्क्लूजन पर पहुंचा कर आयेंगे। यदि आप मैटीरियल इन्फोर्मेशन सरकार को सप्लाई करेंगे और जो मैटीरियल इन्फोर्मेशन माननीय सदस्य के पास है या और कोई व्यक्ति जो पूरे हरियाणा से देना चाहता है, वह हमें सप्लाई करे, हम उसका स्वागत करेंगे और पूर्ण जांच करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात के लिए विशेष तौर से जागरूक है। एक भ्रष्टाचार और ऊपर से उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव जो योग्य हैं अगर इस प्रकार का कोई इल्जाम सही पाया जायेगा तो कानूनी दायरे में ऐसे व्यक्ति के साथ निपटा जायेगा। यह मैं माननीय सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो क्वालिफिकेशन चेयरमैन और मैम्बर्ज की है वह कम से कम जिन लोगों का वे इन्टरव्यू लेते हैं उनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन उनकी है। जैसे एच०सी०एस० और आई०ए०एस० जो प्रोमोटी होते हैं, या इन्जीनियर होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट या और कई किस्म के क्वालीफाईड आदमी जिनको वे भर्ती करते हैं, क्या इस बारे में हरियाणा सरकार भारत सरकार को प्रोपोज करेगी कि चेयरमैन और सदस्यों की क्वालिफिकेशन उन व्यक्तियों से ज्यादा होनी चाहिए जिनका वे इन्टरव्यू करते हैं ताकि वे जस्टीफाई कर सकें और यदि इसके लिए पार्लियामेन्ट को रूल्ज में एमेंडमेन्ट करने की जरूरत हो तो वह करे। दूसरा सवाल संविधान के तहत है कि चेयरमैन और मैम्बर्ज के खिलाफ अनियमितताएं है उन पर कार्यवाही सरकार कर सकती है। लॉ ऑफ दि लैंड चेयरमैन, श्री बागड जो हैं उनके खिलाफ डायरेक्ट भ्रष्टाचार के एलीगेशन लगे हैं जो स्ट्रेटवे उनके खिलाफ जाते हैं और एफ०आई०आर० दर्ज हो सकती है, जो रिकार्ड पर मौजूद है। सरकार के पास जो मैटीरियल है या जो शिकायतें हैं क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाने का सरकार कष्ट करेगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं। पहला है योग्यता के बारे में। यह सही है स्पीकर सर, ऐसी विडम्बना हुई है। वर्षों से संविधान के निर्माताओं ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू और बाबा साहिब अम्बेडकर ने यह कभी नहीं सोचा था कि इन संस्थाओं का ऐसा हाल होगा। एक जमाना था स्पीकर सर, जब बड़ी इन्टीग्रेटी के और बहुत निष्पक्ष व्यक्ति इन पदों पर आते थे। अब कई जगह पर कई प्रकार के इलजाम इन पर लगते हैं। यह सही है कि यह एक पोलिसी का मामला है जिसके तहत पूरे हिन्दुस्तान में पूरे सर्वे के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों और अध्यक्षों की योग्यता को निर्धारण किया जाये, परन्तु यह मामला हमारी सरकार की परिधि में नहीं आता जैसा कि माननीय सदस्य ने खुद कहा है कि इसके लिए संविधान के अन्दर एमैंडमेंट करनी, पड़ेगी, जिसके लिए केवल पार्लियामेंट ही सक्षम है। जहां तक सवाल है पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्यों की इन्कवायरी का, मैं आपके माध्यम से हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कम्पलेंट हमारे पास आयेगी या जो आई हैं। उनका जल्दी से जल्दी समय सीमा के अन्दर और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से जिसमें दोषी को सजा भी मिले और निर्दोष उसमें फंसे नहीं, इस मंशा से निपटारा किया जाएगा। फिर भी कोई कम्पलेण्ट यदि माननीय सदस्य के नोटिस में है तो वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सरकार को लिखकर दे दें, हम उसको टाइम बाउंड पीरियड में यानि 3 से 6 महीने के अन्दर निपटा कर के माननीय सदस्य को, इस हाउस को और अध्यक्ष महोदय, आपको इन्फोर्म करेंगे।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जाते जाते पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी कंस्टीच्यूशनल बॉडी को एक राजनीतिक लोगों के हाथ का खिलौना बना दिया था। जिस किसी सदस्य के 3 महीने बकाया थे उससे इस्तीफा लेकर उसकी पत्नी को मैम्बर बना दिया और जिनके 6 महीने बकाया थे उनसे इस्तीफा लेकर दूसरे आदमी को मैम्बर बना दिया। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बड़ा भारी डिस्प्यूट है और इसकी इंटीग्रेटी में भी डिस्प्यूट है मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके बाद जो भर्ती की जाएगी, उसमें निष्पक्षता बरती जाएगी या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहूंगा, क्योंकि आज हरियाणा में बहुत केस कोर्ट में पैंडिंग हैं। आज ज्यूडिशियल ओफिसर्ज के बहुत पद खाली पड़े हैं। ज्यूडिशियल ओफिसर्ज की रिक्रूटमैंट्स के लिए आमतौर से हाई कोर्ट के जज को एक्सपर्ट के तौर पर कमीशन में बुलाया जाता है। जैसा कि अब आम आदमी के सामने बात है कि कमीशन की इंटीग्रेटी डाउटफुल है। इस हालत में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ज्यूडिशियल ओफिसर्ज की भर्ती के लिए कोई और दूसरा तरीका अपनाएगी ताकि लोगों के सामने बात आए कि हरियाणा में भर्ती में निष्पक्षता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के दो सवाल पूछे हैं । यह सच है कि पिछली सरकार ने एक नायाब तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों और चेयरमैन को एक निश्चित अवधि के लिए लगाने का कार्य किया। अध्यक्ष महोदय आप जानते है और खुद कानून विद भी हैं कि सभी पूर्व सदस्यों से, जिन का समय कम रहा गया था उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद नए सदस्यों को सरकार ने मनोनीत कर दिया, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मलिक जी, आपने सही कहा है। It can best be described as travesty of constitutional process पर कई ऐसी बातें हो चुकी हैं जो कानूनी दायरे में आती हैं उसका

शायद और बदलाव सम्भव नहीं है। आपने औफिसर्ज की ओर खासतौर से दूसरे ज्यूडिशियल औफिसर्ज की नियुक्ति की चर्चा की । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग नियुक्तियों में बहुत ज्यादा देर लगाता था। इससे पहले बोर्ड और निगम की नियुक्तियां स्पैशलाइज कमेटी किया करती थी। हमारी सरकार ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऐडीशनल फंक्शनल अमैंडमैंड बिल लाने का निर्णय लिया है जो इस सदन में प्रस्तुत होगा। माननीय सदस्य उस पर विचार करेंगे जिसके तहत सभी बोर्ड और आयोग की जो नियुक्तियां हैं उनको हरियाणा लोक सेवा आयोग की परिधि से निकाल दिया है। जहां तक सवाल है ज्यूडिशियल औफिसर्ज की नियुक्ति का, हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो भी फोरमैलटीज हैं उनको जितनी जल्दी हो सके, पूरा करके नियुक्तियां करवाई जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि इसकी जांच के लिए इन्होंने हां की है और कहा है कि लिखकर दें और हम दोबारा से लिखकर देंगे। पिछली सरकार में हमने महामहिम राज्यपाल महोदय की सेवा में एक बहुत लम्बा चौड़ा खाका दिया था जिसमें HPSC ने जो गलत काम किए थे इस बारे में भी जानकारी दी थी कि किस तरह से उन दिनों मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला के दबाव में वे लोग काम करते थे और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे उन पुरानी दरखास्तों पर कार्यवाही करने बारे विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 316 में लिखा है कि एच०पी०एस०सी० का जब भी कोई मैंबर नियुक्त होगा तो वह किसी सरकारी बोर्ड, कारपोरेशन का सर्विंग या नान सर्विंग लीयन पर नहीं रह सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई एच०पी०एस०सी० का मैंबर नियुक्त होगा तो वह किसी दूसरे सरकारी आफिस में अपना लीयन नहीं रख सकता। जबकि पिछली सरकार के समय में एच०पी०एस०सी० के चेयरमैन मिस्टर बांगड़ एच०ए०यू० के लीयन पर थे। वे एच०ए०यू० के मुलाजिम थे और वहां पर वाईस चांसलर थे। एच०पी०एस०सी० का चेयरमैन बनाने के बाद भी उन्होंने एच०ए०यू० की नौकरी को नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त चौटाला साहब ने उनके साथ मिलकर एच०पी०एस०सी० के द्वारा की जानी वाली नियुक्तियों में धांधली की और उनके चहेते अफसरों के बच्चों को एच०पी०एस०सी० के थ्रू कानून को ताक पर रखकर नौकरियां दी। एच०पी०एस०सी० के चेयरमैन और सभी मैंबर पूर्व मुख्यमंत्री के दबाव में आकर एच०पी०एस०सी० की नौकरियों में धांधली करते थे। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि एच०पी०एस०सी० के पूर्व और जो मौजूदा चेयरमैन और मैंबर हैं जिन्होंने अनियमितताएं की हैं उनके खिलाफ जांच करायेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि जो भी अनियमितताएं होंगी, जो भी गलत काम हुआ होगा, जो भी गड़बड़ी पाई जायेगी या भ्रष्टाचार का जो भी मामला पाया जायेगा उसकी हमारी सरकार जांच करायेगी और दोषियों को सजा दी जायेगी। इस तरह की बात कोई भी सदस्य या हरियाणा का कोई भी व्यक्ति सरकार के नोटिस में लायेगा उसकी एक सीमित अवधि के अंदर जांच करायेंगे और कोई कितने भी बड़े पद पर आसीन रहा हो या इस समय हो, हरियाणा की सरकार, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि how ever high you may be, the law is above you. The law will take its own course.

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि ये मैंबर साहिबान के खिलाफ तो कार्यवाही करायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी जिनको नाजायज तरीके से नौकरियां दी गई हैं। मैं मंत्री जी के नोटिस में एक बात लाना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में कमीशन ने एक ऐसे व्यक्ति को एच०सी०एस० की नौकरी दे दी जिसके ऊपर पांच मुकदमे कार चोरी के चल रहे हों। इसके अतिरिक्त मैं एक बात मंत्री जी के ध्यान में और लाना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी और गुड़गांव जिले के किसी भी कैंडीडेट का एच०सी०एस० में नम्बर नहीं आया लेकिन आई०ए०एस० में आ गया। एच०सी०एस० में इसलिए नहीं आया क्योंकि इनके पास चौटाला साहब को देने के लिए 70-70 लाख रुपये नहीं थे। (विघ्न)

Mr. Speaker: Please take your seat. Hon'ble Minister is replying.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां क्षेत्र के आधार पर नहीं होती। क्योंकि लोक सेवा आयोग की नियुक्तियां कानून और संविधान की परिधि में मैरिट के आधार पर होती हैं। मेरे माननीय साथी ने कई मामलों की चर्चा की है लेकिन किसी पर्टिकुलर मामले की चर्चा नहीं की। कई ऐसे मामले हैं जो इस समय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पैंडिंग हैं। फिर भी कोई ऐसा मामला जो इस समय सब ज्यूडिश नहीं है तो माननीय साथी लिखकर दें, मैंने पहले भी कहा है यह एक ही सवाल है जिसे बार-बार दोहराया जा रहा है इस बारे में हम कार्यवाही करायेंगे। (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम सबको मालूम है और पूरी हरियाणा की जनता को मालूम है कि चौटाला साहब की सरकार के समय में जितने भी एप्वाईंटमैंट हुई थीं उन सब में गड़बड़ी हुई है। कमीशन के जो मैंबर लगे हुए हैं वे सब उनके वर्कर हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि उन सब मैंबरों को हटा दिया जाये क्योंकि चार-पांच सदस्यों को छोड़कर सारा सदन एकमत है और साथ ही साथ उनके खिलाफ इन्क्वायरी भी होनी चाहिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उनकी संख्या 9 से कम करके 5 कर दी। शायद 9 में से कुछ सदस्य भी यही चाहते हैं । इसके अतिरिक्त माननीय साथी की भावनाओं पर आदर प्रकट करते हुए मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग को भंग करना इस सदन के अधिकार क्षेत्र की परिधि में नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी : ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि क्या योग्यता के विषय में वे इस सदन में अमैंडमैंट के लिए कोई रैजोल्यूशन लेकर आएंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्या ने योग्यता के बारे में और प्रस्ताव लाने के बारे में कहा है। उनका यह सुझाव बहुत ही अच्छा है और सरकार को कम से कम इस प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं है। माननीय सदस्यता इस बारे में प्रस्ताव का मसौदा लेकर आएं तो हाउस उस पर विचार कर लेगा।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, हमारे गाबा साहब जी ने जो बताया था उसी के बारे में मैं भी यह कहना चाहता था कि जो नियुक्तियां हुई थीं उसमें हमारे जो माननीय एस०डी०एम० साहब हैं उनकी भी नियुक्ति हुई है। लगभग एक हफ्ता पहले इस बारे में पेपर में काफी कुछ आया था। कम से कम 10 गांवों की जमीन जो कि एस०डी०एम० की पावर में आती है वह जमीन उन्होंने अपने आदमियों को अलॉट कर दी। उसके बाद उस जमीन की 3-3 बार रजिस्ट्री हो चुकी है। मेरे ख्याल में वह कम से कम 200 करोड़ रुपये का घपला है। इस के बारे में करीब एक हफ्ता पहले पेपर में आया था।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन को रिटेल करता है ?

श्री सुखबीर सिंह (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल उसी में आता है, एच०सी०एस० की जो भर्ती हुई है मैं उसके बारे में ही कह रहा था। जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलैक्ट किए हैं उसी बात को मैं यहां पर बता रहा था और उसी मामले को आगे बढ़ा रहा था। हमारे जो एस०डी०एम० साहब हैं जिनकी सिलैक्शन इसी भर्ती में हुई थी उन्हीं के कारण यह सारा मामला हुआ है। करीब एक हफ्ता पहले यह पेपर में आया था कि कम से कम 200 करोड़ रुपये का घपला है। 70-70 एकड़ जमीन किसी को अलॉट कर दी और उसने वह जमीन आगे बेच दी और फिर जिसने वह जमीन खरीदी थी उसने भी वह जमीन आगे बेच दी। इस प्रकार वह जमीन तीन-तीन बार बेच कर खत्म कर दी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय, से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस पर कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने किसी व्यक्ति विशेष की बात कही है जिसकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की गई है। शायद माननीय गाबा साहब ने भी उसी व्यक्ति की चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दोनों सम्मानित सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे आज ही इस बारे में लिख कर मुझे दे दें, हम सीमित अवधि के अन्दर इस विषय पर जांच करवाएंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एच०पी०एस०सी० ने पिछली सरकार के राज में सुप्रीम कोर्ट को धता बताकर एच०सी०एस० अधिकारियों का चयन किया जिसमें उस वक्त के चीफ सैक्रेटरी ने गलत ऐफिडेविट दिया कि जो नौकरियां निकाली गई हैं और जो नियुक्तियां की गई हैं जिन पोस्टों पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ था उनको हम नहीं भर रहे हैं। हमारे पास जो दूसरी वेकैंसीज हैं उनको हम भर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने वह पोस्टें एडवर्टाइजमैंट नहीं की और एच०पी०एस०सी० ने अपने परिव्यू से बाहर जा कर बिना एडवर्टाइजमैंट किए एच०सी०एस० अधिकारियों का सिलेक्शन कर नियुक्तियां की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को कानूनी तौर पर हटाने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ? इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चीफ सैक्रेटरी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में गलत ऐफिडेविट दिया था क्या सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई पहल करेगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्यों को मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तथा सरकार की यह नीति रही है कि डेट ऑफ ऐग्जामिनेशन तक जितनी भी पोस्ट्स वैकेंट थी चाहे ये ऐडवर्टाईज्ड पोस्ट्स हों और चाहे और

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

ज्यादा पोस्टें हो it is by and large followed in letter and spirit. इन सब पोस्टों के बारे में आपके समक्ष अगर कोई ऐसा केस है तो कृपया मुझे फैक्ट्स दे दीजिए उस पर जांच करवाएंगे और जो भी व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा अमर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सारी स्टेट और सारा हाउस इस बात को जानता है कि कमीशन द्वारा नियुक्तियां गैर कानूनी हुई हैं और यह नियुक्तियां करने वाले लोग भ्रष्ट थे। उन लोगों ने बिना कानून निर्दोष लोगों को जेलों में डाला । क्या यह सरकार उन लोगों के खिलाफ सुओ मोटो ऐक्शन लेने में समर्थ नहीं है। इस मामले में सारा हाउस सरकार के साथ है तो सरकार इस मामले में अपने आप सुओ मोटो ऐक्शन क्यों नहीं ले लेती। हर चीज में क्यों लिख-लिख कर मांगा जाता है। सब लोग इस बात को जानते हैं और सारी दुनिया इससे वाकिफ है, फिर भी इसमें सुओ मोटो ऐक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वैक्यूम में, खाली हवा के अन्दर कोई जांच सम्भव नहीं है। बड़े से बड़े दोषी और सबसे बड़े चोर को भी न्याय प्रणाली के अन्दर ही सजा मिलेगी। माननीय सदस्य की जानकारी में अगर कोई मामला है तो उसको लिख कर देने में क्या दिक्कत है। ये लिख कर दें हम जांच करेंगे और सीमित समय के अन्दर जांच करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। लिख कर देने में घबराहट किस चीज की है। माननीय सदस्य आगे आएं, लिख कर दें सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी, सरकार का यह निश्चय है।

Outstanding amount of Industrial Loan

*11. **Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Minister for Industries be pleased to State—

(a) the Tehsilwise total amount of industrial loan outstanding against industrialists in the State as on 31st March, 2005;

(b) the steps so far taken or proposed to be taken to recover the said amount of loan ; and

(c) the Tehsilwise total amount of outstanding loan for which loanees are not traceable ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Information is placed on the table of the house.

Information

(a) Tehsilwise information is not maintained. However, districtwise outstanding amount from the industrialists as on 31st March, 2005

is Rs. 651 crores and 85 lacs. Districtwise details are given below :—

Districtwise Outstanding Loan as on 31st March, 2005

(Amount in lacs)

Sr. No.	Name of District	Industries Deptt.	HSIDC	HKVIB	HFC
1.	Ambala	18.52	1569.08	48.35	1001.52
2.	Bhiwani	22.82	1581.74	111.38	2586.96
3.	Jhajjar	35.53	1049.27	—	2885.02
4.	Faridabad	23.15	5858.97	60.98	2423.80
5.	Fatehabad	75.99	—	—	212.55
6.	Gurgaon	68.44	8094.84	37.15	5637.97
7.	Hisar	107.56	1257.39	84.21	3119.04
8.	Jind	29.32	274.64	78.40	1380.00
9.	Kaithal	50.05	—	37.79	134.47
10.	Karnal	67.77	67.12	66.69	1019.81
11.	Kurukshetra	14.86	266.74	52.03	298.79
12.	Narnaul	38.36	—	49.03	149.00
13.	Panchkula	65.60	1742.05	33.81	1371.47
14.	Panipat	72.96	903.74	63.72	1842.58
15.	Rohtak	19.21	1508.35	89.59	1671.69
16.	Rewari	25.14	3220.79	22.70	2107.00
17.	Sirsa	38.52	658.52	41.97	879.68
18.	Sonepat	46.27	2247.29	36.48	2738.73
19.	Yamuna Nagar	46.88	694.66	38.53	799.46
	Total	**966.85**	**31004.59**	**954.00**	**32259.54**
	Grand Total	**65184.98**			

(b) Apart from the normal recovery following steps have been taken/ proposed to be taken to recover the said amount of loan.

(i) Launching of recovery campaigns.

(ii) Recover loans as Arrears of Land Revenue.

(iii) Taking over of Primary & Collateral Securities.

(iv) Liquidation of Mortgaged Properties.

(v) One-time-settlement Scheme.

(vi) Compromise settlement of Non-Preforming Assets.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

(c) Tehsilwise Information is not maintained. However, districtwise outstanding loan for which the loanees are not traceable is Rs. Fifteeen crore Eighty Six lac Seventy Six thousand. The details are given below :—

(Amount in lacs)

Sr. No	Name of District	Industries Deptt.	HSIDC	HKVIB	HFC
1.	Ambala	19.32	—	—	39.58
2.	Bhiwani	24.92	—	—	19.80
3.	Jhajjar	7.42	—	—	145.85
4.	Faridabad	1.21	—	—	40.77
5.	Fatehabad	1.83	—	—	0.00
6.	Gurgaon	14.20	—	—	129.23
7.	Hisar	11.87	—	—	60.72
8.	Jind	-	—	—	29.09
9.	Kaithal	17.00	—	—	16.19
10.	Karnal	26.47	—	—	22.37
11.	Kurukshetra	1.93	—	—	0.00
12.	Narnaul	15.13	—	—	0.99
13.	Panchkula	2.50	94.60	—	43.40
14.	Panipat	25.05	—	—	290.09
15.	Rohtak	12.15	41.92	—	168.04
16.	Rewari	1.67	—	—	43.72
17.	Sirsa	6.93	—	—	5.37
18.	Sonepat	16.98	98.12	—	23.55
19.	Yamuna Nagar	31.32	—	—	35.86
	Total	**237.90**	**234.24**	—	**1114.62**
	Grand Total	**1586.76**			

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है उसके मुताबिक आउटस्टैंडिंग लोन 651 करोड़ 85 लाख रुपए हैं जबकि हमारे बजट का टोटल घाटा 51 करोड़ रुपये है। यह आउटस्टैंडिंग लोन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो लोन एडवांस दिखाया गया है और जो आउटस्टैडिंग लोन दिखाया गया है इसमें सबसिडी भी है या सबसिडी इससे अलग है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हरियाणा राज्य में सबसिडी जो है वह स्टेट ऐड इंडस्ट्री ऐक्ट, 1935 में और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सैन्टर स्कीम थी जो कि 1992-93 में बन्द हो गई थी। स्पीकर सर, इन्हीं दो को सबसिडी हैड के अन्दर सबसिडी दी जाती थी। स्पीकर सर, इस बारे में स्पैसिफिक प्रश्न माननीय साथी ने पूछा नहीं था इसलिए सबसिडी का ब्रेकअप डिपार्टमैंट द्वारा माननीय सदस्य को भेज दिया जाएगा।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : स्पीकर सर, सवाल के पार्ट बी में मैंने पूछा है कि—

> "The steps so far taken or proposed to be taken to recover the said amount."

इसका जवाब बहुत ही वेग है। जो जनरल तरीके लोन की रिकवरी के हैं वे इसमें लिख दिये गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इतना लोन जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से क्या कुछ लोनी ऐसे भी हैं जो अनट्रेसेबल हैं। इस बारे में सरकार का जवाब क्लीयर नहीं है कि वे कौन कौन लोग हैं ? क्या उन लोगों ने सबसिडी खाने के लिए ही लोन लिया था या गुड इन्टैंशन से इंडस्ट्री एस्टैबलिश करना चाहते थे। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि चौटाला साहब के राज में कई आफिसर्ज और मंत्री विदेशों में गए थे और उसकी वजह से स्टेट एक्सचैकर पर बड़ा भारी बोझ पड़ा था। वे यह कह कर विदेशों में गए थे कि हम हरियाणा में इंडस्ट्रीज को इन्वाईट करने के लिए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बाहर से हरियाणा में इंडस्ट्रीज आई ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं, जिन्होंने लोन लिया था और जो अब अनट्रेसेबल हैं उनके गारन्टर की क्या पोजीशन है। उनकी मूवबेल प्रापर्टी तो अनट्रेसेबल नहीं हो सकती है। इस बारे में सरकार की क्या पोसिली है और सरकार उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लेने जा रही है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 651 करोड़ रुपये का लोन डिफाल्टिंग अमाउन्ट है और इस बारे में स्पीकर सर आप भी जानते हैं और सारा हाउस भी जानता है कि एक्सटैंशन ऑफ लोन जो इंडस्ट्री का है वह एक कन्टीन्यू प्रक्रिया का हिस्सा है। बड़े उद्योग पति और छोटे उद्योगपति लोन लेते हैं और वे वापस भी देते हैं। जो ब्रेकअप इन्होंने मांगा है वह हमारे पास उपलब्ध है। इस बारे में माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि 3 बड़ी ऐजेन्सीज हैं जो लोन देती हैं। नम्बर एक पर हरियाणा फाईनैंशियल कारपोरेशन है, इसका 32259.54 करोड़ रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है और इसमें से 11 करोड़ 15 लाख रुपए का लोन अनट्रेसेबल है। इसी प्रकार एच०एस०आई०डी०सी० व दूसरी एजैंसीज हैं, जो लोन देती है, इनका आउटस्टैण्डिंग लोन 31004.59 करोड़ है और इसमें से अनट्रेसेबल 2 करोड़ 34 लाख रुपये हैं। इसके अलावा हरियाणा खादी और विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड पहले लोन देती थी, अब नहीं देती है। अब वह लोन की बजाए मार्जिन मनी असिस्टैंस देती है और उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका आउटस्टैण्डिंग अमाऊंट हो।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनके पास ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने लोन लेकर इंडस्ट्रियल यूनिटस लगाई ही नहीं और वे लोन खा गए हैं। अगर इनके पास उन लोगों के नाम हैं तो ये उनके नाम बताने का कष्ट करें और यह भी बताएं कि उन लोगों से वसूली हुई भी है या नहीं हुई है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह एक सैपरेट क्वैश्चन है। फिर भी अगर कोई स्पैसिफिक इन्सटान्स माननीय सदस्य के नोटिस में है तो वे हमें बताएं। उसका जबाव उनको लिखवाकर भिजवा देंगे।

Construction of Community Centre in Narnaund

***62. Shri Ram Kumar Gautam:** Will the Minister for Industries be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Community Centre in Narnaund City in district Hisar ?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : A Community Centre at Narnaud City, District Hisar has already been constructed by the Municipal Committee, Narnaund.

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर साहब, इस समय कोई कम्यूनिटी सैंटर नारनौंद में नहीं है। अगर कोई बना होगा तो हो सकता है कि वह गिर गया हो। मुझे तो इस बारे में पता नहीं है। मेरे हल्के के जितने भी गांवों के लोग हैं सबने इस बारे में डिमांड की है कि आप सरकार से कहकर वहां पर कम्यूनिटी सैंटर बनवाएं। इसलिए ही मैंने आपके माध्यम से हाउस के सामने और सरकार के सामने यह डिमांड रखी है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 5 लाख 99 हजार रुपये की लागत से यह कम्यूनिटी सैंटर वहां पर बना था लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि जो इनके पहले प्रैडीसैसर थे या जो अब भी इनके पड़ौसी हैं उन्होंने उस कम्यूनिटी सैंटर के अंदर नगरपालिका का दफ्तर खुलवा दिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिये हैं और मैं भी सदन को आश्वत भी करना चाहता हूं कि 6 महीने के अंदर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार वहां से वह नगरपालिका का दफ्तर शिफ्ट करवाकर कम्यूनिटी सैंटर खोल देगी।

Mr. Speaker : Are you satisfied Gautam Ji ?

Shri Ram Kumar Gautam : Yes, Sir.

Setting up of Large Scale Industries in Mahendergarh District

***33. Shri Naresh Yadav :** Will the Minister for Industries be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Large Scale Industries in district Mahendergarh; if so, the details thereof?

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): Speaker Sir, at present, there is no such proposal under consideration of State Government to set up Large Scale Industries in Mahindergarh District. However, if any proposal comes up, State Government will consider it on merit.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी किसी भी सरकार ने जिला महेन्द्रगढ़ जिसको इस सरकार ने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, में उद्योग लगाने का प्रयास नहीं किया। जैसे यहां पर समान पानी वितरण की बात की जा रही है तो उसी तर्ज पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और

मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे इस महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को फारवर्ड करने के लिए क्या कोई स्पेशल रियायत देकर इंडस्ट्रलिस्टस को वहां लाने का प्रयास किया जाएगा या वहां पर किसी मल्टी नेशनल कम्पनी को अपनी यूनिट खोलने के लिए तैयार करवाया जाएगा और क्या कोई स्पेशल सबसिडी देकर जिला महेन्द्रगढ़ में इंडस्ट्रियल यूनिट लगायी जाएगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने हरियाणा में कई ऐसे इलाकों को बैकवर्ड घोषित किया हुआ है। माननीय सदस्य का जिला भी इन्हीं बैकवर्ड इलाकों में शामिल है। सरकार इस बात के लिए चिंतित भी है और गंभीर भी है कि उद्योग प्रांत के सभी हिस्सों में हों और खासकर उन हिस्सों में जरूर हों, जिनमें उद्योग धंधों की कमी है। हम माननीय सदस्य की भावना का सम्मान करते हैं और उसके अंदर शरीक भी हैं। जब भी कोई इस तरह का प्रपोजल आएगा तो वहां पर सरकार इन्सैंटिव देकर उद्योग लगाने में पीछे नहीं हटेगी।

श्री आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे सदन को भी सूचित करें कि कितने लघु उद्योग हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद पड़े हैं और उनको दोबारा से शुरू करने का क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, यह एक सैपरेट क्वैश्चन है। माननीय सदस्य अगर इस बारे में लिखकर भेज देंगे तो मंत्रालय इसका जबाव उनको लिखवाकर भिजवा देगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि लघु उद्योगों की प्रमोशन के लिए आगे जो लघु उद्योग खुलेंगे उसके लिए सरकार ने स्पैशल कदम उठाए हैं और इन सारे कदमों का खुलासा हमने अपनी नयी औद्योगिक नीति के अंदर किया भी है।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जैसा कि बता रहे हैं कि प्रदेश में जिला महेन्द्रगढ़ को 88 में से एक बैकवर्ड घोषित किया गया है जब बैकवर्ड घोषित कर ही दिया गया है तो सरकार ने वहां के लिए कोई स्पैशल स्कीम तैयार की होगी। यदि वहां कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने की सरकार ने योजना बनाई है तो कृपा मंत्री महोदय विवरण दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पहले ही कहा है कि इस बारे में भारत सरकार के नार्म्ज हैं। वर्ष 1999 की नीति के तहत यदि 1 करोड़ रुपये के निवेश की फैक्ट्री लगेगी तो उसे मीडियम माना जाएगा और उसके बाद लार्ज स्केल इण्डस्ट्री में आएगी। सरकार ने अपनी इण्डस्ट्रीयल पोलिसी में जो छोटे-छोटे उद्योग हमारे इन सब जिलों के अंदर लगते हैं उनका तफसील से उसमें खुलासा किया है। मैं आपके माध्यम से 4-5 जो विशेष कदम इस बारे में उठाए गए हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा । स्पीकर सर, मौजूदा सरकार ने सैंटर फॉर कंपीटीटिवनैस का गठन करने का फैसला किया है। यह इसलिए किया है कि पहले जो नयी टैक्नोलौजी है उनका छोटे उद्योग फायदा नहीं उठा पाते थे। सैंटर फॉर कंपीटीटिवनैस होगा तो सभी उद्योग उसका फायदा उठा पाएंगे। दूसरा मौडर्नाइजेशन और टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन उसके लिए विशेष बैनीफिट जो स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, जो छोटे उद्योग हैं उनको देने का फैसला किया गया है ताकि डब्ल्यू०टी०ओ० रिजीम उसका फायदा उठा सकें। क्वालिटी अपग्रेडेशन स्कीम सरकार ने बनाई है जिसमें जितना खर्च भी होगा आर०एण्ड०डी० पर, क्वालिटी अपग्रेडेशन पर, ऐक्वीजिशन ऑफ क्वालिटी मास पर, कंसलटैंसी फीस पर, आई०एस०ओ० 9001-2000

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

सर्टिफिकेशन और आई०एस०ओ० 14001 सर्टिफिकेशन में तो उसके लिए सरकार शेयर करेगी। एक और यूनिक स्कीम लघु उद्योगों के लिए पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन की बनाई है क्योंकि डब्ल्यू०टी०ओ० रिजीम के बाद आज के दिन यह एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हमने यह फैसला किया है कि पचास प्रतिशत तक का जो खर्च पेटेन्ट लेने के लिए होगा पांच लाख तक की सीमा तक उसको सरकार वहन करेगी। इसके अलावा हमने क्लस्टर डिवैल्पमैंट स्कीम बनाई है। हमारी नयी टैक्नोलॉजी के अंदर इसमें हमने तीन क्लस्टर्स इमीडियेटली आइडैंटीफाई किए हैं। एक है टैक्सटाइल क्लस्टर इन पानीपत और दूसरा लाइट इंजीनियरिंग गुड्स क्लस्टर फरीदाबाद। तीसरा ऑटो पार्ट्स क्लस्टर गुड़गांव में है। स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं कि विशेष उद्योग इन सारे क्षेत्रों के अंदर आए हैं परन्तु अकेले-अकेले लघु उद्योग सरकार की नीतियों और तकनीक का फायदा नहीं उठा सकते थे इसलिए हमने क्लस्टर डिवैल्पमैंट करने का फैसला किया है ताकि सारी सुविधायें एक ही इलाके के अंदर दे सकें। इसके अलावा हमने यह भी फैसला किया है कि क्लस्टर उद्योग जो होंगे, उनको सरकार अपग्रेड करेगी। जैसे साइंटीफिक इंस्ट्रूमैंट कलस्टर अम्बाला में, मैटल इण्डस्ट्री क्लस्टर जगाधरी में, ऐग्रीकल्चर इम्पलीमैंट क्लस्टर करनाल में, फार्मास्युटिकल क्लस्टर सोनीपत में और एक ऐग्रो कैमिकल एंड इंडस्ट्रीज क्लस्टर बहादुरगढ़ में अपग्रेड करने का फैसला लिया गया है।

Dr. Raghubir Singh Kadian : Speaker Sir, through you, I would like to know that what steps are proposed to be taken by the State Government for creating the investor friendly environment and the hassle free cooperation of the industrial units as compared to the Lok Dal regime.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, कई क्रांतिकारी और पाथ ब्रेकिंग निर्णय इस सरकार ने लिए हैं। सबसे पहला हमने निर्णय लिया है इकोनोमिक हब्स की क्रिएशन का। कुंडली, मानेसर और पलवल में ऐक्सप्रैस हाई वे जो बनेगा उसके चारों तरफ इकोनोमिक हब्स बनाने का सरकार ने फैसला किया है और इसकी व्याख्या हमने इण्डस्ट्रियल पोलिसी के अंदर की है। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि गढ़ी हरसरू, गुड़गांव में एन०एच०10, एन०एच० 8 और एन०एच० 2 पर स्पैशल इकोनोमिक जोन का गठन किया जाएगा। इसके साथ चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने यह फैसला किया है कि आई०एम०टी० मानेसर की तर्ज पर दो नये इण्डस्ट्रियल मॉडल टाउंस का भी गठन किया जायेगा। एक मैगा पैट्रो कैमिकल्ज हब्स जिसमें कई हजार करोड़ रुपये की इण्डस्ट्रीज आयेंगी उसके भी निर्माण का मसौदा हमने तैयार किया है। स्पीकर सर, इसके अलावा सरकार ने 3 पार्क बनाने का फैसला किया है और 4 फूड पार्कस; एक राई में, एक साहा में, एक नरवाना में और एक डबवाली में । फूड प्रोसैसिंग हब्स आपके जिले रोहतक में बनाया जायेगा। एक मैगा फूड पार्क बनाने के लिए हमने भारत सरकार से बात की है और इस बारे में एक प्रोजैक्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा है अगर यह पास होकर वापस आ जायेगा तो इससे बहुत लाभ हरियाणा को पहुंचेगा। इसके इलावा स्पीकर सर हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हरियाणा में नैशनल इंस्टीच्यूट फॉर फूड टैक्नालाजी मैनेजमेंट खोला जाये जो अपनी तरह का एक यूनिक इंस्टीच्यूट होगा। इसके इलावा हमने जैम और ज्वैलरी पार्टस का मसौदा उद्योग विहार गुड़गांव में खोलने का फैसला किया है। 2 अपरैरल पार्क भी खोले जाएंगे। कपड़ा उद्योग के अन्दर हरियाणा ने बहुत तरक्की की है इनमें से एक बहरी

सोनीपत में और दूसरा गुड़गांव में खोला जायेगा। इसी प्रकार से फुट वीयर और लैदर गारमैन्ट्स: क्योंकि करनाल से जुड़ा हैं इसलिए यह करनाल में सरकार खोलेगी। इसी प्रकार से फ्री-इन्टरप्राइजिज जोन खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा प्राईवेट सैक्टर की इन्वैस्टमैंट है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट में उसको सरकार प्रमोट करेगी। इस प्रकार के कई कारगर कदम उद्योग लगाने के बारे में इस मौजूदा सरकार ने उठाये हैं।

श्री शादीलाल बतरा : स्पीकर सर, स्टेट ने रीसैंटली इण्डस्ट्रियल पोलिसी अनाउंस की है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इसके तहत कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में भी कहा है कि ऐसी उम्मीद है कि हमें इस इंडस्ट्रियल पोलिसी से दो लाख करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट तकरीबन आयेगी और अगले दस वर्षों के अन्दर हमें यह उम्मीद है कि दस लाख से अधिक व्यक्तियों को इसके माध्यम से और इसके क्रियान्वयन के बाद रोजगार मुहैया करवा सकेंगे।

Mrs. Kiran Chaudhary : Mr. Speaker Sir, I would like to ask the Hon'ble Minister that what is the criteria for establishing these hubs, which he has just talked about. Whether there is any proposal that these hubs will be created in Bhiwani, which is a backward District.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्या ने जो इकोनोमिक हब्स के बारे में प्रश्न पूछा है मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये इकोनोमिक हब्स पलवल, कुण्डली, मानेसर एक्सप्रैस हाई-वे पर हैं जो एक तरह से दिल्ली के कोरीडोर एक्सप्रैस-वे हैं इसलिए इन दोनों-तीनों तरफ यह एक्सप्रैस हाई-वे बनाये जायेंगे। जहां तक भिवानी का प्रश्न है, भिवानी के अन्दर बैकवर्ड एरिया है और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि जो उद्योग धन्धे हैं वे प्रदेश के हर कोने में जायें। जहां तक इकोनोमिक हब्स का सवाल है यह हाउस जानता है कि वह एरिया ग्रोथ एरिया है, वह दिल्ली के चारों तरफ है इसलिए वहां पर एक्सप्रैस हाईवे का निर्माण किया जायेगा और इन तीनों-चारों जगह इकोनोमिक हब्स बनेंगे।

प्रो० छतरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा एग्रीकल्चर सैक्टर में कृषि प्रधान प्रान्त है और यहां की 80 प्रतिशत पापुलेशन खेती पर निर्भर है। यहां पर बिजली और पानी की कमी है। पापुलेशन के बढ़ने से सेचुरेशन ऑफ लैण्ड भी हैं लैण्ड होल्डिंग कम होने की वजह से जो अनइम्पलौयमैंट की प्रोब्लम है वह किसानों के बेटों के लिए ज्यादा है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन है कि जो किसान के प्रोडैक्टस हैं, जैसे फूड ग्रेन्स, फ्रुट, वेजीटेबल की जो फरदर प्रोसैसिंग यूनिट स्किल उनको देने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए या एजुकेशन देने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है और फर्दर यूनिट्स को चलाने के लिए सरकार कोई इन्सैंटिव देती है या नहीं क्या इस स्कीम पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण का प्रश्न है, जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रैपिड इंडस्ट्रीलाइजेशन हो और तेजी से औद्योगिकीकरण हो, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमने विशेष प्रोत्साहन खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड और उसके द्वारा लगने वाले उद्योगों को देने का फैसला किया है। इसके

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

इलावा हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना लाने का फैसला किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धे लगेंगे और उन उद्योगों में ग्रामीण नौजवानों को प्राथमिकता से रोजगार भी दिया जा सकेगा। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों में फूड पार्कस के बारे में था। उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। हमने स्पैसीफिक फूड पार्कस आइडैंटीफाई किए हैं। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे, चाहे नरवाना में हो, चाहे डबवाली में हो, चाहे साहा में हो और चाहे राई में हो। राई केवल दिल्ली के नजदीक है, बाकी के तीनों क्षेत्र जहां फूड पार्कस प्रपोज किए गए हैं, ग्रामीण आंचल का हिस्सा हैं। इसके अलावा फूड प्रोसैसिंग हब्स रोहतक में है और इंस्टीच्यूट की भी बात इन्होंने की। अध्यक्ष महोदय मैं इसके बारे में पहले ही आपको व सदन को बता चुका हूं। नैशनल इंस्टीच्यूट आफ फूड टैक्नोलोजी मैनेजमैंट जो है, उसमें हमारा यह प्रयास है कि भारत सरकार उसको जल्दी से जल्दी हरियाणा के अन्दर लेकर आए।

श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया : अध्यक्ष महोदय, बावल जिला रिवाड़ी में है और हरियाणा के अन्तिम छोर में बसा हुआ है। वह हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा ग्रोथ सैन्टर है जिसमें YKK और Asia India जैसी बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं। हमारा एक गांव सुठानी है जिसमें हमने उस समय एनसलैरी यूनिट लगाने का प्रावधान किया गया था। उसकी बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई थी और अब वह बिल्डिंग बेकार हो रही है क्या वहां पर एनसलैरी यूनिट लगेगी ताकि उस एरिया के बच्चों को रोजगार मिल सके और साधनहीन होने के नाते उनकी एनसलैरी यूनिट के लगने से आर्थिक स्थिति ठीक हो सकेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की भावना से सहमत हूं। पिछले 6 वर्ष से इस प्रांत में एक ऐसी सरकार दिखी जिसमें एक सुनियोजित तरीके से उद्योगों को हरियाणा से भगाया गया, उनका पलायन कराया गया और उनसे जबरन वसूली की गई। जहां तक एनसलैरी यूनिट का सवाल है यह सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है; जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया था कि अगले 10 वर्षों में प्रांत के अन्दर नई औद्योगिक नीति से 2 लाख करोड रुपये की इन्वैस्टमैंट आने की हमें उम्मीद है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी उद्योगपति सभी कार्य खुद नहीं कर सकता, जब भी इन्वैस्टमैंट आएगा तो उनकी आंउटसोर्सिंग आउट को हम प्राथमिकता देंगे और यह प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मौका उसमें मूलभूत हरियाणा के नागरिकों को ही मिले।

Mrs. Kiran Chaudhary : Hon'ble Speaker Sir, this is just in continuation of my earlier question, which the Hon'ble Minister has replied. He has spoken about the cluster development. I would like to know whether the cluster development is feasible in Bhiwani district or not ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदस्या को पहले ही बताया है कि हमने 3 नए कलस्टर डिवैल्पमैंट के लिए और 4 जो एग्जस्टिंग हैं उनको अपग्रेड करने के लिए यानि ये 7 कलस्टर आइडैंटीफाई किए हैं। ये फैक्ट्रियां नहीं हैं। हमने वे इलाके चुने हैं जहां किसी विशेष धन्धे के लोग पहले से ही कार्य करके प्रांत की तरक्की में भागीदार थे। जैसे जगाधरी बर्तन उद्योग के लिए मशहूर है, करनाल सदैव से चमड़ा उद्योग के लिए चाहे उसमें जूते या चप्पल के लिए हों, चाहे लिबर्टी हो, चाहे दूसरे उद्योग हो, पानीपत कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है और अम्बाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमैंट से जुड़ा हुआ है। हमारा यह प्रयास है कि ये छोटे उद्योग जो

यहां लगे हैं, जो बन्द होने की कगार पर पहुंच गए थे या पिछले 6 सालों में अधिकतर बन्द हो गए थे, क्योंकि न ये कम्पीटीटिव थे और न यहां फ्री एनवायर्न था। पहले इनको प्रोत्साहित करके उनको चालू किया जाएगा और समय आने पर माननीय सदस्या की बात पर भी विचार किया जाएगा।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बता दिया है कि जिला महेन्द्रगढ़ बैकवर्ड है और उसे बैकवर्ड ही रखा जायेगा, क्योंकि जिला महेन्द्रगढ़ में किसी प्रकार की इण्डस्ट्री नहीं लगाई जा रही। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी-नारनौल-सींघाना रोड और भिवानी-नारनौल-जयपुर रोड बहुत बड़े रोड हैं इन पर सरकार को कोई न कोई इण्डस्ट्री जरूर लगानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब तक हमारे इलाके का इण्डस्ट्रीयल डिवैल्पमैंट नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। इस सरकार ने वहां पर किसी तरह की इण्डस्ट्री लगाने का प्रावधान नहीं किया और न ही पिछली सरकार वहां इण्डस्ट्री लगाने का प्रावधान छोड़कर गई। इसलिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि वहां इण्डस्ट्री लगाने का प्रावधान किया जाये और जब तक वहां अलग से इण्डस्ट्री न लगे तब तक जो इण्डस्ट्रीज गुड़गांव से लेकर रिवाड़ी तक और गुड़गांव से लेकर शाहजहां तक लगी हुई हैं जिनमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं उनमें हमारे इलाके के बेरोजगार युवकों को 80 प्रतिशत आरक्षण देकर नौकरियां देने का प्रावधान किया जाये। (विघ्न)

Mr. Speaker : This is the problem that I am facing with you, Yadav ji. (Interruptions). Please take your seat. You are delivering the speech. I told you Yesterday also that this is not the way to put the question. Please put the question.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार ने हमारे इलाके के बेरोजगार युवकों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए। जैसा बहन शकुन्तला भगवाड़िया जी ने बताया कि जो वाई०के०के०, हीरो होण्डा, होण्डा सिटी आदि कंपनियां गुड़गांव, रिवाड़ी, शाहजहांपुर आदि जगहों पर लगी हुई हैं, उनमें नौकरी दिलाने का प्रावधान किया जाये तथा जल्दी से जल्दी महेन्द्रगढ़ जिले में कोई बड़ी इण्डस्ट्री लगाने का सरकार प्रावधान करे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने दो सवाल किए हैं। एक सवाल तो भावावेश में आकर किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि दक्षिणी हरियाणा हर क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता पर है। जो एरिया पिछड़ा हुआ है उस एरिया में विशेषतौर से इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार कटिबद्ध है। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि अब उद्योग धन्धों का नया युग आ गया है। अब ये सरकार द्वारा संचालित नहीं होते बल्कि प्राईवेट कंपनीज उद्योग-धन्धे ज्यादा चलाती हैं। सरकार तो सिर्फ उनके लिए माहौल तैयार करती है। चाहे ला एंड आर्डर का मामला हो, इनसैंटिव का मामला हो या दूसरी कोई और चीजें हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का दायित्व उद्योग धंधे लगाने के लिए प्राईवेट कंपनीज को उचित वातावरण देना है। अध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ जिले को बैकवर्ड घोषित किया गया है। वहां पर उद्योग लगाने वालों को हमारी सरकार विशेष इनसैंटिव देगी। मेरे साथी के भी कई मित्र पड़ोसी राज्यों में होंगे उनको वे यहां उद्योग लगाने के लिए कहें, हमारी सरकार उनको पूरा प्रोत्साहन और प्राथमिकता देगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने की बात सरकार ने इण्डस्ट्रीयल पोलिसी में कही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो पैडी ग्रोविंग एरियाज जैसे कैथल, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, पेहवा, गुहला, चीका, पुण्डरी आदि हैं यहां पर दो-तीन राईस शैलर इण्डस्ट्री बंद होने के कगार पर हैं और यह सब पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। क्या मौजूदा सरकार इन ऐग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको इम्प्रैस करने के लिएं कोई स्पेशल इनसैंटिव स्कीम बनायेगी ताकि इन्हें बंद होने से रोका जा सके ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, राईस शैलर्ज की ऐसोसिएशन अपनी समस्याओं के बारे में सरकार को बताये या उनके प्रतिनिधि अपनी समस्याएं हमें लिखकर दें, उनकी जो भी समस्याएं होंगी हम उन पर अवश्य विचार करेंगे। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का यह फैसला है कि एक भी इण्डस्ट्री अब हरियाणा प्रदेश से न तो पलायन करेगी और न बंद होगी।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : स्पीकर सर, माननीय मन्त्री महोदय ने फूड जोन की बात कही है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना भी चाहूंगा कि करनाल और पानीपत में भी सब्जी का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है जैसे कि माननीय श्री सुरजेवाला जी ने अभी कहा कि चावल की जो ट्रेड है उसमें बहुत जरूरी है कि आप कोई एक्सपोर्ट जोन बनाएं। चावल के ट्रेड में बहुत से ऐसे उद्योगपति और हैं जो स्टेट के अन्दर सरकार की गलत नीतियों के कारण पैडीलैस हो गए हैं। आप सबको मालूम है कि पैडी के मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला और रिश्वत काण्ड पिछले 5 साल में हुआ है। बार-बार मिल मालिकों को रिश्वत देने पर मजबूर किया गया और उनको जेलों में डाला गया। फूड जोन और जगहों पर भी बने हैं । मेरा कहना सिर्फ यह है कि पानीपत में इन्फ्रास्ट्रक्टर ऑलरैडी है और बड़ी-बड़ी फैक्टरियां है जो टिन्ड फूड बनाती हैं। करनाल और पानीपत में भी अचार का बहुत बड़ा उद्योग है। इन सारी चीजों के लिए अगर आप करनाल और पानीपत के बीच में कोई ऐसी सुविधा पैदा करें जिससे वहां पर उद्योग बढ़ें और वहां पर बैठे-बैठे लोग जो सब्जी का काम करते हैं यह फेसिलिटी न होने की वजह से हमारी सब्जी रोटन हो जाती है। नई फैक्टरियां लगाने से इस इलाके के किसानों का भी बहुत भला होगा। क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि क्या सरकार इस प्रकार की कोई सोच यहां के लिएं रखती हैं अथवा कोई और जोन ऐड किया जा सकता है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न एक साथ पूछे हैं। पहला प्रश्न पानीपत, करनाल और कैथल बैल्ट में धान का उद्योग लगाने के बारे में है और दूसरा सवाल सब्जी और दूसरे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य तथा हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो क्लस्टर डिवैल्पमैंट स्कीम है, सरकार ने पहले ही टैक्सटाईल क्लास्टर बनाने का फैसला किया है और इसी प्रकार से अपग्रेडेशन ऑफ फेसिलिटिज, एग्रीकल्चरल इम्पलीमैंटस खेतीबाड़ी के जो उपकरण हैं उनका क्लस्टर बनाने, प्रोत्साहित करने और सब सुविधाएं देने के लिए करनाल को आईडैंटिफाई किया गया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने चमड़ा उद्योग को भी करनाल में विशेष प्रोत्साहन और इनसैंटिव देने का फैसला किया है। स्पीकर सर, इसके अलावा सब से पहले इकोनोमिक जोन का जिक्र है, वह सरकार ने बनाने का फैसला किया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा

कि ये किसी विशेष उद्योग की बात करें जैसे कि इन्होंने राईस शैलर और मिल मालिकों की चर्चा की है। मैंने पहले भी माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में बताया था उनकी ऐसोशिऐशजं आएं और उद्योग मन्त्री जी से मिलें। माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिलें, सरकार उनकी सब समस्याओं का निदान करेगी। जहां तक सब्जी, फल-फूल पैदा करने वाले किसानों का सवाल है, हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी उचित मार्किट वैल्यू उन्हें मिले और वह रोटन न करें इसके लिए जो भी कारगर कदम उठाने हैं उसके लिए सरकार वह सब कुछ करेगी जो किया जा सकता है।

Vacant posts of Doctors

***61. I.G. Sher Singh :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the number of posts of doctors lying vacant in the Government Hospitals in the State at present togetherwith the category-wise details of the vacant posts of specialized doctors;

(b) the steps taken or proposed to be taken to fill up the said vacant posts of doctors.

(c) whether it is a fact that the posts of doctors are lying vacant due to the tendency of doctors for opening of nursing home after leaving the Government services; and

(d) if so, the steps taken or proposed to be taken to curb the tendency of the doctors?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) : श्रीमान जी,

(क) इस समय चिकित्सकों के 162 पद रिक्त हैं। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग से कोई काडर नहीं है।

(ख) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) (ग) के समक्ष (घ) अप्रासंगिक है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपकी अनुमति से सदन को इस सवाल के बारे में विस्तार से बताना चाहूंगी कि इस समय प्रदेश में डॉक्टर्ज के 162 पद खाली हैं जिनमें से 6 सिविल सर्जन के हैं और 41 पद एस०एम०ओज० के और 115 पद एम०ओज० के खाली हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि जो सिविल सर्जन के पद हैं वे हमेशा पदोन्नति से भरे जाते हैं और छः की पदोन्नति की गई है उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी की एप्रूवल की बात रहती है। उम्मीद है कि एप्रूवल एक-दो दिन में कर दी जाएगी। एस०एम०ओज० के पद 75% बाई प्रमोशन से और 25% पद डायरैक्ट रिक्रूटमैंट से भर्ती किए जाने हैं। प्रमोशन वाली प्रक्रिया जारी है। एस०एम०ओज० के जो पद बाई प्रमोशन भरे जाने हैं, जल्दी ही भर दिए जाएंगे। जो 115 एस०एम०ओज० के पद खाली है उनके लिए विभाग ने पहले ही पब्लिक सर्विस कमीशन को केस

[बहन करतार देवी]

भेजा था लेकिन जिस तरह से पूरी स्टेट में सन्देह का वातावरण एच०पी०एस०सी० के प्रति बना हुआ है। उसको देखते हुए वह मांग वापिस ले ली है और विभागीय स्तर पर जैसे कि सरकार ने निर्णय लिया है, फाईनैंशियल सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है उस द्वारा जल्दी ही चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और बहुत शीघ्र ही इन पदों को भर लिया जाएगा।

Mr. Speaker : Questions hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेंज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Bifurcation /Trifurcation of Feeders

***41. Shri Somvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that 11KV feeders of Budhera, Kural Bass, Bithan, Sirsali, Gignow, Sohansara, Ahmadwas, Sirsai, Sorda are overloaded; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to bifurcate/trifurcate the aforesaid feeders and also replace the worn out polls and conductors?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां, श्रीमान।

(ख) इन 9 नं० 11 के०वी० ओवरलोड फीडरों को 20 नं० 11 के०वी० फीडरों में द्विभाजित /त्रिविभाजित करने का प्रस्ताव है जिसमें जीर्ण-शीर्ण खम्भों तथा कन्डक्टरज का बदलना भी शामिल है। एस्टीमेट स्वीकृत हो चुके हैं तथा अग्रिम कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

Present position of Power in the State

***38. Dr. Sita Ram**
Dr. Sushil Kumar Indora : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the present position of power in the State ; and

(b) the steps being taken by the Government to meet the increasing demands of power in the State ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) वर्तमान समय में राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति पूर्णतया संतोषजनक है। राज्य में समग्र विद्युत उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि हुई है। राज्य के पास 4033 मैगावाट की उपलब्ध स्थापित उत्पादन क्षमता है। वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं (धौलीगंगा, दुल्हस्ती, रिहन्द चरण-2) में हिस्से से अन्य 101 मैगावाट क्षमता जोड़ी जाने की सम्भावना है।

अप्रैल-जून, 2005 के दौरान राज्य में विद्युत उपलब्धता निम्न प्रकार से है :—

मास	राज्य में समग्र विद्युत उपलब्धता (लाख यूनिट प्रतिदिन)		ग्रामीण क्षेत्र को दी गई विद्युत आपूर्ति	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
अप्रैल	532	547	246	236
मई	557	645	257	306
जून (5 तक)	587	718	277	348

मई 2005 के दौरान औसतन 645 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन सप्लाई की गई थी जोकि पिछले साल (557 लाख यूनिट/प्रतिदिन) की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र को दी गई बिजली आपूर्ति 306 लाख यूनिट प्रतिदिन रही जोकि पिछले वर्ष (257 लाख यूनिट/प्रतिदिन) की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।

चालू मास के दौरान बिजली की मांग अत्यधिक बढ़ी है। राज्य में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक बिजली दी जा रही है।

राज्य के निजी उत्पादन केन्द्रों में बेहतर कार्यकुशलता के माध्यम से अधिक बिजली उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में 3-6-2005 को (290 लाख यूनिट का) एक रिकार्ड उत्पादन किया है। राज्य दिनांक 1-6-2005 को 3719 मैगावाट की अधिकतम मांग को पूरा करने में समर्थ रहा है।

(ख) राज्य सरकार, राज्य में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न कर रही है। उठाए गए/उठाए जा रहे विभिन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कदम निम्न प्रकार से हैं :—

अल्पकालिक उपाय

1. राज्य विद्युत निगम ने दो वर्ष की अवधि के लिए मलाना पन बिजली परियोजना की 82 मैगावाट बिजली के लिए मलाना पावर कम्पनी के साथ समझौता किया जो जुलाई 2005 से शुरू हो रहा है।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र से 28 मैगावाट बिजली का (जुलाई से सितम्बर 2005 तक) टाटा पावर ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से प्रबन्ध किया गया है।

3. उत्तरांचल से 75 मैगावाट बिजली लेने के लिए यू०पी०सी०एल० के साथ बैंकिंग व्यवस्था के आधार पर प्रयास किए गए हैं। शीघ्र ही एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

है। आपसी (बार्टर) प्रबन्ध के अन्तर्गत यू०पी०सी०एल० जून से अक्तूबर 2005 तक बिजली आपूर्ति करेगा तथा नवम्बर 2005 से मार्च 2006 तक बिजली वापस प्राप्त करेगा।

4. उत्तरांचल से 150 मैगावाट बिजली के लिए (जुलाई से सितम्बर 2005 तक) मैसर्ज टाटा पावर ट्रैडिंग कम्पनी के साथ टाई-अप किया है।

5. इस सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश की नाथपा झाखड़ी परियोजना से प्राप्त 330 मैगावाट बिजली से सरप्लस बिजली प्राप्त करने हेतु प्रयास किए गए है।

6. एन०टी०पी०सी० फरीदाबाद की फरीदाबाद गैस विद्युत केन्द्र में प्रयोग करने के लिए गेल से 0.5 एम०एम०सी०एम०डी० आर०एल०एन०जी० टाई-अप किया है ताकि उस प्लांट की 20-25 प्रतिशत तक की बची हुई क्षमता का अतिरिक्त उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सके।

दीर्घकालिक उपाय

राज्य सरकार, राज्य में भावी बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अपनी निजी उत्पान क्षमता तथा बिजली की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

1. यमुनानगर में 2x300 मैगावाट थर्मल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2. इसी क्षमता की गैस पर आधारित दो अन्य विद्युत परियोजनाओं (यमुनानगर चरण-II एवं हिसार) के क्रियान्वयन द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3. हरियाणा को 10वीं तथा 11वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की स्थापित की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं से भी लगभग 1000 मैगावाट बिजली प्राप्त होगी।

4. निरन्तर एस०वाई०एल० का पानी न मिलने के परिणाम स्वरूप बिजली की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार के साथ केन्द्रीय अनियतित बिजली के हरियाणा को अधिक नियतन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

Recouping of Backlog

***51. Shri Udai Bhan :** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to recoup the backlog of reserved posts of Scheduled Castes/Backward Classes in the Government and Semi-Government jobs; if so, the details thereof, togetherwith the time by which said backlog is likely to be recouped?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहन करतार देवी) :श्रीमान जी, सरकार की यह नीति है कि राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों को बिना किसी अनावश्यक देरी के भरा जाना सुनिश्चित किया जाए। सरकार पिछले कुछ वर्षों में उत्पन्न हुए आरक्षित पदों के बैकलॉग को पूरा करने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान

चलायेगी। यह आशा की जाती है कि अधिकतर बैकलॉग अगले एक वर्ष के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा।

Complaint against former Chief Minister

***6. Shri Karan Singh Dalal**
Shri Dharam Pal Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to State whether any complaint/chargesheet in regard to the misuse of power, financial irregularities, corruption and acquisition of assists disproportionate to known source of income, irregularities in awarding tenders and Government purchase has been received by the Government against the former Chief Minister, Haryana during the year 2000 to 2005; if so, the action so far taken or proposed to be taken thereon?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जी हां, वर्ष 2000-2005 की अवधि में श्री ओम प्रकाश चौटाला, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध 17 शिकायतें विभिन्न व्यक्तियों/ संगठनों से प्राप्त हुई थीं। इन पर की गई/की जाने वाली नवीनतम कार्यवाही का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

अनुबन्ध

क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	आरोप	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1. (क)	श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रधान, युवा कांग्रेस	5-11-2004	गांव नाथूपुर (गुड़गांव) ग्राम पंचायत की सवा सौ करोड़ रु० की जमीन चार करोड़ में डी० एल०एफ० को बेचने बारे	तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आदेश दिए थे कि मंत्रि-परिषद के निर्णयानुसार 19.5 एकड़ जमीन को de-notified कर दिया गया है। अतः इस शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
(ख)	श्री करण सिंह दलाल, विधायक	8-11-2004	-सम-	-सम-
2.	श्री करण सिंह दलाल, विधायक	8-11-2004	गांव बंधवाड़ी तथा गवालपहाड़ी (गुड़गांव) की एक हजार एकड़ जमीन का घोटाला।	तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आदेश दिए थे कि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। अतः इस शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5
3.	श्री खजान सिंह, सचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सिविल लाईन, गुड़गांव।	20-10-2004	गांव बिन्दापुर झाड़सा (गुड़गांव) में 25 करोड़ रु० की जमीन को मात्र 70.00 लाख रु० में अधिग्रहित करवाना।	उपायुक्त, गुड़गांव से 13-5-05 को रिपोर्ट मांगी गई है, जो अभी अपेक्षित है।
4.	श्री जयपाल सिंह, पूर्व शराब ठेकेदार	4-9-2003	शराब के ठेकों की नीलामी में 65.00 करोड़ रु० का घोटाला सी०बी०आई० जांच की मांग।	तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आदेश दिए थे कि इस मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग से को टिप्पणी प्राप्त कर जाए। इस बारे विभाग को टिप्पणी हेतू 4-11-2003 को गया है, टिप्पणी अभी अपेक्षित है।
5.	श्री कृष्ण लाल, निवासी सिरसा	15-4-05	श्री गोपी चन्द टैक्सटाइल मिल्स, हिसार रोड, सिरसा नाजायज खरीद बारे।	यह शिकायत चौकसी विभाग में 25-5-05 से जांच हेतु लम्बित है।
6.	श्री खजान सिंह, सचिव, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सिविल लाईन, गुड़गांव	2-10-2004	शिकायत बाबत हुडा विभाग द्वारा किसानों की दादालाई जमीनों से बिजनैस करके हजारों करोड़ के घोटाले आदि करने बारे।	यह शिकायत चौकसी विभाग में 2-10-04 से जांच हेतु लम्बित है।
7.	श्री रविन्द्र कुमार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा, दिल्ली	27-1-2004	सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना -निदेशक, इरोज सिटी डिवैल्पर, प्रा०लि०।	यह शिकायत चौकसी विभाग में 14-12-04 से जांच हेतु लम्बित है।
8.	श्री अशोक कुमार पत्रकार, चण्डीगढ	-	एम०बी०बी०एस० के दाखिलों में हेरा-फेरी	यह शिकायत चौकसी विभाग में 6-1-2005 से जांच हेतु लम्बित है।

1	2	3	4	5
9.	श्री प्रताप सिंह चौटाला, भूतपूर्व विधायक, मण्डी डबवाली	13-4-2004	आय से अधिक चल-अचल सम्पति अर्जित करने बारे।	यह शिकायत चौकसी विभाग में 2-2-2001 से जांच हेतु लम्बित है।
10.	श्री हरपाल सिंह, वासी बहूअकबरपुर (रोहतक)		पशुपालन विभाग में विकास कार्यों के लिए दी गई राशि मे लाखों का घोटाला।	यह शिकायत चौकसी विभाग में 24-5-2005 से जांच हेतु लम्बित है।
11.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री ओम प्रकाश, वासी चौटाला	27-9-2001	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मनी राम के विरुद्ध झूठे मुकदमें दर्ज कराने बारे।	शिकायत कर्ता का पति एक अपराधी प्रवृति का व्यक्ति था। आरोप निराधार पाए गए थे।
12.	श्री रवि चौटाला पुत्र प्रताप सिंह चौटाला वासी सिरसा	4-12-2002	परिवादी को धमकी देने और मुकदमा में झूठा फंसाने बारे।	शिकायत झूठी एवं निराधार पाई गई थी तथा इसे फाईल कर दिया गया था
13.	श्रीमती मुकेश पत्नी सतपाल पहाड़ी वासी कृष्णा कालौनी, भिवानी	29-1-2003	परिवादी के पति के विरुद्ध राजनैतिक कारणों से झूठे फौजदारी मुकदमें दर्ज कराने बारे।	शिकायत कर्ता का पति हरियाणा विकास पार्टी का कार्यकर्ता है और कई अपराधों में संलिप्त रहा है तथा बचाव में दी गई शिकायत को 11-6-2002 को फाइल कर दिया गया है।
14.	श्री चन्द्र शेखर धरनी कार्यालय प्रभारी पंजाब केसरी कार्यालय, पानीपत	12-4-2005, 28-4-05 व 26-5-05	बाबत परिवादी के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाने, पत्नी का स्थानान्तरण कराने व परिवार का उत्पीड़न इत्यादि।	इस शिकायत की जांच जिला पुलिस प्रमुख, पानीपत से कराने हेतु 27-4-2005 को लिखा गया है।
15.	श्री कुलदीप सिंह गदराना, अधिवक्ता वासी औढा जिला सिरसा	17-5-2005	परिवादी को झूठे केसों में फंसाने बारे	आरोप निराधार पाए गए और मामला 10-7-2004 को फाईल कर दिया गया है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

1	2	3	4	5
16.	गुमनाम शिकायत	7-6-2005	श्री सोम सेठी, पत्थर/रोड़ी ठेकेदार,फरीदाबाद तथा अन्य द्वारा श्री ओम प्रकाश चौटाला, भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा अन्य की मिली भगत से सरकार को 5000 करोड़ रुपए की टैक्स रायल्टी का नुकसान पंहुचाने बारे।	शिकायत का निरीक्षण चौकसी विभाग द्वारा किया जा रहा है।
17.	श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला	13-6-2005	सत्ता में रहते हुए आय से अधिक चल/अचल सम्पत्ति अर्जित करने बारे।	दिनांक 13-6-2005 को निदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो को जांच हेतु लिख दिया गया है।

Vegetable Grown in Jail Gardens

***12. Shri Dharam Pal Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the vegetable grown in the jail gardens in the State togetherwith the quantity produced in each Jail separately during the period from 1996 to till date; and

(b) the details of the above vegetable sold in the market and provided to the prisoners kitchen, separately during the period referred to in part (a) above ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हरियाणा राज्य की प्रत्येक जेल के उद्यान में वर्ष 1996 से मार्च, 2001 तक पैदा की गई सब्जी का ब्यौरा निम्न प्रकार से है तथा विधान सभा के पटल पर रखा जाता है :—

क्र० सं०	जेल का नाम	वर्ष 1996 से 2001	उगाई गई सब्जियों की मात्रा क्विन्टल	कि०ग्रा०	ग्राम
1.	केन्द्रीय जेल, अम्बाला	-do-	171	15	0
2.	केन्द्रीय जेल, हिसार	-do-	1831	87	370
3.	जिला जेल, रोहतक	-do-	1842	49	0

4.	जिला जेल, करनाल	-do-	2980	78	269
5.	जिला जेल, भिवानी	-do-	2045	0	0
6.	जिला जेल, सोनीपत	-do-	777	78	579
7.	जिला जेल, जीन्द	-do-	170	20	0
8.	जिला जेल, गुड़गांव	-do-	175	51	0
9.	जिला जेल, कुरुक्षेत्र	-do-	72	27	0
10.	बच्चा जेल, हिसार	-do-	204	52	430

(ख) बाजार में सब्जी की बिक्री नहीं की गई। वर्ष 1996 से मार्च, 2001 तक पैदा की गई तथा कैदियों की रसोई में उपलब्ध करवाई गई सब्जी का ब्यौरा निम्न प्रकार से है तथा विधान सभा के पटल पर रखा जाता है :—

क्र०सं० जेल का नाम	वर्ष 1996 से 2001	बन्दियों के किचन में उपलब्ध करवाई गई सब्जियों की मात्रा		
		क्विन्टल	कि०ग्रा०	ग्राम
1. केन्द्रीय जेल, अम्बाला	-do-	171	15	0
2. केन्द्रीय जेल, हिसार	-do-	1831	87	370
3. जिला जेल, रोहतक	-do-	1842	49	0
4. जिला जेल, करनाल	-do-	2980	78	269
5. जिला जेल, भिवानी	-do-	2045	0	0
6. जिला जेल, सोनीपत	-do-	777	78	579
7. जिला जेल, जीन्द	-do-	170	20	0
8. जिला जेल, गुड़गांव	-do-	175	51	0
9. जिला जेल, कुरुक्षेत्र	-do-	72	27	0
10. बच्चा जेल, हिसार	-do-	204	52	430

यह भी बताना उचित होगा कि सरकार ने दिनांक 14-3-2001 को निर्णय लिया था कि प्रत्येक जेल की कृषि योग्य भूमि ठेके पर दी जाएगी।

Thurana-Majra Road

***63. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open the road from Thurana to Majra lying blocked due to water flowing ?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : इस समय यह सड़क आप्रेशनल है। परन्तु गांव की नालियों की हालत अच्छी न होने के कारण गांव भाजरा का गन्दा पानी समय-समय पर सड़क पर इक्ट्ठा हो जाता है समस्या के समाधान के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

Agriculture College, Bawal

***34. Shri Naresh Yadav** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Agriculture College functioning earlier in Bawal is lying closed presently; and

(b) if the reply to part (a) above is in affirmative, whether the Government intends to reopen the said college; if so, the time by which it is likely to be reopened?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

Loharu Lift Irrigation System

***42. Shri Somvir Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the channels of Loharu Lift Irrigation System feeding Loharu Constituency are not getting sufficient water ; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government to improve the lifting capacity of pumps of the Loharu Lift Irrigation System, removal of beam of Loharu feeders and desilting of Loharu canal system ?

राजस्व मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) आपूर्ति को नहर प्रणाली के अन्तिम छोर तक पहुंचाने व समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए, लोहारू व बधवाना नहर प्रणाली के जलघरों की उठान क्षमता का विभिन्न चरणों में सुधार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त लोहारू फीडर, लोहारू नहर और बधवाना डिस्ट्रीब्यूटरी की प्रवाह क्षमता में सुधार करने की योजना है ताकि अवरोधक (बर्म) हटाने व गाद निकालने के उपरान्त ये नहरें अपनी प्राधिकृत क्षमता के साथ प्रवाह कर सकें।

Supply of contaminated water in Gurgaon Feeder

***52. Shri Udai Bhan** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the water of Haryana which is supplied to Gurgaon Feeder/Agra Canal from Okhla Head of Delhi is totally contaminated with chemicals due to which the agricultural land of

the whole of Faridabad district is becoming unfertile and the drinking water of the said area has totally polluted; and

(b) if so, the action being taken by the Government in this regard?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) नहीं, श्रीमान्

यद्यपि यमुना नदी से दिल्ली के ओखला हैड के माध्यम से गुड़गांव फीडर/आगरा नहर में सप्लाई किये जा रहे पानी में प्रदूषण का स्तर ऊंचा है जो कि मुख्यत : दिल्ली की 19 ड्रेन और उत्तर प्रदेश की एक ड्रेन द्वारा यमुना नदी में छोड़े जाने वाला घरेलू मल की वजह से है। गुड़गांव फीडर/आगरा नहर पर आधारित कोई जल सप्लाई प्रणाली नहीं है।

(ख) यह एक अन्तर्राज्जीय प्रदूषण समस्या है और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने इस मामले को दिल्ली सरकार के साथ उठाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को लिखा है कि वे केवल शोधित मल ही यमुना में डालना सुनिश्चित करे।

राज्य सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को लिखकर अनुरोध किया है कि वह दिल्ली सरकार को गुड़गांव/आगरा नहर में गिर रहे यमुना नदी के अत्यधिक प्रदूषित जल की समस्या को सुलझाने हेतु शीघ्र कदम उठाने के निर्देश जारी करे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नहरों के छोरों तक पानी न बहने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion No. 3 from Shri Dharampal Malik, MLA regarding non flowing of water on the tails of the canals in several parts of Haryana, especially in Gohana tehsil. I admit it. Shri Dharampal Malik will read his Notice.

Ch. Dharampal Singh Malik : Mr. Speaker Sir, I want to draw the attention of Governmenmt with regard to the matter of an urgent public importance that on account of non flowing of water on the tails of the canals in several parts of Haryana, especially in Gohana tehsil due to theft committed by those people whose fields are situated near the canals Head, the crops of the farmers are being damaged/ruined for non supply of water in their fields.

So, Sir, I want that the Minister should make a statement on this matter as the crops of crores of rupees have been damaged during this year.

वक्तव्य-

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, I would request the Revenue Minister to make a statement.

Revenue Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Speaker Sir, water availability in Haryana is much less than the requirement. Whereas the ideal requirement for Haryana for meeting all water requirements is 36 MAF, the availability of surface and sub-surface water is only about 14 MAF. Consequently irrigation channels are run in groups. The availability position is being aggravated as the State is not getting its allotted share of Ravi-Beas waters because of non completion of SYL Canal in Punjab portion despite the fact that Hon'ble Supreme Court has already directed the completion of the same on 15th January, 2002 and 4th June, 2004. The availability in Western Yamuna Canal (WJC) and Lift areas has further suffered because of capacity constraint of Narwana Branch and also because Haryana has to supply Yamuna water to Delhi much in excess of their share because of the order of Hon'ble Supreme Court made in a Public Interest Litigation. It is true that theft of water results in avoidable shortage of water at the tails. The Irrigation Department checks theft by imposition of tawan and lodging criminal complaints with the police. In cases where technical solutions for improving water supply to tails are possible at a viable cost, improvement schemes are being implemented.

There are 29 tails of canals in Gohana Sub Divn. The system of irrigation in Gohana Sub Divn. mainly comprises channels and direct outlets off-taking from Butana Branch, Bhalaut Sub Branch, Bainswal Disty. system, Dubeta Disty., Bajana Disty., Gohana Disty. system and Israna Disty. system. The irrigation of Gohana Division is mainly supervised by Gohana Water Services Division at Gohana. However, some of the irrigation area on Gohana Disty. and Israna Disty. systems is looked after by Panipat Water Services Divn., Panipat. Whereas total Culturable Command Area (CCA) of Gohana Sub Division under Gohana Water Services Division is about 1.30 lacs acres, the CCA under Panipat Water Services Division is about 19000 acres. The irrigation intensity achieved in the areas of Gohana Water Services Division is of the order of 76% to 80% against an overall State average of 68%. The irrigation achieved in the area of Panipat Water Services Division is only 42%. Out of 25 tails under control of Gohana Water Services Division only two tails namely Bhainswal Disty. and Gillor Minor are some times short. Out of the four tails under control of Panipat Water Services Division, tail of Jawara Minor is normally short and tail of Israna Minor is also short at times. Admittedly the irrigation intensity on Israna Disty. and Gohana Disty. system comprising Siwanka and Jawara Minor is only 42% and is less than the average irrigation achieved in WJC command. Low intensity of irrigation is mainly because of lower irrigation on Israna Disty. and Jawara Minor. The irrigation in Israna Disty area and Jawara Minor area will improve after construction of a new channel named Ramgarh Disty. approved under Nabard funded RJDF-X at a cost of Rs. 7.88 crores for which land acquisition proceedings are already under progress.

Admittedly there are cases of water theft in this area as also in other areas of the State, Gohana Water Service Division, Gohana registered 1465 cases of water theft during the period from 1-4-2004 to 31-3-2005. Out of these cases 1265 cases were decided by the Divisional Canal Officer wherein Tawan of Rs. 10.70 lacs was imposed on the offending cultivators. The Division lodged 106 FIRs during this period. Panipat Water Service Division also registered about 700 cases of water theft during this period and Tawan of about Rs. 4 lacs was imposed during the year on the offending cultivators. It is a fact that because of such large scale water thefts the interest of the farmers at the tail of the channels suffer. Such large scale theft of water, however, has to be seen not merely in the context of law and order problem. It is also a social problem.

However, the over-all intensity of irrigation in Gohana Administrative Sub Division is of the order of 73.86% and above the general average of the WJC command. So far as WJC command in the Yamuna Water Services Unit is concerned, excluding Agra Canal area, an average of 9.75 lac acres is irrigated against the CCA of about 15.355 lac acres. Therefore, the irrigation intensity achieved is about 63.5%. Out of 241 tails in Yamuna Water Services Unit there had been only 6 chronically short tails. There is one chronically short tail in Gohana Sub Division namely Jawara Minor. The position of shortage of tails in other commands, as on 31-3-2005 is that out of 427 tails in Bhakra Water Services Unit, 57 tails were short. In the Lift Canal Unit out of 504 tails 200 tails were short. The overall position of the State showed 263 tails short out of total 1172 tails.

I am glad to inform the House, as has been acknowledged by the Hon'ble Members themselves, water availability in the State, particularly in chronically short areas has improved considerably. This trend will continue.

Ch. Dharam Pal Malik : Sir, I want to clarify few points. सर, मंत्री महोदय ने भी यह माना कि टेल पर पानी नहीं पहुंचा है और गोहाना तहसील के जो एक साल में 1465 केसिज थैफ्ट के हैं उनमें से बहुत कम केसिज में एफ०आई०आर० रजिस्टर्ड हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि It is a very heinous crime क्योंकि नहरों में पहले पानी तोड़कर आगे वाले लोगों के पेट पर लात मारी जाती है आगे नहरों में पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है और न ही उनके तालाबों में पानी पहुंचता है। स्पीकर सर, दस बारह गांव ऐसे हैं जिनके बारे में मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। क्या उनके पास ऐसे फैक्टस हैं कि इन गांवों में पिछले बीस-तीस सालों में आज तक पानी क्यों नहीं गया है ? इनमें से कुछ गांवों के नाम हैं कासन्डी, कासन्डा, सयामणी, खानपुर गामड़ी, गढ़ी उजेलखा, गढ़ी रामगढ़, कैलाना और सैनीपुरा आदि। इन गांवों में आज तक भी पानी नहीं गया है हालांकि यह कमान्ड एरिया में आते हैं । बहुत सारे पानी की थैफ्ट हो जाती है इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या भविष्य में थैफ्ट केसिज में एफ०आई०आर० रजिस्टर्ड की जाएगी क्योंकि थैफ्ट एक कागनीजेबल ऑफेन्स है । क्या मंत्री महोदय नहरी पानी की थैफ्ट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के बारे में सहमत हैं या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने थैफ्ट के बारे में बात कही है उससे हम लोग भी काफी कंसर्न्ड हैं। हमारे महकमें के लोगों ने काफी केसिज भी दर्ज किए

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

हैं। यह एक सोशल प्रौब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की तरफ से कई दफा समझा बुझाकर केसिज कम दर्ज कर दिए जाते हैं। जिन गांवों में पानी नहीं पहुंचा है माननीय सदस्य उसके बारे में लिखकर मुझे दे दें, उनके यहां टेल पर पानी पहुंचाने के बारे में पूरी कार्यवाही करेंगे। जहां तक ऐक्शन का सवाल है, एक्शन भी लेंगे लेकिन इसमें इनके मैम्बर्ज का भी हमें पूरा सहयोग चाहिए, वे भी लोगों को इस बारे में शिक्षित करें कि वे ऐसी कार्यवाही न करें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मिनिस्टर महोदय ने यह माना है However, some of the areas of Gohana Distributory and Israna system is looked after by Panipat Water Services Division, Panipat. इसमें मेरा कहना यह है कि वह अधिकारी जो पानीपत बैठा है He has to looked after the area of Gohana Tehsil and his Head office is at Panipat. I do not understand what is the sense in it. लोग वहां पानीपत हर काम के लिए जाएं, क्या यह ठीक है ? क्या मंत्री महोदय उस ऑफिस को गोहाना शिफ्ट करने के लिए रजामंद हैं या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : जो माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा है मैंने भी कल अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की है। हम फिजिबिलिटी देख रहे हैं, यदि ऐसा लगेगा कि पानीपत से गोहाना ऑफिस जाने में फायदा है तो उचित कार्यवाही करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में 28 फुट लंबा जेवर टेप्पल सीमान्त बांध बना दिया गया है और वह हमारे यहां के बांध से ऊंचा है मेरा इस बारे में कालिंग अटैंशन मोशन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरा भी कालिंग अटैंशन मोशन है That is regarding construction of bunds alongwith Eastern Banks of Yamuna river in U.P. Govt. from Delhi to U.P. Border.

Mr. Speaker : These are lying with the Government, you can enquire tomorrow.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay the papers on the Table of the House.

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the table—

> The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1994-1995, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1995-1996, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1996-1997, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1997-1998, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1998-1999, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 1999-2000, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2000-2001, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report of Haryana Police Housing Corporation Limited for the year 2001-2002, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

वर्ष 2005-2006 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारंभ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on Budget for the year 2005-2006 will be resumed. Shri Arjan Singh was on his legs, when House was adjourned. He may please resume his speech. आनरेबल मैम्बर्ज, आपसे मैंने एक गुजारिश करनी है कि कोई भी मैंबर साहेबान 15 मिनट से ज्यादा न बोले। बहुत से सदस्यों ने बोलना है और आज का दिन हमारे पास बचा है कल यह न कहना कि हमें टाइम नहीं मिला।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने हल्के की समस्याओं से अवगत करवाना चाहता हूं। मेरे हल्के में ज्यादातर आबादी गरीब लोगों की है। वे गरीब लोग फूस के मकान बना कर रहते हैं और आजकल गर्मियों के दिनों में हर रोज किसी न किसी फूस के घर में आग लग जाती है इसलिए इसके लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। ताकि वे गरीब लोग लगने वाली उस आग से बच सकें। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसे बैट्री लेकर भी ढूंढा जा सके। चाहे लिंक रोडज हैं और चाहे अप्रोच रोडज़ हैं। पिछली सरकार के मुख्य मंत्री ने एक रोड बनाई थी जिसे उन्होंने अपने लिए ही बनाया था और खुद ही उससे निकल जाते थे। मेरा अनुरोध है कि एक स्पेशल रोड बनाई जाए जिस पर 40-50 टन का लोड सहन करने की क्षमता हो यानि जिस हिसाब से वहां लोड है उस हिसाब से सड़क बनाई जाए। इसके

[श्री अर्जन सिंह]

अलावा वहां पर बसों की सुविधा भी नहीं है। मेरे हल्के में जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वे भी जहां तक उनका रूट है वहां तक नहीं जाती । मेरे हल्के में एक सबसे बड़ी समस्या है, वह है कि वहां कोई कालेज नहीं है और न ही कोई अस्पताल है वहां पर केवल दो छोटी-छोटी डिस्पैंसरीज हैं और उनमें भी कोई सुविधा नहीं है व न कोई डाक्टर है वहां पर अच्छी डिस्पैंसरीज या अस्पताल न होने के कारण लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि मेरे हल्के की समस्याओं की तरफ भी ध्यान दिया जाये। मुख्यमंत्री जी उठकर जा लिए, अब मैं अपनी बात कहूं किस से। जहां तक आप लोगों की पब्लिसिटी का सवाल है तो हमारे काम होंगे तो उसका श्रेय सरकार को जायेगा क्योंकि जनता को पता है कि जितने काम होंगे वह सरकार ही कर सकती है तो उसका श्रेय मौजूदा सरकार को जायेगा। उसको पता है कि कोई एम०एल०ए० अपने आप तो कोई काम कर नहीं सकता जिस प्रकार आप अपने हल्के के काम कर रहे हैं वैसे ही हमारे काम करो तो उसका श्रेय आपकी सरकार को ही जायेगा। यह सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है, निष्पक्ष काम कर रही है और सब के लिए काम कर रही है। अगर सरकार नहरों का इन्तजाम ठीक कर सके तो उसको करना चाहिए क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसी को कांम करने का श्रेय जाता है। अगर टीका-टिप्पणी करने की बजाए कि पिछली सरकार ने यह नहीं किया या विपक्ष यह कहे कि पिछली सरकार ने यह किया उसमें तो सदन का समय खराब करने की बात है, अगर पिछली सरकार ने नहीं किया तो अब आपकी सरकार कर दे। पिछली सरकार के पास भी तो साढ़े पांच साल थे उसने उस समय क्यों नहीं किए। आज इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हाउस जिस ढंग से चल रहा है वह बहुत ही अच्छे तरीकेसे चल रहा है। हर सदस्य को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है और जो भी कोई अपने हल्के की ग्रीवेन्सिज है वह यहां पर कह सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदेश में भयमुक्त माहौल है, कोई चोरी और डकैती का सामना लोगों को नहीं करना पड़ रहा है । जैसे पिछली सरकार के समय में था। एक बात मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में बिजली के कनैक्शन के लिए लोगों ने जो 15 सालों से सिक्योरिटी जमा करा रखी थीं उनको कनैक्शन नहीं दिए गये जबकि उनकी सिक्योरिटी मौजूद थी बल्कि पिछली सरकार ने एक नई स्कीम बनाई कि पैसा देकर कोई भी टयूबवैल के कनैक्शन ले सकता है ? अगर किसी आदमी के पास पैसे नहीं है तो क्या उसको कनैक्शन नहीं मिलेगा और क्या वह बैठा रहेगा ? जिन्होंने 15 साल से सिक्योरिटी जमा कर रखी है और जो स्कीम बनाई थी उसके तहत भी लोगों को यह कहा कि तीन महीने में कनैक्शन मिल जायेंगे लेकिन उनको 6 महीने तक भी कनैक्शन नहीं मिल पाये। जब पूछा गया तो कहा कि हमारे पास सामान नहीं है। फिर पैसा किस बात के लिए लिया ? इस बात पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर सर, एक बहुत भारी समस्या टोल टैक्स ही है। किसी भी सड़क पर जाओ बांस लगाकर खड़े हैं कि टोल टैक्स दो। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, यह बताते नहीं कि यह टोल टैक्स किस बात के लिए है जितनी बार भी सड़क से गुजरो हर बार का 50 रुपये टैक्स वसूला जा रहा है। एक आदमी आकर फिर पीछे हट गया किसी से मिलने के लिए और अब वह दोबारा वापिस आया तो उससे दोबारा 50 रुपये लिए गए जब वह बोला कि मैं तो किसी से मिलने यहां तक गया था तो उसको कहा गया कि जितनी बार यहां से निकलोगे उतनी बार 50 रुपये देने ही पड़ेंगे। (विघ्न) यह जी०टी० रोड पर करनाल के पास है। आप चाहें तो अपनी गाड़ी की बत्ती उतारकर वहां

से निकल कर देख सकते हैं, वहां बत्ती वाले को तो वे छेड़ते नहीं और किसी को छोड़ते नहीं (विघ्न) पंजाब वाले MLA से भी लेते हैं, वे लेते हैं तो कहते हैं हमने पुल बनवाया है लेकिन करनाल में तो कोई पुल भी नहीं बनाया गया । गवर्नमैंट ने रेत-बजरी आदि सभी चीजों का रेट निर्धारित कर रखा है लेकिन पौपुलर की फसल का कोई रेट गवर्नमैंट ने निर्धारित नहीं कर रखा। फैक्ट्री वाले इसको खरीदते समय अपनी मनमर्जी का रेट देते हैं। जमींदार को इस बात का पता नहीं होता कि इसके रेट क्या लगेंगे। इस मोनोपोली को सरकार को रोकना चाहिए। जब हम अपना अनाज बेचते हैं तो किसान समझता है कि इसको बेचते हुए वह अपनी मनमर्जी का रेट लगाएगा, क्या किसान ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता और अगर वह ऐसा करता है तो सरकार उल्टे उसके खिलाफ केस दर्ज कर देगी और उसके सारे अनाज को गवर्नमैंट खाते में लेकर चली जाएगी। रेत-बजरी भी एक निजी जरूरत है और इसके भी रेट निर्धारित होने चाहिएं। सरकार अपने फायदे के लिए कम्पीटिशन में रेट बढ़ा देती है। गरीब आदमी को एक ट्राली बजरी लेने के लिए 500 रुपये की रौयल्टी देनी पड़ती है, इतने की बजरी नहीं होती जितनी उसको रोयल्टी देनी पड़ती है इसलिए सरकार को इसके रेट निर्धारित करने चाहिएं। उसकी बोली कोई तभी देगा जब वह अपनी बजरी निर्धारित रेट पर देने के लिए तैयार होगा। दूसरा जो चालान काटे जा रहे हैं इसके लिये यह सरकार बसों का इंतजार करे ताकि सवारियों को आने-जाने में दिक्कत न आए। जीपों वाले अपने रोजगार के साथ-साथ सवारियों को पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं और उनके एक दिन में 2-3 चालान काटे जाते हैं। यह भी नहीं देखा जाता कि इतना उन्होंने एक दिन में कमाया भी नहीं होता। मोटर साईकिलों वालों के चालान काटने के लिए पुलिस वालों पर कंडीशन लगी हुई है कि एक दिन में 15 चालान तो काटने ही काटने हैं । 15 चालान किस बात पर काटे जब अगले ने सारे डॉक्यूमैंट पूरे करे हुए हैं। सारे कागजात पूरे हैं। फिर भी चालान काटे जाएं। वे अपने डॉक्यूमैंट लेकर कैसे जाएं, किसी ने खेत में जाना है, किसी ने तेल लेने जाना है और किसी ने रोटी देने जाना है। यदि रास्ते में बारिश आ जाएं या रास्ते में वे कागज खो जाएं तो क्या होगा ? पुलिस वालों को यह तो पता होना चाहिएं कि यह जैनयुन आदमी है और इसी गांव का रहने वाला आदमी है। लोगों में आज चालान का भय है। इस सरकार में तो खैर राहत है। पहले की सरकार में बहुत बुरा हाल था। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस ओर गौर करना चाहिए। कुछ अधिकारी पिछली सरकार के यहां बैठे हैं उनकी आदत वही बनी आ रही है जो उन पर रैस्ट हाउस का खर्चा पड़ता था, रैली का खर्चा पड़ता था वह समस्या तो हट गई। अब न किसी के जिम्मे बस लगाई जाती है और न ही जीप लगाई जाती है। उन ऑफिसर्ज की आदत पीछे से बनी आ रही है वे लोगों से पैसा ज्यों का त्यों लेते आ रहे हैं और वे लोगों पर बर्डन डालते आ रहे हैं। मैं कल एक तहसीलदार के पास गया और कहा कि आप किस बात के पैसे ले रहे हैं। आपने जो परसैंटेज बना रखा है वह किस बात का है। क्या आपको सरकार से तनख्वाह नहीं मिल रही। आप ये दो नम्बर के पैसे किस बात के ले रहे हैं। सरकार तो बहुत बढ़िया आई है। लेकिन अफसर ज्यूं के त्यूं हैं, उन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पहले तो कहते थे कि हमें रैस्ट हाउस का खर्चा देना पड़ा, रैली का खर्चा देना पड़ा, अब कौन सा खर्चा देना पड़ता है, हमें पता लगना चाहिए। जहां तक पब्लिसिटी की बात है, आप जो खुद पब्लिसिटी करोगे वह इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी हम आपकी पब्लिसिटी करेंगे। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम अपने हल्के में आकर आपका गुणगान करेंगे कि बहुत बढ़िया सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रही है उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के पेज संख्या पांच पर नेतृत्व परिवर्तन का जिक्र किया गया है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिस दिन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बने उस दिन वाकई में पूरे प्रदेश में खासतौर से दक्षिणी हरियाणा के लोगों में यह बात हो रही थी कि जो पांच साल से भुगत रहे थे वही अब आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के तीन महीने के कार्यकाल में लोगों की यह भ्रांति दूर हो गई है और अब हर वर्ग को बराबर मान-सम्मान मिल रहा है। कहीं पर कोई भी जाटशाही नहीं चल रही। हुड्डा साहब की सरकार के छोटे से कार्यकाल की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रांसफर्ज की बात है उसमें भी हर वर्ग को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल रहा है, चाहे डी०सी० के लैवल की बात हो और चाहे एस०पी० लैवल की बात हो। उपाध्यक्ष महोदय, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अपने मंत्रियों की, अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को आदेश दिये थे कि वह कमेटी पता लगाये कि पश्चिमी बंगाल में 25 साल से लगातार सी०पी०एम० की सरकार कैसे राज कर रही है। कमेटी के सदस्य पश्चिमी बंगाल गये और मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दी कि वहां पर ज्योतिबसु की सरकार के लगातार 25 साल तक चलने के क्या कारण हैं ? लेकिन चौटाला साहब पर उसका उल्टा असर हुआ और उन्होंने अपनी मन मर्जी की, जिसका नतीजा वे आज उधर बैठकर भुगत रहे हैं। पिछली सरकार के समय में जब पंचायत इलैक्शन हुए उस समय सरपंच बनने के लिए लोग बहुत उत्साहित थे लेकिन बाद में उनके साथ जो कुछ हुआ वह बात सबको मालूम है कि उनकी कोई अधिकारी सुनता नहीं था। किस तरह से उनके अधिकारों के साथ भेदभाव किया गया यह बात सभी को मालूम है, इस बारे में मैं अधिक जिक्र नहीं करना चाहूंगा। अब हमारी सरकार बनने के बाद सभी की बात सुनी जाती है। आम आदमी भी अपनी बात किसी अधिकारी को, विधायक को, मंत्री को बता सकता है और उसकी बात सुनी भी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चुनावों की बात आई, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय रिकार्ड मतों से जीते हैं यह सब इसीलिए हुआ है कि वे आम जनता में लोकप्रिय हैं। उनका रिकार्ड आने वाले समय में भी नहीं टूटेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाली सरकार के समय में जब वे लोग रैली करते थे तो आम लोगों की गाड़ियां दो-तीन दिन पहले ही रैलियों में ले जाने के लिए पकड़ ली जाती थी और आम जनता इससे बहुत परेशान थी लेकिन हमारी सरकार के समय में अभी 14 तारीख को रैली की गई थी, किसी की भी गाड़ी नहीं पकड़ी गई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं भूमि अधिग्रहण के बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि गुड़गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रति एकड़ जो 15 लाख रुपये का मुआवजा सरकार ने तय किया है यह बहुत कम है। इस बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गुड़गांव के अंदर रैजीडैंशियल और इण्डस्ट्रियल एरियाज में तो एक-एक, दो-दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ लैंड का रेट है और सरकार की तरफ से वहां 15 लाख रुपये मुआवजा प्रति एकड़ दिया जाये यह ठीक नहीं है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि गुड़गांव में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाव तय किया जाये। जहां मार्किट रेट ज्यादा है वहां ज्यादा मुआवजा दिया जाये। सरकार द्वारा इस पर दोबारा से विचार किया जाये। इसके अतिरिक्त जो सैक्शन 4,6 और 9 के तहत भूमि अधिग्रहण की जाती है उसमें तीन-तीन साल लग जाते हैं जिस कारण किसान को भी पैसा काफी समय बाद मिलता है इसलिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जाये कि भूमि अधिग्रहण मार्किट रेट पर हो और साथ ही साथ किसानों को पैसा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं

एस०वाई०एल० नहर के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज के दिन पंजाब में, हरियाणा में और सैंटर में तीनों जगह पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं इसलिए एस०वाई०एल० के मुद्दे को अब हल करने का अच्छा अवसर है। यदि यह मुद्दा अब भी हल नहीं हुआ तो फिर कभी हल नहीं होगा। इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लें और इसे जल्दी से जल्दी हल करवायें यह मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। यह बात हमारे और हमारे प्रदेश की जनता की भलाई की है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं पेयजल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि वित्तमंत्री जी के भाषण के पेज 19 पर गुड़गांव में पेयजल की व्यवस्था का जिक्र किया है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा क्योंकि गुड़गांव में पानी की बहुत समस्या है। वहां पर हुडा के सैक्टरों में ई०डी०सी० चार्ज किया जा रहा है और लोग अपना बोर करके पानी पी रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी सैक्टर्ज में ठीक तरह से पानी नहीं पहुंच रहा। उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में पौपुलेशन बढ़ रही है इसलिए वहां पर बिजली और पानी की व्यवस्था की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था बहुत कमजोर है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है उसे और बढ़ाना बहुत जरूरी है इसमें और सुधार करना चाहिए ताकि लोगों को भविष्य में पीने का पानी मिल सके। हुडा की तरफ से या गवर्नमैंट की तरफ से लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। सैक्टरों में पीने के पानी का बहुत ज्यादा अभाव है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मॉडल स्कूल खोलने की बात कही गई है। मैं गवर्नमैंट की इस बात को मानता हूं कि ठीक है कि 18 स्कूल खोले हैं इसके बावजूद हरियाणा में 20 जिले हैं इसलिए दो स्कूल और भी खोले जाने हैं। पता नहीं वह दो अभागे जिले कौन से हैं। जिनका इसमें नम्बर नहीं पड़ा। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि जैसे गुड़गांव की पौपुलेशन बढ़ रही है और इसके साथ ही हमारी लड़कियों में शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। हमारी लड़कियां पढ़ने के लिए शहर में नहीं आ सकती हैं। अभी मैं एक ताजा उदाहरण यहां पर बताऊंगा, हमारे यहां पर बादशाह काण्ड हुआ था। एक लड़की ऐग्जाम देने गई और उस लड़की को दो लड़कों ने पकड़ कर पॉयजन पिला दिया। बड़ी मुश्किल से उस लड़की की जान बची। आप यह मानकर चलें कि बाहर के बहुत से लोग यहां पर आ चुके हैं और गुड़गांव की पौपुलेशन बढ़ रही है। उसके लिए हमारे रूरल एरिया में अलग से कॉलेज होना चाहिए। इस बारे में मैंने डिमाण्ड भी की है कि हमारे भौंडसी, दमदमा या बादशाह के बीच कहीं पर भी जगह दी जाए जहां हमारे लोकल बच्चे पढ़ सकें। हमारे यहां पर आज शहर में आना गुनाह हो गया है और हमारे बच्चे शहर में नहीं आ सकते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी पौपुलेशन बढ़ रही है वहां पर एक कॉलेज का प्रावधान किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं बजट भाषण के क्रम सं० 24 का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें सरकार ने और माननीय वित्त मन्त्री जी ने 5100/-रुपये की बजाय 15,000/-रुपये देने की योजना शुरू की है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक बात बड़ी आड़े आ रही है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि 15000/- रुपये की राशि किस को दी जाएगी। पिछली बार तीन दिन का विधान सभा का सैशन चला था और सब साथियों ने पीले और गुलाबी कार्डों के बारे में यहां पर बात रखी थी और सरकार से इस बारे में कुछ तय करने के लिए कहा था लेकिन वह जो पीले और गुलाबी कार्ड हैं उनमें आज भी वही की वही स्थिति बनी हुई है उसका न तो दोबारा से सर्वे हुआ है और न ही उनकी छंटनी हुई है। अगर कोई कहता है कि मैं गरीब हूं और मुझे शगुन योजना के 15000/-रुपये की राशि मिलनी चाहिए तो दुर्भाग्य की बात यह है कार्ड में फर्क आ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस

[श्री सुखबीर सिंह]

कार्ड के बारे में दोबारा से सर्वेक्षण करवा कर जो पीले और गुलाबी कार्ड हैं उनको नियमित किया जाए ताकि जो गरीब आदमी हैं उनको इसका बैनिफिट मिल सके। अगर ऐसा नहीं होता तो चाहे 15 हजार रुपये मिलें या 25 हजार रुपये अगर गरीब आदमी को पैसा नहीं मिलता तो उसका क्या फायदा है ? इसका उदाहरण मैंने दिया है और बताया है कि पीले और गुलाबी कार्ड इसमें आड़े आ रहे हैं। सरकार को इस पर दोबारा से गौर करना चाहिए और इसका सर्वेक्षण करना चाहिए और ठीक व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां तक राजस्व की बात है, 17% राजस्व बढ़ने का कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। गुड़गांव के अन्दर बोली चल रही थी हम वहां पर पहुंचे और बोली में हिस्सा लिया। पिछली सरकार के समय में ऐसा होता था कि नाम ऊपर से तय हो कर आ जाता था कि फलां आदमी के नाम पर बोली छूटेगी लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। हमारे गुड़गांव जोन हॉल में मैं खुद पहुंचा और 55 करोड़ रुपये से गुड़गांव में बोली शुरू हुई और जो वहां पर मोनोपोली थी वह हमने तोड़ी। मैंने खुद 80 करोड़ रुपये की बोली लगाई और वह ठेका सवा अट्ठासी करोड़ रुपये में छूटा था अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर फिर मोनोपोली हो जाती । आज जो 17% का बैनिफिट मिला इसका कारण यही था कि अब की बार आजादी से बोली लगी है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ । किसी पर किसी मन्त्री, वित्त मन्त्री या मुख्य मन्त्री का कोई दबाव नहीं था कि बोली फलां आदमी के नाम दी जाएगी। ओपन बोली हुई है इसलिए राजस्व बढ़ रहा है। राजस्व को बढ़ाने के लिए मैं एक और बात यहां पर कहना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय इस समय हाउस में बैठे हुए नहीं हैं लेकिन वे मेरी बात को सुन रहे होंगे। हमारे गुड़गांव के अन्दर तीन स्टोरी मकान बनते हैं और मल्टीस्टोरी मकान भी बनते हैं । तीन स्टोरी के मकानों की रजिस्ट्रियां पिछले दो साल से बन्द की हुई हैं हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है लेकिन फिर भी इनकी रजिस्ट्रियां नहीं की जा रही हैं । अगर ये रजिस्ट्रियां खोल दी जाएं तो स्टेट को इससे बहुत बैनिफिट हो सकता है। इस पर कोई कानूनी बाउंडनैस नहीं है और इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर यह रजिस्ट्रियां खोल दी जाएं तो मैं समझता हूं कि एक ही महीने के अन्दर मैं आपको फिगर दे दूंगा कि गुड़गांव तहसील में 100 करोड़ रुपये का रैवेन्यू आ जाएगा। इसमें कोई लीगल हिच नहीं है और कोई बाउंडेशन भी नहीं है, ख्वामखाह ये रजिस्ट्रियां करना पिछली सरकार ने रोक दी थीं। उपाध्यक्ष महोदय एम०एल०ए०, फलैट्स की बहुत कमी है उसको पूरा करने की बात सरकार ने कही है, यह बहुत ही अच्छी बात है। हमारे गौतम साहब तथा हमने यह रिक्वैस्ट की थी कि जहां एम०एल०ए० फ्लैट्स कम्पलीट हों वहीं एम०एल०ए० फण्ड्ज़ का होना भी बहुत जरूरी है । माननीय वित्त मन्त्री महोदय से हमने पहले भी एक बार बात कही थी और आज भी यहां पर कह रहा हूं कि एम०एल०ए० के लिए फण्ड का प्रावधान किया जाए ताकि हम अपने हल्के में किसी नाली या गली को बनवा सकें। हमें कुछ तो राईट मिलना चाहिए। पब्लिक ने हमें चुन कर भेजा है तो पब्लिक के लिए हमें इतना राईट तो होना चाहिए जिससे एम०एल०ए० को कुछ मान-सम्मान तो मिले और हम लोग कुछ काम कर सकते हों। आज हम जहां भी देखते हैं चाहे वह दिल्ली की गवर्नमैंट हो और चाहे वह पंजाब की गवर्नमैंट हो सब जगहों पर एम०एल०एज० फण्ड मिलता है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात पर गौर करेंगे और वित्त मन्त्री जी से कह कर एम०एल०ए० फण्ड शुरू किया जाए ताकि सबको मान-सम्मान मिल सके। इसके साथ ही मैं सड़कों की बाबत बात कहना चाहूंगा। गुड़गांव और नोयेडा की निस्बत आज गुड़गांव को देखा जाए तो गुड़गांव एशिया के मानचित्र पर पहले आता है इसके बावजूद भी हुडा और हमारी सरकार

की नौबत यहां तक आई हुई है कि प्राईवेट कोलोनाईजर्ज पर दबाव दिया जाता है कि वे रोड बनाएं। अगर कोई शहर के अन्दर चला जाता है, अगर वह रोड से निकल जाए तो मैं इस बात की गारण्टी लेता हूं कि छः छः फुट के खड्डे इन रोड्ज़ के अन्दर हैं। जिस सैक्टर में रोडज़ का पैसा सरकार ने चार्ज कर लिया है, ई०डी०सी० ले ली है लेकिन इसके बावजूद भी रोडज़ और लाईट की वहां व्यवस्था नहीं है जो गुड़गांव की मोनोपोली के अनुसार होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं नोएडा के बारे में कहना चाहता हूं कि आज लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं ? वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नोएडा में बहुत ही अच्छी डिवैल्पमैंट हो रही है, वहां की गवर्नमैंट वहां पर बहुत ज्यादा सुविधा दे रही है। हमारे यहां से वहां पर फैक्टरियां जा रही हैं। हमारी गवर्नमैंट को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां तक आपने मेवात रैनीवैल की बात कही है तो यह बहुत ही खुशी की बात है और वहां पर पानी की व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी यहां पर बैठे हुए हैं, हमारा और आपका कल्याण इसी में है कि यह पानी आ जाए और हमारे हिस्से का पानी हमें मिल जाए। इससे हमारे एरिया का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा और हमारा उद्धार भी हो जाएगा। यह सारा खारे पानी का एरिया है और यहां पर व्यवस्था बड़ी खराब है और हमारे लोग इस वजह से बहुत परेशान हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यहां पर जो नई उद्योग नीति की बात आई है इस बारे में मैं एक बात कहूंगा कि नई उद्योग नीति लागू की है यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन इस सबके बावजूद भी इसमें कुछ चेंजिज करने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में बहुत बड़ी औद्योगिक नीतियां आई हुई हैं और उनमें दिक्कत एक बात की आ रही है कि वहां पर हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में हम कई बार मांग भी कर चुके हैं। सी०एम० साहब से हमने इस बारे में पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं लेकिन इस सबके बावजूद भी वहां पर हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आजकल हीरो होंडा में स्ट्राईक चल रही है और इसका कारण यह है कि वहां पर 80 प्रतिशत कर्मचारी हरियाणा से बाहर के हैं। जब उन इण्डस्ट्रीज में स्ट्राईक होती है तो इण्डस्ट्री वाले हरियाणा प्रदेश पर ब्लेम लगाते हैं कि इनकी वजह से स्ट्राईक हो रही है। लेकिन जब वे भर्ती करते हैं तो वहां पर गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल आदि दूसरी स्टेट्स के लोगों को लगाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस बारे में कहा था कि यह हमारे लिए अनुकूल नहीं है कि हम उनको इस बारे में कहें कि वे हरियाणा के लोगों को नौकरी दें। यह प्राईवेट कम्पनी वालों की मर्जी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमैंट को इसमें इंटरफियर करना चाहिए। यह जो फैक्ट्रियों में स्ट्राईक हो रही है, फैक्ट्ररी वाले बार-बार यह बात उठाते हैं कि हरियाणा वाले यह स्ट्राईक कर रहे हैं और हरियाणा वाले फैक्ट्ररी नहीं चलने दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्ट्राईक का कारण यह है कि वहां पर हमारे क्षेत्र के लोग नहीं हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग तो सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत ही हैं और 80 से 85 प्रतिशत लोग तो बाहर के हैं। वे लोग आपस में न तो शर्म मानते हैं और न ही इस बात से दबते हैं कि एक एक महीने तक स्ट्राईक पर चलते हैं कई बार तो यह स्ट्राईक पांच महीने चली या ज्यादा चली। पहले स्ट्राईक मारुति उद्योग में हुई थी आज हीरो होंडा में हो रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें इन्टरफियर करके और ऐसे कोई नार्मज फिक्स करें ताकि अगर ऐसी कोई बात हो जाए तो मिल बैठकर उस बात को खत्म किया जा सके। यहां पर जो भी इण्डस्ट्रीज लगी हैं उनमें बाहर के लोग बढ़ते जा रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के लोग कम होते जा रहे हैं, इसी वजह से उन फैक्ट्रीज

[श्री सुखबीर सिंह]

में स्ट्राईक हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज के लिए और रैजिडैंशियल एरियाज़ के लिए जिस जमींदार की जमीन ली जाती है इस बारे में सरकार को कानून बनाना चाहिए, जो कि पहले कई जगहों पर था। हम यह नहीं कहते हैं उस जमीन पर अगर कोई फैक्ट्री लगे तो वहां पर उस जमींदार के बेटे को मैनेजिंग डायरैक्टर लगा दें। अगर उस घर का बच्चा चपरासी लगने के लायक है तो उसको चपरासी ही लगाया जाए और अगर उस घर का बच्चा कम्प्यूटर इंजीनियर के लायक है तो उसको कम्प्यूटर इंजीनियर ही लगाया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह जिस लायक हो उसको वही नौकरी दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए। जो आदमी सैंकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री चलाता हो उसके लिए एक आदमी को नौकरी देना कोई बड़ी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि भले ही वह आदमी कोई काम भी न करे तो भी उनको उस आदमी को 2,5 और 10 हजार रुपये सैलरी देनी भी पड़े तो कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मानेसर आज पूरे एशिया के नक्शे पर आ रहा है। अगर हम आज आई०एम०टी० में जाते हैं तो वहां पर 200 फुट चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। वह पैरिस बना हुआ है। लेकिन अगर कोई कासम जैसे गांव में चला जाए तो वह वहां पर घुस ही नहीं सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, या तो वहां पर डी०एस०आई०डी०सी० की ड्यूटी लगे, एच०एस०आई०डी०सी० की डयूटी लगे लेकिन वे गांव जो उसके अन्दर आए हुए हैं उनकी डिवैल्पमैंट होनी चाहिए। आज वे गांव ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनमें न तो सड़क है, न बिजली है, न पानी है और न ही सीवरेज है। उपाध्यक्ष महोदय, उन गांवों की डिवैल्पमैंट होनी चाहिए। जिन कालोनाइजर्ज के अन्दर जो गांव आते हैं उनको ही उन गांवों की डिवैल्पमैंट करनी चाहिए। पीछे जब चौधरी बंसी लाल जी की गवर्नमैंट थी तो उन्होंने शीतला माता के मन्दिर का उद्धार करवाया था गेट बनाए थे और सभी को बुलाकर वहां पर काम करने की ड्यूटी लगा दी थी। इसी तरह से रिहायशी कालोनिज़ के अन्दर जो गांव आए हुए हैं उन सब गांवों की डिवैल्पमैंट प्राईवेट कालोनाईजर करवाता है। आज जो हीरो होंडा जैसी कम्पनी है, वह एक मुफ्त में स्कूल चला रही है और उसने एक अस्पताल भी बना रखा है लेकिन गुड़गांव जैसे एरिया में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। वहां पर ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पर हमारी वीकनैस है। वहां पर इन्डस्ट्री वाले एक नये पैसे का डोनेशन नहीं देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गवर्नमैंट से कहना चाहूंगा कि वे बड़े बड़े इंडस्ट्रिलिस्टस को बुलाएं और उनसे यह कहें कि वे गुड़गांव को टेक ओवर कर लें ताकि वहां की डिवैल्पमैंट हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, क्षेत्र के उद्योगों के अनुसार जो रोजगार की बात की है वह अच्छी बात है लेकिन हमारे फाईनैंस मिनिस्टर इलैक्शन से पहले बार-बार कहते थे कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा लेकिन मेरे ख्याल में आज वह बात दबती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और बुजुर्गों को पैंशन देने के लिए दोबारा से सर्वेक्षण किया जाए। यह सर्वेक्षण ठीक ढंग से किया जाए ताकि इसका सबको बैनीफिट मिल सके। इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री हैं जैसे आई०एम०टी० मानेसर हैं इस तरह की इंडस्ट्री को पीछे किया जा रहा है क्योंकि न तो वहां बिजली है, न वहां पानी है और न ही वहां पर दूसरी फैसिलिटीज हैं। हालांकि उसको बैकवर्ड इलाका बनाया हुआ है लेकिन फिर भी वहां सुविधायें नहीं दी गयी हैं। अभी आधे घंटे पहले इस बात पर बहस हो रही थी लेकिन इस पर बोलने के लिए टाईम नहीं दिया जा रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आई०एम०टी० मानेसर लगी तो है लेकिन वहां पर सुविधा नहीं है। कहां भिवाड़ी, कहां जयपुर और कहां नीमराणा लेकिन

इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने इनको स्पेशल छूट दी है अगर आप भी इसी तरह की छूट इंडस्ट्रीज को देंगे तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे यहां पर इंडस्ट्री न लगे। अगर कोई छूट इनको नहीं दी जाएगी तो कोई भी आदमी अपनी इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं होगा। वह कहेंगे कि हम क्यूं यहां पर आएं क्योंकि जब सारी चीजें उनको वहां पर मिल जाती हैं तो वे यहां पर क्यों आएंगे। इसलिए अगर आप पाटली एरिया अपने यहां पर डिवैल्प करना चाहते हैं तो इनके लिए आपको अलग से सबसिडी देनी पड़ेगी ताकि यहां पर भी इंडस्ट्रीज लग सकें।

श्री उपाध्यक्ष : सुखबीर जी, अब आप वाईंड अप करें।

श्री सुखबीर सिंह सोहना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। अब मैं स्वास्थ्य सेवा के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी मंत्री महोदया बैठी हुई हैं । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वे एक बात पर ध्यान दें कि जिस हिसाब से आज पौपुलेशन बढ़ रही है उसको देखते हुए हमारे यहां पर भी एम्स जैसा होस्पीटल बनना चाहिए। अगर आज कोई आदमी बीमार होता है तो उसको सीधा एम्स में भर्ती करवाना पड़ता है इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस हिसाब से आज डिवैल्पमैंट हो रही है उसको देखते हुए एम्स जैसे होस्पीटल की बहुत जरूरत है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से कहूंगा कि हमारे एरिया में एम्स जैसा होस्पीटल बनना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इस बार हुई है उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अब से पहले चाहे पिछली सरकार रही हो या उससे पहले की सरकार रही हो, नगरपालिका, नगरपरिषद या ब्लॉक समिति के चेयरमैन वगैरह के नाम यहां से थोपे जाते थे कि जाओ उस नाम के आदमी को चेयरमैन और उप चेयरमैन बना दो लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ । अब की बार बहुत बढ़िया बात हुई है। सी०एम० साहब ने कहीं कोई इंटरफियर नहीं की है। उन्होंने कहा कि जिस आदमी को पब्लिक ने चुनकर भेजा हैं उन्हीं नुमाइन्दों में से जो आदमी काबिल हो उसको आप अपने आप चुनो। जिसको मैम्बर्ज स्पोर्ट करते हैं उसको आप चुनो। कोई भी नाम किसी पर थोपा नहीं गया है जबकि पिछली बार यह होता था कि यहां से नाम थोप दिया जाता था कि फलां आदमी को बना दो चाहे वह काबिल है या नहीं है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं सरकार को भी और खास तौर पर मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। आज आम जनता में भी इस बात की चर्चा है कि यह बात मानने वाली है कि इस बार कोई नाम थोपा नहीं गया है। मुख्यमंत्री महोदय ने सब जगहों पर कहा है कि जो भी काबिल आदमी हो उसको ही चुने। मेरी तरफ से कोई नाम नहीं है और मैं कोई इंटरफियर भी नहीं करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो काम सरकार ने किया है इसका पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप वाईंड अप करें।

श्री सुखबीर सिंह सोहना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। इसी तरह से अम्बेडकर और बाल्मिकी आवास योजना के बारे में कहा गया है लेकिन इसकी डिटेल नहीं दी गयी है सिर्फ कोड वर्ड में इस बारे में लिखा गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका खुलासा किया जाए। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन गरीब आदमियों को क्या मिलेगा। इसलिए इस बारे में डिटेल इंफोर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो मेरी मेन बात थी उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि रेजीडैंशियल कालोनाईजेशन में और इंडस्ट्रियल कालोनाईजेशन में वीकर सैक्शन के लिए कोटा होता है। नम्बर ऑफ प्लाट्स नम्बर ऑफ फ्लैट्स में इनका बीस परसैंट कोटा होता है

[श्री सुखबीर सिंह]

और यह बीस परसैंट कोटा ड्रा से निकाला जाता है। इसी तरह से हुडा के भी हर जिले में जो प्लाट्स होते हैं इनका भी ड्रा निकाला जाता है मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि इस बारे में कोई ऐसे नार्म्ज अवश्य तय होने चाहिएं कि इनका बैनीफिट हरियाणा प्रदेश के आदमियों को ही मिले। चाहे तो यह डौमिसाइल के द्वारा या ड्रा के द्वारा डिसाईड कर दिया जाए। ई०डब्ल्यू०एस० के लिए जो 60 गज के प्लाट्स होते हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वह केवल 6 हजार रुपये में मिलते हैं और इनको लेने के लिए वे लोग ऐप्लाई करते हैं जो 6 महीने पहले ही हरियाणा में आकर बसते हैं। दूसरे स्टेट से आने वालों के राशन कार्ड बन जाते हैं और वे इनको लेने के लिए एप्लाई करते हैं। वे इनके लिए केवल 6 हजार रुपये जमा करवाते हैं और जब बाहर निकलकर आते हैं तो वे इनको दस लाख रुपये का बेचकर चले जाते हैं। पिछली बार भी हुडा के प्लाट्स इसी तरह से सेल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़गांव में सैक्टर 57 में चार हजार रुपये गज का रेट प्लाट्स का रखा गया था लोगों के प्लाट्स निकले लेकिन उन्होंने ये प्लाट्स बीस बीस या तीस तीस लाख रुपये में प्रोपर्टी डीलर्ज को बेच दिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि वीकर सैक्शन के बारे में तो सरकार को अवश्य कोई न कोई नार्म्ज इस बारे में बनाने चाहिएं कि यह बैनीफिट हरियाणा प्रदेश के लोगों को ही मिले। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो हमारा खदान का एरिया है उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट से सरकार को कोई न कोई बात जरूर करनी चाहिए। इसी तरह से वनरोपण की बात है इसका एरिया भी तय कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज वनरोपण तो हो नहीं रहा है बल्कि कटिंग बहुत जोर से चल रही है इसलिए इस बारे में भी नार्म्ज तय किए जाने चाहिएं। अगर खदान के बारे में सरकार कुछ कर दे तो अच्छा रहेगा क्योंकि दक्षिणी हरियाणा इस समस्या से ज्यादा ग्रस्त है। यह बैन जब तक नहीं खुल पाएगा तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारी सरकार को इस बारे में तय करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में डायरैक्शन आ जाए कि इस एरिया में वनरोपण होगा और इस एरिया में माइनिंग होगी तब यह उद्धार हो सकता है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : सुखबीर जी, अब आप बैठें। अब श्रीमती प्रसन्नी देवी जी बोलेंगी।

श्री उदय भान: उपाध्यक्ष महोदय, इनके बोलने से पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा यह कहना है कि इतनी सीरियस डिसक्शन बजट पर चल रही है और यहां सदन में न तो मुख्यमंत्री जी हैं, न वित्तमंत्री जी हैं, न पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर हैं और न यहां अधिकारी बैठे हुए हैं। यह इम्पोर्टैंट मसला है, उनको यहां बैठना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिए। प्रसन्नी जी, अब आप बोलें।

श्रीमती प्रसन्नी देवी (नौलथा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसको बहुत शानदार और प्रत्येक वर्ग का बजट मान कर चल सकते हैं इसमें हर वर्ग को सभी किस्म की सुविधा दी गई है । बहुत सारी ऐसी चीजें रखी गई हैं जिनसे कई साल से पीछे थे। नहरी पानी टेल तक पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। पानी न होने की वजह से खेती खराब हो रही थी। पिछली सरकार के समय में कोई बोल नहीं सकता था और कोई अपने मन की बात नहीं कह सकता था। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने सभी हल्कों में सुविधाओं का समान रूप से वितरण कर दिया है। सभी जगह टेलों पर पानी पहुंच रहा है और अब किसी के साथ कोई

भेदभाव नहीं हो रहा है, यह एक सराहनीय काम है। ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म की गई है। को-ऑपरेटिव बैंक हैं उसकी ब्याज दर भी कम की गई है। गन्ने के मूल्य के लिए किसान कई कई साल तक पीछे फिरते थे उन सबकी पेमेन्ट कर दी है ताकि किसानों को अपना काम करने में सहूलियत मिले। किसान अन्नदाता है, सबके लिए अन्न पैदा करता है उसको सहूलियत दी जाए तो उसको अन्न ज्यादा पैदा करने में दिक्कत नहीं आती । पिछली सरकार तो बहुत ही काम करने का दावा करती, थी, किन्तु सुबह कोई घर से निकलता था उसका कोई निश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस आएगा या नहीं। हरियाणा प्रदेश आज के दिन बिल्कुल भयमुक्त है इसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। पीछे जब हमारी सरकार थी तो रजबाहों के फाउंडेशन स्टोन रखने का काम शुरू किया गया था। चौटाला जी की सरकार जो किसान हितैषी का ढिंढोरा पीटती थी उसने वे सारे पत्थर हटवाकर उन पर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला नाम लिखवा दिए। एकाध रजबाहा बनवाया भी लेकिन ज्यादातर नहीं बनवाए। इरीगेशन मिनिस्टर साहब यहां बैठे नहीं है मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि जो रजबाहे शुरू हुए थे और नहीं बन सके, उसके लिए कोई कमेटी गठित की जाए जो यह देखे कि जहां पूरे तरीके से पानी नहीं पहुंच रहा वहां पानी कैसे पहुंचाया जाए जिससे किसानों को पानी मिल सके। वहां के हालात ऐसे हैं कि वहां ऊंची-नीची जमीन होने के कारण पानी नहीं पहुंच पाता । कुछ स्कीम यमुना पर बांध बनाकर बारिश के दिनों में कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला के लिए तैयार की गई थी लेकिन वे स्कीम ऐसी की ऐसी धरी हैं उसके बाद कई सरकारें आई लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए। एक बात के लिए हरियाणा की जनता बधाई की पात्र है कि उसने एक ऐसी सरकार को बहुत मार्जिन के साथ चुनकर भेजा है जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। वहीं मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई देती हूं कि उनकी रहनुमाई में एक बहुत अच्छी सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो हमारा गरीब तबका है, हरिजन भाई हैं पिछड़ा वर्ग है जिनके पास जमीन नहीं है उनकी जो कई समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। जिनको पैंशन मिलनी चाहिए उनको पैंशन नहीं मिल रही है। पिछली सरकार के समय में जो 40 साल के लोग थे उनको तो पैंशन मिल रही थी और जो गरीब हरिजन और पिछड़ा वर्ग है उनको जो 70-80 साल के आदमी थे उनको पैंशन नहीं मिल रही थी। गरीबी-रेखा के नीचे रहने वालों का भी यही हाल है। सहूलियत बहुत दी गई है लेकिन कार्ड सिस्टम ठीक से नहीं बनाया गया जिस कारण वे उसका ठीक से लाभ नहीं उठा सके। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहती हूं कि इसके लिए सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सर्वे करवाया जाये। बल्कि सरकार को मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस बारे में अधिकारियों को समय दिया जाये कि इतने दिन में वे सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट दें ताकि इस स्कीम से गरीब आदमी फायदा उठा सकें। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर सर, बजट में बहुत सारी सहूलियतें हर वर्ग को दी गई हैं लेकिन मैं गरीब आदमियों के लिए और जो हरिजन और पिछड़ा वर्ग है उनकी चौपालों के बारे में एक बात कहना चाहूंगी कि गरीब आदमी के पास अपनी जमीन नहीं होती, उनके पास अपना साधन नहीं होता तो वे कहां से अपनी चौपाल बनायेंगे। नई चौपाल, अधूरी चौपाल, चौपाल की मरम्मत आदि कई बातें हैं, इनके लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि बजट में इसके लिए अच्छा पैसा देकर उन गरीब आदमियों की चौपाल बनाने का काम किया जाये और उनको इस सुविधा का लाभ दिया जाये। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर सर, पहले हमारी सरकार ने गरीब आदमी को पंचायत के छोटे-छोटे

[श्रीमती प्रसन्नी देवी]

प्लाट दिए थे। क्योंकि जिस आदमी के पास खेती की जमीन नहीं है तो वह घर की जमीन कहां से लायेगा। परन्तु अब परिवार बढ़ गये हैं एक परिवार के कई-कई परिवार हो गये हैं इसलिए कोई पौलिसी बनाकर इन गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लाट देने चाहिए। क्योंकि पंचायत की 4-5 एकड़ जमीन में से कई घरों को प्लाट दिए जा सकते हैं और कई घरों का भला हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहती हूं कि गरीब आदमियों को प्लांट की सुविधा जितनी जल्दी हो सके देनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं को नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि महिलाएं जितनी जटिल काम की ड्यूटी दे सकती हैं और जितनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभाती हैं, वह आप सभी जानते हैं। महिलाओं को जो तीसरा हिस्सा दिया गया है इससे महिलाओं को लाभ होगा, इसके अलावा मैं स्कूलों की बात करना चाहूंगी । स्कूल बहुत से अपग्रेडिड भी हैं और बहुत जगह अपग्रेड करने की भी जरूरत है लेकिन हमको महिलाओं के लिए मिडल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी स्तर के कुछ स्कूल खोलने होंगें। कुछ सर्वे करवा कर कि जिस एरिया में इनकी जरूरत है वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्कूल खोले जाएं। सरकारी स्कूल वैसे तो तकरीबन हर जिले में हैं लेकिन कई जगह अब भी नहीं है। महिलाओं के लिए सरकार को एक-एक कालेज हर जगह खोलना चाहिए। कई जिलों में तो महिलाओं के लिए कालेज हैं, जहां नहीं हैं वहां एक-एक सरकारी कालेज महिलाओं के लिए खोलना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठी नहीं हैं। स्वास्थ्य के बारे में इस बजट में अच्छी सुविधाएं दी गई हैं लेकिन मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि जहां हम एक ब्लाक में स्वास्थ्य के लिए एक पी०एच०सी० खोलते हैं वहीं हमको इस चीज पर अपने डिपार्टमैंट की कोई कमेटी बनाकर इसका कोई तरीका निकालना चाहिए कि हम किस तरीके से इन पी०एच०सीज० की संख्या में बढ़ोतरी करके लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर सकते हैं क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और नार्म्ज अभी वहीं के वहीं हैं। कोई डाक्टर गांव में टिकने के लिए तैयार नहीं है इसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी चाहिए कि जो डाक्टर 2-3 साल गांव में सर्विस करेगा उसी को सिलैक्ट करेंगे तभी गांव वालों का कुछ कल्याण होगा नहीं तो पी०एच०सीज० खोलने के बावजूद भी बहुत बुरा हाल होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य कैम्प लगाए जाएं तो उससे बहुत लाभ मिल सकता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हर आदमी होस्पिटल में आकर नहीं दिखा सकता और वह बीमारियां पलती रहती हैं। इन कैम्पों से मैंने अपने समय में महसूस किया था। छोटे-छोटे बच्चे हार्ट पेशेंट हैं जिनका हम अन्दाजा नहीं लगा सकते। वैसे तो पिछले दिनों हैल्थ कैम्प लगे थे लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इन हैल्थ कैम्पों की तादाद जितनी बढ़ाई जा सकती हो उतनी ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूं, सरकार ने बजट में सुविधाएं तो बहुत ज्यादा दी हैं। हर डिपार्टमैंट में हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं और कोई कमी नहीं छोड़ी गई। हमारे अधिकारी भी थोड़े उसी ढर्रे के बने हुए हैं इसलिए हमें थोड़ी इन अधिकारियों के साथ सख्ती करनी पड़ेगी उनको किसी भी काम के लिए जब तक सरकार टाईम बाउंड नहीं करेगी तब तक उनका ध्यान उस काम की ओर नहीं जाता । हमें आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण और सरकार जिस तरह से हर काम को लेकर चले हैं, उसको पूरा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 100 दिन का जो सरकार का प्रोग्राम आया है वह बहुत अच्छा प्रोग्राम आया है। थोड़े दिनों में ही

लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वे काल-कोठरी से निकल कर आए हों। आज अपोजिशन के भाई बड़ी-बड़ी बातें लेकर आगे आते हैं । उस समय एक बाप और 2 बेटे यानि इन 3 के सिवाय कोई बोल नहीं पाता था, बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, बोलते कहां से आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं । कितने लोगों को इन्होंने सर्विस से निकाल दिया और कितने लोग सर्विस के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं, कितने पहले निकाल दिए और कितने पद नए भरने की कोशिश की गई । हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार का जो प्रोग्राम तय किया है, वह सराहनीय है। उपाध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई के लिए बजट तो काफी रखा गया है लेकिन वाटर सप्लाई की हालत काफी अर्से से खराब पड़ी है। हर गांव में इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, विशेष तौर से जो गरीब आदमी हैं, हरिजन, पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो अपनी लाइन बिछाकर अपने मोहल्ले में पानी नहीं ले जा सकते उनको प्रायोरिटी के साथ पानी उपलब्ध करवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि गांवों में महिलाओं को शौचालयों की बड़ी भारी दिक्कत हैं। आज न जंगल हैं और न बणी हैं। गरीब आदमी जिसके पास खेत की जगह नहीं है और जिसके पास रहने की पूरी जगह नहीं है उन महिलाओं को बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए चाहे बजट में बढ़ोत्तरी करनी पड़े लेकिन हर गांव में महिलाओं के लिए शौचालय बनाये जायें। विशेषतौर से जो गरीब परिवार हैं जो एक-एक कमरे के मकान में रहते हैं जो अपने लिए शौचालय नहीं बना सकते उनके लिए तो शौचालय हर गांव में अवश्य बनाये जायें। जिनके पास पैसा है वे तो अपने आप भी बनवा लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार के समय में पंचायत समिति, जिला परिषद और तीन बाई इलैक्शन हुए और ये सभी इलैक्शन ईमानदारी से हुए। इन इलैक्शनों में महिलाओं के लिए जितनी रिजर्वेशन थी उससे अधिक सीटें मिली और जो महिलाएं जीतकर आई हैं उनमें काम करने का पूरा उत्साह है। पंचायती राज का जो ढांचा है उसमें महिलाओं को इतना अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा यह कभी महिलाओं ने सोचा भी नहीं होगा। खासतौर से गरीब वर्ग की महिलाओं ने तो बिलकुल भी नहीं सोचा होगा लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी की नीति के कारण आज महिलाओं को पंचायती राज में पूरी भागीदारी मिल रही है और इसके लिए हम सदा स्वर्गीय राजीव गांधी जी के आभारी रहेंगे। पहले एक आध महिला को पंचायती राज में भागीदारी मिलती थी और कोई महिला सरपंच, जिला परिषद की अध्यक्ष बनने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी और शहर के हिसाब-किताब में भी कोई महिला नहीं सोच सकती थी कि वह चेयरमैन बन सकती है लेकिन पंचायती राज के जरिये स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उनके सपने को पूरा किया है और हम भी आगे उसे पूरा करते जा रहे हैं। यदि उनकी इस नीति पर हम पूरी तरह से कार्य करेंगे तो इससे महिलाओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और हमारी बहनों को काम करने का पूरा अवसर भी मिलेगा। पंचायती राज में महिलाओं की जितनी अधिक भागीदारी होगी उतना ही समाज के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि महिलाएं तो पंचायत में बैठकर काम करती हैं और आदमी तो शराब आदि पीते हैं और शराब पीकर पूरी तरह से काम भी नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहूंगी कि सड़कों के लिए बजट में बहुत पैसा रखा गया है। लेकिन बहुत सी जगहों पर सड़कों की हालत खराब है उनको ठीक करने के लिए यदि बजट में पैसे की बढ़ोत्तरी करनी पड़े तो वह की जाये। मैं चाहती हूं कि सभी सड़कों का सर्वे कराया जाये और जो सड़कें टूटी हुई हैं उन्हें ठीक कराया जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहती हूं कि जो लोग दूर डेरों में रहते हैं जहां पर सड़क की सुविधा नहीं है उनका भी सर्वे कराया जाये और उनके लिए भी सड़कें बनाई जायें, क्योंकि प्रजातंत्र में सबको पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिएं, यह सबका अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब छोटी-

[श्रीमती प्रसन्नी देवी]

छोटी बातें हैं इनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और आम आदमियों की ये मूलभूत जरूरतें हैं इन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। ट्रांस्पोर्ट के बारे में मेरे किसी भाई ने भी जिक्र किया, मैं भी इस बारे में कहना चाहूंगी कि जो प्राईवेट बसें गांवों के रूट्स पर लगाई हुई हैं वे दूसरी बुकिंग कर लेती हैं और गांवों में सवारी लेने नहीं जाती । इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि जहां पर प्राईवेट बसों को परमिट दे रखा है वहां पर सरकारी बस भी चलनी चाहिएं ताकि लोगों को परेशानी न हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्राईवेट बस वाले भी समय पर आयेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये सब छोटी-छोटी बातें हैं मैं चाहूंगी कि इस तरह की कमियां हर विभाग में हैं। सभी विभाग अपनी सब कमेटी बनायें और इस तरह की कमियों का ये सर्वे करके उनको दूर करें। ऐसा करने से आम आदमी की परेशानी दूर होगी तथा वे और भी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। आज थोड़े दिन के हमारे शासन में ऐसा लगता है कि रामराज आ गया । यदि हम इन छोटी-छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे तो लोग और भी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि वित्तमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट सदन में पेश किया है इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वित्तमंत्री जी को और सरकार के सभी मंत्रियों को बधाई देती हूं कि इस बजट में सभी वर्गों को सुविधाएं दी गई हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सोमवीर सिंह (लोहारू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया। इस सरकार को बने हुए अभी करीब सवा तीन महीने ही हुए हैं और इस सवा तीन महीने के अरसे के दौरान तीन चुनाव हुए हैं। पहले पंचायतों के चुनाव हुए, फिर म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव हुए और फिर उसके बाद अभी तीन बाई-इलैक्शन हुए हैं। इस थोड़े से अरसे के दौरान इस सरकार ने जो थोड़े से काम किए हैं और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें हर वर्ग का विशेषतौर पर ध्यान रखा गया है। सिर्फ 51.68 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। किसानों की भलाई के लिए खासतौर पर सरकार ने जो काम किये हैं उनका माननीय वित्त मन्त्री जी ने जिक्र किया है। पिछली सरकार के समय में किसानों की भलाई का ढिंढोरा तो खूब पीटा जाता था और उनकी भलाई के लिए बड़े लोभ और लालच भी दिए गए थे कि बिजली माफ होगी और दूसरे नारे दिए गये थे लेकिन उस सरकार ने किसानों की भलाई के बदले उन पर मुकद्दमें दर्ज करवाये थे।यहां तक कि किसानों के खिलाफ देशद्रोह तक के मुकदमें चलाए गए थे। इस सरकार के बनने के साथ ही जिन किसानों के ऊपर आन्दोलन के समय मुकदमें बनाए गए थे वे सभी के सभी वापिस ले लिये गये। इस सरकार के बनते ही प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई और बरसात से खेती को नुकसान हुआ। सरकार ने तुरन्त उसी समय स्पैशल गिरदावरी करवाई और किसानों को नुकसान का मुआवजा भी दिया। गेहूं का 50% तथा दूसरी फसलों का 25% मुआवजा बढ़ाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में करीब एक साल पहले जो मुआवजा बांटा गया था उसके बारे अखबारों के अन्दर भी बहुत से साथियों ने पढ़ा होगा कि लोगों को 2-2 और 10-10 रुपये का मुआवजा दिया गया था। इतना कम मुआवजा देने के कारण उस समय की सरकार की बहुत बदनामी हुई थी और उसके बाद उस सरकार द्वारा यह आर्डर्ज दिए गये थे कि 100 रुपये से कम मुआवजा किसी को नहीं बांटा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि जहां उस सरकार ने 2-2 रुपये का मुआवजा

बांटा वहीं पर इस सरकार ने बनते ही गेहूं को हुए नुकसान का मुआवजा 50% तक बढ़ाया है। इसी प्रकार से सरसों की खेती पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले करीब अढ़ाई महीने से सरसों की खरीद की गई है और पूरा 1700/- रुपये क्विंटल का रेट किसानों को दिया गया है। इसी प्रकार से को-आपरेटिव सोसाइटीज के ब्याज की बात है। हमारे यहां पर जो रेट ऑफ इन्ट्रैस्ट है वह दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में काफी कम है। 50 हजार रुपये का जो लोन है उस पर 1% रेट ऑफ इन्ट्रैस्ट कम किया गया है। जहां पर पहले 11% रेट ऑफ इन्ट्रैस्ट लगता था वहां 10% रेट ऑफ इन्ट्रैस्ट किया गया है और 50 हजार रुपये तक के लोन पर रेट ऑफ इन्ट्रैस्ट 8% किया गया है। ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन पहले चौधरी देवी लाल जी के समय में माफ की गई थी लेकिन चौटाला साहब की सरकार ने उसको बढ़ाते-बढ़ाते करीब 1500/- रुपये तक बढ़ा दिया था। इस सरकार ने बनते ही ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है। खाद पर टैक्स माफ किया गया है। इसी प्रकार से किसानों की जमीन जो पब्लिक इंट्रैस्ट के लिए ऐक्वायर कर ली जाती थी और उसके मुआवजे के लिए किसान कोर्टों में मुकदमे चलाते थे परन्तु इस सरकार ने बनते ही तय किया है और इसके लिए तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं। गुड़गांव के आस-पास जो जमीन ऐक्वायर की जाएगी उसके लिए 15 लाख रुपये दिये जाएंगे, चण्डीगढ़ और पंचकूला की पैरीफरी के अन्दर जो जमीन ऐक्वायर की जाएगी उसके लिए साढे बारह लाख रुपये और बाकी हरियाणा के अन्दर कहीं पर भी जमीन ऐक्वायर की जाएगी, उसका पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के इस फैसले से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इसी प्रकार से को-आपरेटिव शूगर मिल्ज हैं उनकी पूरी पेमेंट किसानों को दे दी गई है। इसी प्रकार से शूगर मिल के अन्दर तथा को-आपरेटिव सैक्टर में शॉप्स खोली गई हैं जहां पर उचित कीमत पर अच्छी क्वालिटी का सामान लोगों को दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पानी की बात है, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि पानी के बंटवारे में भेदभाव होता रहा है और विशेषतौर पर दक्षिणी हरियाणा के साथ पानी के बंटवारे में भेदभाव हो रहा था लेकिन इस सरकार ने बनने के साथ ही इस बात का फैसला किया है कि पानी का समान बंटवारा करेंगे। तीन चार जिलों को छोड़कर हरियाणा के सभी जिलों को इसका लाभ होगा। हांसी ब्रान्च और भाखड़ा मेन ब्रान्च को जोड़ने के लिए अलग से एक कैनाल बनाई जा रही है जिस पर करीब अढ़ाई करोड़ रुपये की लागत आएगी और इस कैनाल के बनने के बाद दक्षिणी हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस बात के लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सिवानी कैनाल सिस्टम है, सिवानी लिफ्ट इरिगेशन है वहां पर पहले 40 दिन में आठ दिन पानी आता था अब 32 दिन के अन्दर उसमें 24 दिन पानी आता है। पहले वहां पर 24 दिन में 8 दिन पानी मिलता था अब 24 में 16 दिन पानी इस एरिया में आ रहा है जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले यहां पर सिंचाई के लिए पानी की बात तो छोड़िए, पीने के पानी की समस्या रहती थी। इसी तरह से जो लिफ्ट इरिगेशन पम्पस हैं, जो कि बहुत सालों से लगे हुए हैं वे कमजोर हो गए हैं क्योंकि पिछली सरकारों के वक्त में उनकी देखरेख पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इस बजट में इस बात के लिए भी प्रावधान रखा गया है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। एस0वाई0एल0 के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है ताकि अपने हिस्से का पानी कोर्ट से प्राप्त कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं कि ये नैशनल हाईवे नम्बर 2, 4 और 6 को पैरीफेरी ऐक्ट के तहत बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा पहले एम०एल०एज० को एम०एल०ए० होस्टल में जगह नहीं मिलती थी और उनको

[श्री सोमवीर सिंह]

बाहर जगह लेकर रहना पड़ता था इस कमी को दूर करने के लिए नए एम०एल०एज० फलैट्स बनाए जाएंगे इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा गवर्नमैंट को जमीन दिल्ली में नहीं दी जा रही थी और इस सरकार ने उस जमीन को अपने कब्जे में लिया है और उस पर रैस्ट हाउस बनाने जा रही है यह भी बहुत सराहनीय कार्य है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है। जिसमें यह जिक्र किया गया है कि आने वाले 10 सालों में 2000 करोड़ रुपये की इन्वैस्टमैंट की जाएगी और उन उद्योगों में हरियाणा के 10,000 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। जिस तरह से मानेसर को डिवैल्प किया गया है उसी तरह से दो और जगहों को डिवैल्प किया जाएगा। इसी तरह से बजट में बिजली के क्षेत्र का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से पिछले दिनों बिजली की समस्या थी और जमीदार लोग बिजली के बिल जमा नहीं करवाते थे जिसकी वजह से उन पर मुकदमें दर्ज होते थे। इस सरकार ने आते ही उनकी उस समस्या को दूर किया है इसके अलावा हमारी सरकार सौर ऊर्जा प्राप्त करने के बारे में विचार कर रही है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है । हिमाचल से बिजली लेने का प्रावधान किया जा रहा है। आज हरियाणा में जमीदारों को 8 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं इसके लिए इस सरकार का और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। यह सरकार अस्पतालों के आधुनिकीकरण करने के बारे में और उनकी स्थिति को सुधारने के बारे में कोशिश कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं परिवहन व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं कि परिवहन के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है। मंत्री जी ने पहले भी यात्रियों को सुविधा देने के लिए घोषणाएं कर रखी हैं। बस स्टैण्डज़ को साफ सुथरा रखने के लिए, यात्रियों को पीने के पानी की सुविधा के लिए और शौचालयों को साफ सुथरा रखने की घोषणा की हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत सी बाते हैं और मैं उनके बारे में कहने लगूं तो वे बातें खत्म ही नहीं होंगी। अब मैं महिलाओं के बारे कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने विशेष तौर पर महिलाओं के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए हैं। जींद के अन्दर इन्दिरा गांधी के नाम पर कॉलेज खोला जा रहा है। औरतों के लिए बैंक खोला जा रहा है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही इम्पलाई होंगी। इसके अलावा जो जे०बी०टी० की भर्ती की जाएगी उसमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता सेनानियों की पैंशन 1400 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये मासिक कर दी गई है। इसी तरह से जो लड़कों और लड़कियों में लिंग भेद है, उसको भी खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर किसी के दूसरी लड़की होती है। तो उस लड़की के मां-बाप के खाते में 5000 हजार रुपये जमा करवाने का प्रावधान हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मेरी कांस्टीचुएंसी की बात करना चाहता हूं। यहां पर उप-मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूं कि 1973 में मसूरी में एकांत नामक टूरिस्ट कम्पलैक्स को पी०डब्ल्यू०डी० को दिया गया था और जिसकी 9 बीघा जमीन है। पिछली सरकार ने उसकी नीलामी के लिए कागजात तैयार करवाए थे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर विशेष गौर करें क्योंकि मुझे इस बात का पता लगा है कि अभी भी उस जमीन को और उस रैस्ट हाउस को नीलाम करने के लिए डेट रखी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि वह बहुत अच्छा रैस्ट हाउस है पुराने समय में इसको खरीदा गया था। अगर इसका रख-रखाव किया जाए तो इसका हरियाणा के लोगों को फायदा मिलेगा। खास तौर से जब पोलिटिशियंज

या आफिसर्ज वहां जाएंगे तो उनको वहां पर इसकी सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छी जगह पर यह रैस्ट हाउस है, इसलिए इस चीज पर आप ध्यान दें कि यह नीलाम न होने पाए। इसी तरीके से अब मैं अपने क्षेत्र की सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा। अकाल के समय पंचायती राज डिपार्टमैंट के द्वारा बारबास और घिगनाव गांव के बीच में सड़क बनवायी गयी थी लेकिन उस सड़क पर अब चला नहीं जा सकता। आम आदमी उस सड़क पर चलने के बजाए कच्चे पर चलना पसन्द करता है। जब हमने इस सड़क की रिपेयर करने के बारे में पी०डब्ल्यू०डी० डिपार्टमैंट और मार्केटिंग बोर्ड से बात की तो उनमें से कोई भी यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि यह सड़क हमारी है। पंचायती राज डिपार्टमैंट के पास पैसा नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क को चाहे मार्केटिंग बोर्ड को दो या चाहे पी. डब्लयू. डी. को दो लेकिन इस सड़क की रिपेयर करवायी जानी चाहिए। इसी तरह से सिवानी से सिंघानी वाया ओधरा अगर आप जाओगे तो मेरे विचार में पिछले 6 सालों से उस सड़क पर कोई थेगली तक नहीं लगी है। अब उस पर थोड़ा बहुत पैचवर्क किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि उस सड़क की दोबारा से कारपेटिंग करवायी जाए। इसी तरह से जहां तक पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की बात है मेरे क्षेत्र के अंदर आधा एरिया ऐसा है जहां पर खारा पानी है खासतौर से बहल और सिवानी के बीच का एरिया। पिछले पांच साल के अंदर वाटर वर्क्स में भी पूरा पानी नहीं भरा जाता था सिंचाई की तो बात दूर की है। कुछ गांव ऐसे पड़ते हैं जो हिसार जिले में भी हैं शायद आप जानते भी होंगे। कालूवास, ढाणी मिठ्ठी इनके बीच के जितने भी गांव हैं वहां पर पानी की बहुत चोरी होती है जिसके कारण वाटर वर्क्स तक पूरा पानी नहीं पहुंच सकता । मेरा निवेदन है कि इस बात पर भी गौर किया जाए कि वाटर वर्क्सों को तो कम से कम पूरा पानी दिया जाए। इसी तरह से एक और समस्या है। हमारे यहां पर बहल और सतनाली के एरिये में ट्यूबवैल्ज की बोरिंग बहुत है। हर गांव के अंदर तीन-तीन या चार-चार बोरिंग हैं। जब इनकी मोटर जली हुई होती हैं। तो महकमें से बात की जाती है। महकमें वालों का कहना होता है कि स्टाफ की कमी है। उनका यह भी कहना है कि उनके पास ऐक्स्ट्रा मोटर नहीं है। जब जली हुई मोटर निकालते हैं और उनको रिपेयर करवाने के लिए ले जाते हैं और फिर जब उनको वापस डालते हैं तो इसमें एक हफ्ते का समय निकल जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम हर एस०डी०ओ० के पास तीन तीन या चार चार मोटरें एक्स्ट्रा होनी चाहिए ताकि मोटर जलते ही मोटर को चेंज किया जा सके। इसी तरह से स्टाफ की भी बहुत कमी है। कुछ एक वाटर वर्क्स जैसे गुरेरा का वाटर वर्क्स, लीलस का वाटर वर्क्स ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी भी पूरा नहीं पहुंच पाता है। इसी तरह से होस्पीटल की बात है। बहन जी यहां पर बैठी हुई हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि लोहारू जो भिवानी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और जो राजस्थान बोर्डर पर पड़ता है वहां के हौस्पीटल में स्टाफ की कमी है। वहां पर एक एस०एम०ओ०,चार एम०ओ० और एक डैंटल सर्जन की पोस्ट्स है। इसके अलावा वहां पर 6 डॉक्टर्ज की पोस्ट्स भी हैं। लेकिन आज वहां एक एम०ओ० ही है। पिछले पांच साल का समय बीत गया तब से अब तक एक ही एम०ओ० वहां पर हैं और कोई नहीं है। इसी तरह से वहां पर जो एक्सरे मशीन है उस पर भी जंग लगा हुआ है। छोटी-मोटी कोई बात हो जाए तो उसके लिए भी भिवानी आना पड़ता है। जिससे आम आदमी को तकलीफ होती है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर एस०एम०ओ० या कम से कम दो एम०ओ० और एक डैंटल सर्जन जरूर भेजे जाएं तथा उस एक्सरे मशीन को चलाने के लिए रैडियोग्राफर न सही कम से कम कोई आदमी तो भेजा जाए। इसी तरीके से इरीगेशन की खासतौर पर मैं बात करूंगा। हमारे यहां लिफ्ट इरीगेशन में या तो लोहारू कैनाल से पानी लगता है। या सिवानी की तरफ से

[श्री सोमवीर सिंह]

पानी आता है। हमारे यहां पर इस बारे में दो तीन मोटी-मोटी समस्याएं हैं। पहली बात तो यह है कि वहां पर पानी पूरा नहीं दिया जाता है। लोहारू लिफ्ट इरीगेशन के एक्सियन ने करीब 300 क्यूसिक पानी का इंडैन्ट दिया था लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से 100 या 150 क्यूसिक के करीब ही पानी मिलता है। जो पम्प हाउस हैं उनकी हालत बहुत कमजोर हैं। लाडावास और सोहरा डिस्ट्रीब्यूटरीज में सिर्फ पीने के लिए ही पानी दे पाते हैं। झुप्पा डिस्ट्रीब्यूटरी, लोहारू डिस्ट्रीब्यूटरी और दमकोरा डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी बहुत कम पहुंच पाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम पांच नम्बर पम्प हाउस के ऊपर पूरे पानी की सप्लाई की जाए। इसी तरीके से जो पम्प हाउस की लिफ्टिंग की कैपेसिटी हैं वह बहुत पुअर है क्योंकि यह बहुत समय पहले लगायी गयी थी। और बहुत से पम्प हाउसिज की रिपेयर भी नहीं हो रही जिसके कारण पूरा पानी नहीं उठा पाते। सबसे बड़ी प्रौब्लम हैं कि अटेला के अंदर 132 के०वी० का पावर हाउस बना हुआ है जो कि बहुत पुराना है और उसकी कई बार रिपेयर भी हो चुकी है इसमें केवल 150 क्यूसिक पानी उठाने की क्षमता है और जो पम्प हाउस नं० 2 है उसमें वोल्टेज की कमी की समस्या है मैं निवेदन करूंगा कि अटेला के पावर हाउस में नया ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि वह पूरा पानी उठा सके और पम्प हाउस में वोल्टेज की समस्या भी न रहे। जब तक अलग से ट्रांसफार्मर का काम नहीं किया जाएगा तब तक चाहे जितने आश्वासन दे लें पानी नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा सबसे बड़ी बात सफाई की है। लोहारू फीडर की सफाई पिछले कई सालों से नहीं हुई है, ठोकरें बनी हुई हैं बरम बने हुए हैं उन सबको हटाया जाए। देवसर फीडर में पानी की चोरी होती है। सिवानी साइड में भी पीने का पानी नहीं पहुंचता है। पिछली सरकार के समय में लोहारू लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम 3.04 क्यूसिक पर थाउजैंड से घटाकर 2.40 क्यूसिक पर थाउजैंड पर एकड़ कर दिया था, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि अथोराइज्ड डिस्चार्ज रिस्टोर किया जाए ताकि इलाके की पानी की समस्या के हल में मदद मिल सके। इसी तरीके से लोहारू में पावर हाउस हमने 1999 के अंदर मंजूर करवाया था और वह पिछली सरकार के समय में बनकर तैयार हुआ है इसके अंदर ट्रांसफार्मर 10/16 मैगावाट का लगना था जबकि आया 6/8 मैगावाट का है अभी ट्रांसफार्मर लगा नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितनी क्षमता का ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ था, उतनी क्षमता का लगाया जाए। जो ट्रांसफार्मर आया है उसे जीवननगर से लेकर आए हैं काफी पुराना है जब तक वहां पूरी क्षमता का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाएगा तब तक जमींदार को फायदा नहीं मिल सकेगा। इसी तरह से मिठ्ठी के अंदर 33 के०वी० का सब स्टेशन है इसका प्रपोजल 4 एम०वी०ए० का गया हुआ है। पिछली सरकार ने भिवानी जिले के साथ भेदभाव किया था। दक्षिणी हरियाणा के 5 रैस्ट हाउस बंद किए गए थे उनमें से चार तो भिवानी के किए गए थे और एक महेन्द्रगढ़ का बंद किया गया था। मेरा निवेदन है कि भिवानी से बहल 60 किलोमीटर की दूरी पर है।जब ये रैस्ट हाउस बिजली बोर्ड ने बंद किए थे तो आर्डर में यह था कि बिजली बोर्ड का घाटा घटाने के लिए इन्हें बंद किया जा रहा है। वह इतना बड़ा रैस्ट हाउस है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर पर भी इतना बड़ा रैस्ट हाउस नहीं होगा और वह रैस्ट हाउस आज एस०डी०ओ० की रिहाइश के लिए काम में लिया जा रहा है जबकि एस०डी०ओ० को कहीं और दो कमरे का मकान भी किराए पर लेकर दिया जा सकता है। मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन है कि कई बार वे भी वहां जाते हैं तो किसी के घर बैठकर चाय पीते हैं। मेरा अनुरोध है कि वे मेरी मदद इस बारे में करें और इसको दोबारा से चालू करवाया जाए। इसी के साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गरीबी रेखा से

नीचे रहने वाले लोगों को पीले कार्ड बांटे गये हैं, इस बात का जब हम चुनाव के दौरान जनता के बीच गये तब पता चला कि 40 साल के आदमी को तो पेंशन मिल रही है और 70 साल के आदमी को पेंशन नहीं मिल रही है, इसके लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम दोबारा से सर्वे करायेंगे तो इस काम को जल्द से जल्द करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : धन्यवाद, डिप्टी स्पीकर सर। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने प्रदेश के हालात को देखते हुए जो प्राथमिकताएं बजट के माध्यम से सदन के पटल पर रखी हैं वे स्वागत करने योग्य हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह की आशा और उम्मीद हरियाणा की जनता ने इस सरकार से लगाई थी उनके अनुरूप एक बहुत अच्छा प्रयास बजट के माध्यम से सरकार ने यहां हमारे सामने रखा है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और संसदीय प्रणाली का भी इनको बहुत अच्छा अनुभव है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे प्रश्नकाल के दौरान हमारे संसदीय विभाग के मंत्री जी ने सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में विस्तार से बताया है। जैसा हम देख रहे हैं औद्योगिक नीति जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने बनाई है और जिस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देकर हरियाणा के लोगों के दुखों और तकलीफों का निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उसके अच्छे नतीजे आने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट सरकार का एक आईना है जिसमें लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ा स्थान है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे जो कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इंडस्ट्रीज जिसे सी०आई०आई० कहते हैं, उनके साथ बैठकर बात करें कि जो पंजाब और हरियाणा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो हरियाणा के उद्योगों को अपनी ताकत के भरोसे से चलाते हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके साथ बैठक करें। उस बैठक में यह बात खोजने की कोशिश करें कि ये उद्योगपति हरियाणा प्रदेश के कौन से हिस्से में हैं, जहां अपने साधनों से और अपने भरोसे से औद्योगिक कामों को विकास की गति देना चाहते हैं, अपने ही पैसों से हरियाणा के अन्दर कौन सी ऐसी जमीन है जहां बिना सरकार के खजाने में से किसी प्रकार की मदद के लिए वे औद्योगिक व्यवस्था को खड़ी कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सुनने में आया है कि पिछले दिनों शनिवार के दिन इंग्लिश के दि ट्रिब्यून अखबार में एक ऐडिटोरियल लिखा गया था। जिस दिन बजट पेश किया गया था, मैंने उसकी कॉपी माननीय वित्त मंत्री जी को भिजवा दी है। उस ऐडिटोरियल में लिखा गया था Borrow More and Work More वाली बात इनके सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली सरकार ने किस तरीके से गलत बातें की और किस तरीके से अनाप शनाप खर्च किया। किस तरीके से राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के खजाने का दुरुपयोग किया गया उसका नतीजा यह है कि आज हरियाणा के लोगों के सिर पर 22 हजार करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है। अखबार में लिखा है कि वह कर्जा बढ़कर वर्ष के अन्त तक 25 हजार करोड़ रुपये बनकर खड़ा हो जायेगा। वित्तमंत्री जी आपका डैफिसिट 242 करोड़ रुपये के करीब है और आपकी आमदनी से ज्यादा आपका खर्चा है। आपको ये सारी बातें देखनी पड़ेंगी और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जरूरी है कि सरकार के खजाने से अलग हटकर के राजस्व प्राप्ति के सरकार को

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

नये -नये आयाम, नये-नये तरीके खोजने होंगे और उसके लिए डिप्टी स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को चीन के एक दार्शनिक की कहानी सुनाता हूं। उन्होंने उस वक्त के राजा को एक अच्छी बात कही। उस दार्शनिक का नाम कंफ्यूसिस था। राज्य को उन दिनों एक भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। राजा उस दार्शनिक के पास गया और पूछा कि राज्य की बिगड़ी हुई व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है! तो उस दार्शनिक ने राजा से कहा कि इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं पहली फौज, दूसरी जनता को रोटी और तीसरी जनता का भरोसा। राजा ने उस दार्शनिक से कहा कि अगर 3 चीजें न होकर दो ही चीजें रखी जाएं तो वे दो चीजें कौन सी हो सकती है तो उस दार्शनिक ने राजा को कहा कि फौज छोड़ दो। जनता को रोटी और जनता का विश्वास अगर राजा के साथ हो तो काम चल सकता है क्योंकि जनता का भरोसा आपके साथ होगा तो जनता आपकी सीमाओं की रक्षा कर सकती है और आपके लिए लड़ मर सकती है। फिर राजा ने कहा कि अगर दो चीजों की बजाय एक चीज रखी जाए तो वह कौन सी है तो उस दार्शनिक ने कहा फिर जनता का भरोसा रखो क्योंकि जनता का भरोसा आपके साथ होगा तो भूखी जनता भी आपके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकती है। तो मैं इस उदाहरण के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय यह कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा में नई सरकार बनी हैं, हरियाणा की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपको जनता की उन उम्मीदों पर खरा उतरना है उसके लिए सबसे पहला काम सरकार के सामने है जो यह है कि वे लोग जिन्होंने हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड़ किया या कानून की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने दिन दिहाड़े प्रदेश के अन्दर तरह तरह से अत्याचार किए, गलत मुकदमें बनाए, अधिकारियों का दुरूपयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और सरकार के खजाने पर इतना बड़ा कर्जा खड़ा कर दिया उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए। वित्त मंत्री महोदय ने जिस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं कही हैं, इन प्राथमिकताओं में आपको जनता को यह भरोसा दिखाना होगा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार को ऊपर के स्तर पर नहीं बल्कि नीचे के स्तर पर खत्म करने की जरूरत है इसके लिए जरूरी है कि सरकार के मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी गांव के स्तर पर जाकर व शहरों के मौहल्लों में जाकर लोगों के आमने-सामने मुखातिब होकर उनकी दिक्कतों को सुनें। सरकार अधिकारियों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करें और जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करते उनको सही तरीके से दण्डित करें। किसानों को कई तरह की राहत देने की बात इस बजट में कही गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी राहत हरियाणा के लोगों को दी जा सकती है। जिस तरीके से पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट में जब वे मुकदमा दायर करने आते हैं तब हरियाणा के लोगों से जो कोर्ट फीस ली जाती है वह बहुत ज्यादा है चाहे वह केस स्पैसीफिक परफोरमैंस के हों या डिक्री के हों। पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और चण्डीगढ़ में जो फीस है, वह बहुत कम है। हरियाणा में यह कोर्ट फीस बहुत ज्यादा है। इसके लिए वकील लोगों से हरियाणा की फीस के मुताबिक पैसा लेते हैं। हाई कोर्ट में जो वे स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं वह सही मायनों में कम कर के डाली जाती है, उससे हरियाणा का नागरिक लुटता है और हरियाणा का किसान लुटता है। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इसको हरियाणा, पंजाब और चण्डीगढ़ की तर्ज पर जो उनकी कोर्ट फीस है हरियाणा की फीस भी उसी तर्ज पर करके इन लोगों को राहत दे सकते हैं। इसी तरीके से शिक्षा की बात बजट में की गई है। राजीव गांधी नाम के नए

विश्वविद्यालय की बात कही गई है जो कि अच्छा प्रस्ताव है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हमारे पुराने विश्वविद्यालय है, जिन विश्वविद्यालयों के साथ उनकी वर्किंग के साथ पिछली सरकार ने खिलवाड़ किया, चाहे दाखिले के मामले थे और चाहे नियुक्तियों के मामले थे उनमें दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो। पिछली सरकार ने यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता को खत्म करने के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार को इनकी स्वायत्तता बहाल करने की पहल करनी चाहिए। इन विश्वविद्यालयों में बहुत अच्छे पढ़े-लिखे लोग जिन की इंटीग्रेटी लोगों की नजर में बखूबी अच्छी तरह से जानी जाती है उनको वाइस चांसलर लगाया जाए। अच्छे प्रोफेसर, अच्छे लोगों को यूनीवर्सिटीज में लगाएं और लोगों का भरोसा कायम करें। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने वैट के बारे में कहा है। वैट के बारे में इन्होंने कहा कि ये नई-2 रियायतें हरियाणा के लोगों को देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा हरियाणा एक प्रदेश है जहां पैस्टीसाईड्स और एग्रीकल्चर इम्पलीमैंट्स पर वैट में छूट नहीं है। पंजाब में और दूसरे प्रदेशों में पैस्टीसाईड्स और ऐग्रीकल्चर इम्पलीमैंट्स पर वैट में एग्जैम्पशन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मेरी इस बात को नोट कर लें और हरियाणा प्रदेश में जो पैस्टीसाईड्स और एग्रीकल्चर इम्पलीमैंट्स हैं उनको वैट के परव्यू से बाहर लाया जाये। यानि कि वैट के माध्यम से इन चीजों पर जो टैक्स लगता है वह नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से किसानों की हौंसला-अफजाई होगी। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक क्रौप डाईवर्सीफिकेशन की बात है आज के दिन क्रौप डाईवर्सीफिकेशन किसान की मेन जरूरत है, कह देने मात्र से क्रौप डाईवर्सीफिकेशन नहीं होगी। आज के दिन हरियाणा में धान की बुआई बहुत बड़े स्तर पर हो रही है और हम सब जानते हैं कि धान की फसल उस एरिया के लिए उपयुक्त मानी जाती है जहां पर बरसात 1500 मिली मीटर होती है। हरियाणा प्रदेश में तो कभी भी बरसात 250-300 मिली मीटर से अधिक नहीं होती। हमारे यहां लोग धान की सिंचाई नहर के पानी से करते हैं और इसके अतिरिक्त ट्यूबवैलों के माध्यम से नीचे से मीठा पानी निकालकर धान की फसल की सिंचाई करके बहुत बड़ा जोखिम हरियाणा के किसान उठा रहे हैं। उसका नतीजा यह है कि आज तमाम हरियाणा में पीने के पानी की बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है, हमें इस समस्या का निवारण करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल प्रबन्धन के लिए जो हमारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे इन्जीनीयर्ज हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाये और वह कमेटी स्टडी करे। और वह कमेटी पूरे प्रदेश का सर्वे करे कि सही तरीके से कौन-कौन सी फसलें हमारे यहां लगाई जा सकती हैं और पानी का इंतजाम कैसे किया जा सकता है, उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पंजाब में श्री एच०एस० जौहल हैं, उनका आर्टीकल मैंने पढ़ा था शायद वित्तमंत्री जी ने भी पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा तो वे इसको जरूर पढ़ें। मैं उस आर्टिकल की कॉपी इनके पास भिजवा दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों द्वारा धान की बुआई को रोकने के लिए हमारी सरकार को केन्द्र सरकार से बात करनी चाहिए। यदि हम किसानों से बात करेंगे तो किसान नाराज हो जायेंगे और विपक्ष के साथी इसका राजनैतिक लाभ उठायेंगे। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से बात करके किसानों के लिए उचित मुआवजा तय करवाया जाये कि जो किसान धान की फसल बोते हैं जिनके यहां पर्याप्त मात्रा में पानी है, यदि वहां किसान इस फसल की बिजाई नहीं करेंगे तो उन्हें मुआवजा दिया जायेगा। इस तरह की स्कीम केन्द्र सरकार से एप्रूव करवाई जाये और किसानों से भी आश्वासन लेना चाहिए कि मुआवजा लेने के बाद वे धान की फसल की बिजाई नहीं करेंगे।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारी सरकार इस तरह का कार्यक्रम हरियाणा के किसानों के लिए तैयार करली है तो इससे बड़ी हम देश की और प्रदेश की सेवा नहीं कर सकते। यदि हरियाणा के किसान हरियाणा में धान बोना छोड़ दें और उनको जरूरत के मुताबिक मुआवजा दे दिया जाये जिससे किसानों को आर्थिक नुक्सान न हो तो जो हरियाणा में पीने के पानी की कमी के बारे में हर कोने से आवाज आ रही है। कि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक साल तक जितना मौजूदा पानी हमारी नहरों और रजबाहों में है उस पानी को उन रजबाहों में चलायें जिनसे धरती के नीचे का पानी रिचार्ज होता है तो उस पानी को रिचार्ज करके पूरे हरियाणा प्रदेश में धरती के नीचे मीठा पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त धान और गेहूं की फसल की लगातार उपज से धरती का उपजाऊपन खत्म होने के कगार पर है, उसको भी बचाया जा सकता है और उसके लिए किसानों के सामने अगर कोई आल्टरनेट है तो वह सोयाबीन या अरहर की खेती का है। हरियाणा का किसान आज सोयाबीन और अरहर की खेती करना चाहता है लेकिन उसके सामने दो समस्याएं हैं। एक तो उसको इन फसलों के अच्छे बीज उपलब्ध नहीं होते दूसरे अगर सोयाबीन बो दी जाती है और फसल पैदा हो जाती है तो उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** सरकार द्वारा भी सोयाबीन न खरीदने की वजह से किसानों को सोयाबीन की फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि जो किसान सोयाबीन बोयेगा उसका सारा उत्पादन सरकार खरीदेगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा डर हरियाणा के अन्दर रोजों की वजह से है। रोज झुण्ड के झुण्ड हरियाणा में चलते हैं और फसलों को बर्बाद करते हैं। इसके साथ ही वे लोगों के लिए जान का खतरा भी बने रहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को भारत सरकार को विश्वास में लेकर इस प्रदेश के अन्दर रोजों की बढ़ती हुई संख्या पर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए तथा इनका कोई न कोई इलाज सोचना चाहिए वरना आने वाले दिनों में यह रोज हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि वे हर जिले में जा कर किसानों, पंचों तथा सरपंचों को बुला कर लोगों को आश्वस्त करें कि जो किसान सोयाबीन बोयेगा जो किसान अरहर बोयेगा या धान की फसल न बो कर कोई दूसरी फसल बोयेगा उसे सरकार हर तरीके का प्रोत्साहन देगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी का बढ़ता हुआ खर्च हरियाणा की जनता के सिर पर बहुत बड़ा बोझ है। वित्त मन्त्री जी, आप इस बारे में मेरा नोट लिख लीजिए। मेरा निवेदन है कि हरियाणा जैसी छोटी सी स्टेट में दुनियां भर के फाईनैंशियल कमिश्नर, दुनियां भर के आई०ए०एस० अधिकारी, तीन-तीन डी०जी० और इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, सैक्रेटरी ऑफ दि डिपार्टमैंट जो ऑफिसर्ज होते हैं वे अपने साथ कमिश्नर का रैंक लेकर चलते हैं ताकि उनको सुविधाएं मिलती रहें। आज हरियाणा की हालत अगर सुधारनी है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि जितने भी ऐसे पद हैं या अधिकारी हैं, कई-कई आई०जी०, कई कई डी०जी०, कई कई फाइनैंशियल कमिश्नर हैं उनके खर्चों को हटाना होगा और सच्चाई को मानना होगा। जब तक खर्चों पर रोक नहीं लगेगी तब तक स्टेट की इकोनोमिक कण्डीशन को ठीक नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, बिजली हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या है। बिजली की चोरी या लाईन लौसिज कह लें। यह प्रदेश के अन्दर बहुत ज्यादा है इसके लिए व्यापक स्तर पर कोई लौंग टर्म पॉलिसी सरकार को ऐडॉप्ट

करनी पड़ेगी। हमारे प्रदेश के पड़ौस में हिमाचल प्रदेश है, उससे हमें बिजली की बात करनी चाहिए और अगर इसके लिए आसाम तक भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। हाईडल पावर को जब तक यह प्रदेश एडॉप्ट नहीं करेगा तब तक बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। हाईड्रो बिजली पानी से बनती है और इसकी कीमत काफी सस्ती पड़ती है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इस हाईड्रो पावर को आपको अपनाना पड़ेगा इसके लिए चाहे आप हिमाचल प्रदेश जाएं या आसाम में जाएं या और कहीं पर भी जाएं। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बिजली की खरीद में अनाप-शनाप तरीके से मनचाहे लोगों को जगह-जगह पर दूसरे प्रदेशों में बिठा दिया जिन्होंने गलत और नकली कम्पनीज़ बना रखी थीं। वे दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीदते थे, यह रिकार्ड पर दिखाया जाता था और उस बिजली को हरियाणा प्रदेश के लोगों को बेचते हुए दिखाया जाता था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वे कोई भी लोग थे उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज होने चाहिएं। हरियाणा के लोगों से उन्होंने पैसा वसूला है जबकि हरियाणा के लोगों को कभी बिजली मिली नहीं क्योंकि वह बिजली केवल कागजों पर ही दिखाई हुई थी इसलिए उन लोगों से उस पैसे की वसूली होनी चाहिए तथा उनके खिलाफ मुकदमें भी दर्ज होने चाहिए। इसी प्रकार से जैसे चौधरी सोमबीर जी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने पता नहीं कितने अनाप-शनाप तरीके भ्रष्टाचार के लिए निकाले। अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले में बिजली विभाग की कम से कम 15 एकड़ जमीन थी जिस पर बड़े-बड़े अधिकारियों के घर और दफ़्तर थे। रातों -रात उन पर बुलडोजर चला दिए और अधिकारियों को डरा धमका कर उन मकानों को खाली करवाया गया। अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है लेकिन ओम प्रकाश चौटाला और उनके लोगों ने बिजली विभाग की जिस जमीन पर जबरन कब्जा किया था वहां पर आज भी उनका कब्जा बरकरार है और उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वह जमीन 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि जिसने बिजली विभाग या दूसरे विभागों की जमीनों को चौटाला साहब और उनके परिवार के लोगों तथा सरकारी अधिकारियों से मिली भगत करके, साजिश से उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, वे कब्जे वापिस लिए जाएं और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। स्पीकर सर, इसी तरह से पिछली सरकार जिसे डींग मारने की आदत थी डींग मार दी कि हमने आबियाना माफ कर दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आबियाना माफ हुआ था तो उसकी नोटिफिकेशन कहां है, कौन सा बिल इस असैम्बली के अन्दर आया जिसमें यह कहा गया है कि हरियाणा के किसानों का आबियाना माफ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कोई आबियाना माफ नहीं किया गया था। असैम्बली के अन्दर मुख्यमंत्री चौटाला गलत बोलने का काम करते थे उन्होंने यह मात्र अखबारों में चर्चा करने के लिए किया था। आज किसान भाई आबियाना नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे तो भुलावे में हैं कि उनका आबियाना माफ हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि असैम्बली में कोई बिल वगैरह लाकर किसानों का आबियाना माफ कर दिया जाए। स्पीकर सर, मेरे हल्के में जो नहरें और रजबाहें हैं उनका आबियाना उत्तरप्रदेश की सरकार को जाता है । इस विषय में मेरा सरकार से निवेदन है कि पिछली सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया था। आज की सरकार इस बारे में उत्तरप्रदेश की सरकार से बातचीत करके वहां के किसानों का आबियाना माफ करवाए या सरकार अपने खजाने से वहां के किसानों का आबियाना उत्तरप्रदेश की सरकार को देकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें।

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

स्पीकर सर, मैं सदन में बताना चाहूंगा कि हमारी कमेटी एक बार राजस्थान में गई थी और हम रोजाना 700 किलोमीटर गाड़ी सड़कों पर चलाते थे लेकिन हमने सड़कों पर कहीं पर भी लोगों का हजूम नहीं देखा और न ही किसी गाड़ी या बस की छत्तों पर नौजवानों को, बूढ़ों को या बच्चों को बैठे हुए देखा है। हमारे हरियाणा में यह होता है, चाहे वह बस हो, जीप हो या कोई दूसरी सवारी हो लोग उनकी छतो पर या पीछे लटके हुए मिलते हैं। मेरा परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस बारे में व्यवस्था करें। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से एक और प्रार्थना है कि जो लड़कियां बसों से दूसरी जगहों पर पढ़ने के लिए जाती है तो उनसे छेड़छाड़ की जाती है तो इस विषय में मेरा निवेदन है कि मंत्री जी को छात्राओं के लिए अलग से बसों का इन्तजाम करना चाहिए और लड़कों के लिए अलग से प्रावधान करना चाहिए। परिवहन मंत्री जी, इसके अलावा हरियाणा में जनता के लिए जिन साधनों का प्रावधान रखा गया है उसमें इनको और बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। स्पीकर सर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्व विद्यालय पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन वहां से डिग्री प्राप्त करके निकलने वाले बच्चों को कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है। इसके अलावा जो साईंटिस्ट और ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधिकारी है उनकी उपयोगिताओं का आज हमारे हरियाणा के किसानों के लिए न के बराबर फायदा होता है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस यूनिवर्सिटी के ऐसे ही हालत हैं तो सरकार को इस बारे में पुन: विचार करना चाहिए और किसी योग्य वी0सी0 को वहां पर बिठा करके उनकी वर्किंग पर ध्यान रखने के लिए वित्तमंत्री जी को सदन में आश्वासन देना चाहिए। स्पीकर सर, हरियाणा में जो हमारी कृषि है वह सैचुरेशन प्वायंट पर है। आज हमारा जो उत्पादन है वह आखिरी सीमा पर पहुंच गया है और अब वापसी की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें हरियाणा में डेयरी फार्मिंग के विकास के बारे में विचार करना चाहिए और हमारे यहां के लोगों को इस बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमारे हरियाणा के साथ दिल्ली लगता है और चण्डीगढ़ भी लगता है। यहां पर जो दूध की सप्लाई हो रही है उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हरियाणा सरकार को हरियाणा के नौजवानों को डेयरी फार्मिंग के बारे में ट्रेनिंग देने के बारे में विचार करना चाहिए। इससे वे दूसरे प्रदेशों को बहुत अच्छा दूध प्रोवाईड कर सकते हैं । इसके अलावा हमारे यहां पर जो मुर्रा नस्ल की भैंसें है इनकी नस्ल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उनको एक्सपोर्ट भी करवाया जा सकता है, स्पीकर सर, स्कूलों के हालात पर सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जो टीचर्ज हाजरी लगाते हैं उनकी चैकिंग हो। चौटाला सरकार के समय में लड़कियों के स्कूलों में मेल अध्यापक लगा दिए गए थे। मेरा सरकार से यह कहना है कि लड़कियों के स्कूलों में ज्यादातर महिला अध्यापिकाएं ही होनी चाहिए। स्पीकर सर, जो प्राईवेट स्कूलज़ हैं, सरकार को इस बारे में सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हरिजन और बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं अगर वे प्राईवेट स्कूलों में दाखिला लेते हैं तो सरकार उनकी रिक्वीजीशन पर पाबन्दी लगाकर उनके लिए एक इन्तजाम करे। कि अगर प्राईवेट स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे फीस सरकारी स्कूलों जैसी ही ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं वाईंड अप ही कर रहा हूं । सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पिछली सरकार ने एक और ढोंग किया था और कहा था कि जो

छोटे लोग शहरों के अंदर रहते हैं उनका हमने हाउस टैक्स माफ किया है लेकिन कोई भी हाउस टैक्स माफ नहीं किया गया है। आज वह हाउस टैक्स कई गुना बढ़ गया है जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमें हुए हैं और अपने घरों में बैठे हुए सोच रहे हैं कि अब हाउस टैक्स का क्या होगा ? मैं आपके माध्यम से माननीय वित मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि आप एक मीटिंग बुलाएं जिसमें तमाम हरियाणा की जो म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं जिनको संवैधानिक अधिकार भी है कि वे अपनी मर्जी से काम करें, वे हों। जो चुंगी पिछली सरकार के टाईम में हटायी गयी थी उसके बारे में आप उनके साथ बैठकर बात करें। स्पीकर सर, यह मेरा अपना सुझाव है अगर सरकार इसको ठीक समझे तो इसे मान ले। अगर म्यूनिसिपल कमेटीज, नगर परिषद या नगर निगम की इच्छा हो तो हाउस टैक्स समाप्त करके चुंगी भी लगानी पड़े तो लगायी जाए क्योंकि इससे बहुत बड़ा लाभ सरकार को हो सकता है और हजारों बच्चों को रोजगार भी आप दे पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यह कहां का इन्साफ है कि बगैर कोई काम किए, व्यापार किए या रोजगार किए अगर रहने के लिए भी आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है तो यह लोगों के लिए एक बोझ है इसलिए इस बोझ को सरकार को हटाना चाहिए। अगर नगरपालिकाएं चाहती हों और यदि चुंगी लगानी पड़े तथा हाउस टैक्स को हटाना पड़े तो मैं समझता हूं कि हरियाणा के लोग इसका स्वागत ही करेंगे।

Mr. Speaker : Please try to wind up.

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं अभी कंक्लूड कर देता हूं। अब मैं अपने हल्के की बात कहता हूं। जो पलवल-मानेसर कुंडली एक्सप्रेस हाई-वे बन रहा है यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। कांग्रेस की सरकार जब 1991 से लेकर 1996 तक हुआ करती थी तब इस काम की शुरूआत हुई थी और आज फिर से कांग्रेस की सरकार इसको अंजाम देने जा रही है। यह हरियाणा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा हरियाणा सरकार को सुझाव है कि इस एक्सप्रेस हाई-वे से जहां हरियाणा के लोगों को कुछ-कुछ इलाकों में ही रोजगार मिलेगा जैसे कि क्लस्टर आप बना रहे हैं लेकिन इससे सबसे बड़ी राहत दिल्ली की सरकार को मिलेगी । इसलिए सरकार को दिल्ली की सरकार के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। आपको दिल्ली की सरकार को कहना चाहिए कि उनके सारे ट्रैफिक को हमारा यह एक्सप्रेस हाई-वे पार करेगा इसलिए जो पैसा इसके ऊपर खर्च होगा उसमें दिल्ली की सरकार को भी इस खर्च में शामिल करना चाहिए। स्पीकर सर, जो लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स है उसके बारे में भी सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स में दो फैसले सरकार को लेने पड़ेंगे। पिछली सरकार के समय में चौटाला ने इसका बड़ा मिसयूज किया। कई उद्योगपतियों को जैसे हीरो होंडा है चौटाला ने अपने रिश्तेदारों को, अपने विधायकों को और अपने मंत्रियों को हीरो होंडा की एजैंसी हर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, ब्लॉक लैवल पर इसलिए दिलवायी क्योंकि उनको गैर कानूनी तरीके से एल०ए०डी०टी० टैक्स में बड़ी भारी रियायत दी गयी थी । इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इस हीरो होंडा कम्पनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए तथा उस वक्त के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

Mr. Speaker : Dalal Sahib, please take your seat. Now, Shri Ranbir Singh Mahendra will speak.

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा (मुंढाल खुर्द) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की सरकार नौ साल के बाद बनी है और यह इसका पहला बजट पेश किया गया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं क्योंकि यह बजट जनता की भावनाओं को पूरा करता है। जिस उद्देश्य के लिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए और जो जनता चाहती थी उन आशाओं के अनुकूल बजट पेश किया गया है जिसके लिए हमारी सरकार और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बधाई के पात्र हैं। पिछले दो दिन से सदस्यगण यहां अपने विचार रख रहे हैं। कई बातें उनमें से ऐसी हैं जो कि कॉमन हैं उन पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रीगणों ने जो अपने विचार रखे उसमें एक बात शिक्षकों की रही है। आमतौर पर एक शिकायत है कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों की बहुत कमी है। मैं जहां भी गया, जिस गांव में भी गया, वहां सबने यही कहा कि स्टाफ पूरा करवा दो ताकि रिजल्ट अच्छा आ सके। अभी इस बारे में सोमवीर सिंह जी भी बोल रहे थे। हैल्थ मिनिस्टर ने यह माना भी है कि डॉक्टरों की कमी है। सच्चाई तो यह है कि देहात में कोई डॉक्टर रहना ही नहीं चाहता है। आज मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों से यह कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी ने एक सपना लिया था, वह सपना था पंचायतों को इम्पॉवर्ड करने का। 1992-93 में केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इस बारे 73 वां संशोधन पास किया गया था जिसका 11वां शिडयूल कांस्टीच्यूशन में आज भी है, उसमें इस बात के लिए साफ कहा गया था कि 73 वें संशोधन के हिसाब से 29 महकमें ऐसे थे जो स्थानीय निकायों को ट्रांसफर करने थे लेकिन मुझे इस बारे में कहते हुए खेद है कि उत्तर भारत के किसी भी प्रान्त ने इस बारे में आज तक अपील नहीं की। साउथ में कर्नाटका, केरला वैस्ट में महाराष्ट्र और गुजरात हमसे इतना आगे निकले हुए हैं कि वे 73 वें अमैंडमैंट को याद रखते हैं। कर्नाटक की पोजीशन यह है कि टोटल स्टेट का जो बजट है उसका 1/3 हिस्सा स्थानीय निकायों को बजट में प्रावधान करके दिया जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि 73 वें संशोधन को असली जामा पहनाकर के राजीव जी के सपने को पूरा करें। इससे काफी सारे अहम् मुद्दे स्थानांतरित हो जाएंगे और लोगों को भी इस बात का पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है ? हम इस बात से खुश हैं कि राजीव जी का सपना था कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से एक लेडीज एम०एल०ए० और दो लेडीज पंचायत में मैंबर बनें लेकिन उनकी असली मंशा यही थी कि 29 महकमें नगर निकायों को दिए जाएं। मुझे खेद है कि ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने डी०पी०ई०पी० स्कीम के तहत जे०बी०टी० टीचर्स को कंट्रैक्ट पर लगाया और जब जे०बी०टी० में रैगुलर टीचर्स को भर्ती करने लगे तो कंट्रैक्ट बैसिज वाले टीचर्स ने ऐतराज किया और कहा कि वैकेन्ट पोस्टों के अगेंस्ट उनको ऐडजस्ट किया जाए तो उन्होंने यह बहाना बनाया कि प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर्ज हैं वे रैगुलर इनरोलमैंट से अलग हैं इसलिए डी०पी०ई०पी० स्कीम में उनको ऐडजस्ट नहीं कर सकते। अदालत से टीचर्स के मामले में उस समय की सरकार को राहत मिली है। मैं पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी का बयान पढ़ रहा था और कल भी यह बात हाउस में आई कि टीचर्स की तनख्वाह के बारे में झगड़ा पड़ा हुआ है। कई ऐसी बातें हैं जिनका झगड़ा पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि श्री ओमप्रकाश चौटाला जहां प्रजातंत्र की सांस लेते थे लेकिन पंचायत को अधिकार देना तो दूर की बात रही उन्होंने जो विकास समितियां बनाई उनकी कोई लायब्लिटी तक नहीं होती थी और कोई एकाउंटेब्लिटी नहीं होती थी। पैसा जाता था लेकिन काम करते थे या नहीं

करते थे कोई पूछने वाला नहीं होता था। जो इलैक्टिड पंचायत थी उनके पास कोई पावर नहीं थी। आज अधिकारीगण भी यह बात कहते हैं कि कोई भी पंचायत का मैम्बर हो या दूसरे अधिकारी हो, काम करने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि फंक्शंज, उसके बाद फाईनैंस एण्ड दैन फंक्शंनरिज। फैक्शन हमारे सामने 29 हैं और उसके बाद 29 का फैसला होने के बाद फाईनैंसिस की बात आती है। मैं कल ही वित्त मंत्री जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि लोकल बॉडीज के लिए 100 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है लेकिन 100 करोड़ बहुत कम हैं उनके लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध किया जाए उसके बाद फंक्शंनरिज की ऐप्वाइंटमैंट की जाये। जहां पर गवर्नमैंट सर्विस में सेलरी की सुरक्षा होगी वहां पर अधिकारी चाहेगा कि यह काम करें अपनी ड्यूटी करें। सबसे पहले मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उत्तरी भारत में हरियाणा एक रोल मॉडल बने। 73 वां अमैंडमैंट लागू करने के बाद जिसमें इस बात का प्रावधान है कि पंचायतों को और लोकल बॉडीज को पॉवर दी जायेंगी, उसकी तरफ सरकार पहल करें। मैं 1/3 तो नहीं कहता लेकिन मैं वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करता हूं और आश्वासन भी चाहता हूं वित्त मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कि अगले बजट में, क्योंकि यह बजट बनाते समय तो उनके पास समय थोडा था अगले बजट में कम से कम 1/4 बजट लोकल बॉडी को दिया जाये ताकि 73rd अमैंडमेंट जो श्री राजीव गान्धी जी का सपना था उसको पूरा करने की पहल की जा सके। हरियाणा प्रान्त जब से बना तब से रोल मॉडल रहा है। 1970 में हरियाणा प्रान्त में कम्पलीट इलैक्ट्रिफिकेशन हुई थी उस समय चौधरी बंसी लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और श्रीमती इन्दिरा गान्धी देश की प्रधानमंत्री थीं। इसके साथ-साथ टूरिज्म और लिफ्ट इरीगेशन स्कीम सारे एशिया में सबसे पहले हरियाणा में कामयाबी से चलीं। आज भी चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वे 73 वें अमैंडमैंट को लागू करने की पहले करें ताकि हरियाणा को रोल मॉडल के रास्ते पर ले जायें। आज चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती सोनिया गान्धी कांग्रेस प्रधान हैं। हम चाहेंगे कि जैसा कि उन्होंने जीन्द की रैली में इस बारे में आश्वासन दिया था कि हर मुमकिन सहायता दी जायेगी इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि 73वें अमेंडमैंटको नजरअंदाज न करके श्री राजीव गान्धी के सपने को पूरा करने की तरफ कदम उठाने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, क्राप डाईवर्सिफिकेशन के बारे में जैसा कि दलाल साहब ने कहा इसके बारे में मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं यह बात बहुत अच्छी है और समय की पुकार है लेकिन इसके लिए एक बात जरूर होनी चाहिए और वह यह है कि किसानों को इसके बारे में पूरी शिक्षा देनी चाहिए। अगर वे अपनी फसल बदलते हैं या फसल चक्र को बदलते हैं तो जैसे गेहूं, चने और धान से अगली फसल क्या बोनी चाहिए तो उसकी अगली मार्केटिंग क्या होगी, किसान को उससे कोई नुकसान तो नहीं हो जायेगा की जानकारी देनी चाहिए। यहां पर कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है। विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि यूरोपियन कण्ट्रीज और यूरोपियन यूनियन को, फ्रान्स और जापान को जहां सरकार द्वारा किसान को 50 प्रतिशत सहायता दी जाती है जबकि उसके बदले हमारे हिन्दुस्तान में सिर्फ 9 प्रतिशत की सहायता दी जाती है जब तक किसान का भविष्य सेफ नहीं होगा तब तक किसान दूसरी फसल बोने के लिए तैयार नहीं होगा। आज किसान गेहूं इसलिए बोता है कि वह सोचता है कि कम से कम गेहूं को सरकार तो खरीदेगी। उसको अगली फसल के बारे में पूरी जानकारी और आगे के लिए क्या फ्यूचर है उसके बारे में पूरी तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अब लिंगानुपात के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दूसरी बेटी होगी तो 5000 रुपये दिए जाएंगे और 5 साल तक दिए जाएंगे,

[श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा]

5 साल तक पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा रहेगा उसके बाद उसका इन्ट्रस्ट हर महीने मिलता रहेगा लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि 1996 से पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपनी बेटी अपना धन नाम की स्कीम चलाई थी जिसके तहत 5000 रुपये जमा होते थे उसके ऊपर जो कुछ इन्ट्रस्ट वगैरह बनता था, 18 साल बाद, लड़की को अगर वह 5वीं पास हो, शादीशुदा न हो उसको 52 हजार रुपये मिलते थे लेकिन वह स्कीम बन्द कर दी गई। आज साढ़े 3 लाख परिवार उस स्कीम से मरहूम हैं। सरकार ने उस समय कोई प्रावधान नहीं रखा था, उस समय इन्दिरा विकास पत्र के जरिए पैसा देते थे। लड़की और पेरेंटस के नाम से इन्दिरा विकास पत्र खरीदे जाते थे। वह स्कीम बन्द हो गई और साढ़े 3 लाख परिवारों को कुछ नहीं मिला, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और न ही उन लोगों को कोई पैसा दिया गया इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह इंट्रस्ट की स्कीम है। अगर एक मिनट के लिए मान लो कि यह स्कीम बन्द हो जाती है तो हमें इसके बारे में कोई अल्टरनेटिव जरूर सोच लेना चाहिए ताकि यह स्कीम आगे जाकर कामयाब हो सके। मैं एक बात अपने हल्के के बारे में कहना चाहता हूं। पावर के बारे में जितना हम कहते हैं कि पहले से सुधार है, उतना सुधार है नहीं कि जिसकी तारीफ हम अच्छी तरह से कर सकें। मेरे हल्के में एक ऐसा ऐक्सीयन है जोकि पावर हाउस से लाइट बन्द कर देता है ताकि लाइन लोसिज न हो, हमने पता किया तो महकमें के अधिकारियों ने इस बात को माना। अगर इस तरह से लाइन लौसिज बन्द करने हैं तो फिर अच्छा है कि मेन पावर हाउस ही बन्द कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पावर मिनिस्टर और मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में कहना है कि जहां तक बिजली का प्रश्न है पहले से तो बहुत इम्प्रूवमैंट है, लोग इस बात को कहते हैं। पानी, बिजली के लिए लगातार काम करने की जरूरत है। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए जाएं कि इस तरह की बात न करें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्कूलों के बारे में, टीचिंग स्टाफ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। किसी भी स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक स्कूल में स्टाफ पूरा किया जाए। पब्लिक हैल्थ के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 42 गांवों में पीने का पानी नहीं है। एक गांव तो ऐसा है जिसका नाम रानीला है पैसे से खरीदकर वहां के लोग पानी पीते हैं। इस बारे में हमने महकमे से बात की तो उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, पानी की बहुत किल्लत है। 50 साल के बाद आजादी के बाद भी अगर यह होता है कि पीने का पानी खरीदकर मिलता है तो क्या हाल होगा ? इस प्रकार पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है और मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय से पहले भी प्रार्थना की थी कि पीने के पानी का उचित प्रबन्ध करवाया जाए। विशेषकर जहां पानी खरीदकर लिया जाता है उन गांवों के लिए जल्दी से जल्दी कोई स्कीम बनाई जाए ताकि उनको पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोड्स का प्रश्न है, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए ऐप्रोच रोड्स जो हैं, कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर है कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले 10 सालों से उन पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। और न ही कोई नई सड़क मंजूर की गई इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनका एस्टीमेट बनवाया जाए, उनका काम किया जाए और सड़कें बनवाई जाएं। मेरे हल्के की मैं पांच सड़कों का जिक्र करना चाहूंगा जिनको बनाना बहुत जरूरी है। ये सड़कें हैं बापोड़ा से प्रेम नगर, सूई से राजपुरा-खरखड़ी, धनाना से कुचपड़, बामला से कायला। अध्यक्ष महोदय, ये सड़कें एक

गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं इनके अलावा वहां आने जाने के लिए और रास्ता नहीं है और तिगड़ाना से मण्डाना सड़क भी टूटी हुई है। इस सड़क में तो गढ्ढे पड़े हुए हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इरीगेशन के बारे में कैप्टन साहब से कहना चाहता हूं कि सिरसा जिले में पानी की जो नालियां बनी हुई हैं उनमें चार-चार इंच की नालियों के अलावा कुछ नालियां 9-9 इंच की भी सिंचाई के लिए बनाई हुई हैं। हमारे भिवानी जिले में तो केवल चार इंच की नाली ही बनी हुई हैं और भिवानी का इलाका रेतीला इलाका है इसलिए वहां पर सिंचाई के लिए प्रत्येक नाली 9-9 इंच की बनाई जाये ताकि सरकार की तरफ से किसानों को सुविधा देने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसका किसान कुछ तो लाभ उठा सकें। जो नाली पहले चार इंच की बनी थी उनसे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त भिवानी जिले की कुछ टेल्ज ऐसी हैं जिनकी डिटेल मैं माननीय मंत्री जी को दे दूंगा, इनको आगे बढ़ाना और माईनर्ज को बनाना इसमें शामिल है। अध्यक्ष महोदय, बरसात का सीजन आने वाला है और 1995 के बाद हर साल कुछ गांव ऐसे हैं जो बरसात के दिनों में पानी में डूबते हैं। ये गांव है धनाना, बड़ेसरा तिगड़ाना तालू, मुंढाल मिताथल आदि। इन गांवों में बरसात का पानी न आ जाये और जो पानी इन गांवों में बरसात के दिनों में भर जाता है उसको निकालने के लिए उचित प्रबन्ध किए जायें। पिछली सरकार ने ड्रेनेज की जो स्कीम बनाई थी वह कारगर नहीं है। जब तक वहां पर पम्पिंग सैट्स लैवल के हिसाब से नहीं लगाये जायेंगे तब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा और कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर पम्पिंग सैट्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। धनाना से मण्डाना की तरफ तो पम्पिंग सैट लगाने की जरूरत नहीं है वहां का तो लैवल और अलाईनमैंट सही कर देने मात्र से ही पानी अपने आप निकल जायेगा। इसलिए मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जिन ड्रेनेज की लैवलिंग सही नहीं है उनकी लैवलिंग सही करायी जाये और जो दोबारा से बनने वाली हैं उनको दोबारा से बनवाया जाये। इसके अतिरिक्त मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भिवानी जिले में लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम के तहत पानी चलता है। एक बार चलने के बाद किसान यह चाहेगा कि उसे लगातार पानी मिलता रहे। लेकिन लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम के पम्पिंग सैट बिजली से चलते हैं और बिजली रात के समय ज्यादा आती है और किसान पूरी-पूरी रात जागता रहता है, कई दफा बिजली न आने पर किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम्ज पर आल्टरनेट जनरेटर्स का इंतजाम किया जाये ताकि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल सके। अध्यक्ष महोदय, बहन प्रसन्नी देवी जी ने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की बात कही। उनकी यह बात बिलकुल सही है और सभी सदस्यगण भी इस बात को मानेंगे कि हर गांव में कुछ घर ऐसे होते हैं जो अपने खर्चे से शौचालय नहीं बनवा सकते। बहुत से गांवों में शौच जाने केलिए न तो पंचायत की जमीन है और जो गरीब हरिजन हैं उनके पास तो अपनी जमीन भी नहीं है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांवों में विशेषतौर से जो एस०सी० हैं या जो दूसरे गरीब परिवार हैं जिनके पास साधन नहीं हैं उनके लिए शौचालय बनवाये जायें। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बड़े-बड़े दस गांव ऐसे हैं जहां पर शौचालय बनाने बहुत जरूरी हैं। ये गांव हैं धनाना, बामला, बौंद, तालू, सांवड़, सांजरवास और फौगाट आदि। इन गांवों में शौचालय बनाने के लिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बजट में प्रौविजन किया जाये और पैसा दिया जाये। इसके अतिरिक्त मैं बिजली के बारे में बात करना चाहूंगा कि जिस समय हरियाणा प्रदेश का कम्पलीट इलैक्ट्रीफिकेशन हुआ था उस समय गांवों और शहरों की आबादी बहुत कम थी। यह बात मैंने पिछले अधिवेशन में गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए भी उठाई

[श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा]

थी कि आजकल हर गांव और हर शहर में बिजली की लाईनें लोगों के मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं और लाईनों के तार भी बहुत लूज हैं । हम विभागीय अधिकारियों को बार-बार टैलीफोन करते हैं कि लाईनें खिंचवाई जायें लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मेरी सरकार से पुरजोर प्रार्थना है कि पूरे प्रदेश में जहां पर तारें पुरानी हो गई हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है उनको बदला जाये और जो बिजली की लाईन लोगों के घरों के ऊपर से जा रही हैं उनको हटवाया जाये ताकि दुर्घटनायें होने से रोकी जा सकें। मैं जिस समस्या का जिक्र कर रहा हूं यह पूरे प्रदेश की समस्या है केवल हमारी नहीं है इसलिए इस तरफ मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी अपना रूख नर्म करें। पिछले गवर्नर एड्रैस के दौरान मैंने स्पोर्टस के बारे में बात कही थी और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने ऑन दी फलोर ऑफ दि हाउस यह बात कही थी कि स्पोर्टस स्टेडियम के बारे में हम बात करेंगे। मैंने देखा है कि एशियाड और ओलम्पिक्स के मल्टी पर्पज स्टेडियम के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इसमें लीड करें और एक स्टेडियम आईडैंटीफाई करें। मैं यह कहता हूं कि जी०टी० रोड़ पर विशेषतौर पर करनाल एक ऐसी जगह है जहां सारी फेसिलिटीज अवेलेबल हैं। फिर भी मैं यह बात कहता हूं कि स्पोर्टस डिपार्टमैंट से या टैक्नीकल एक्सपर्टस से इस बारे में ऐग्जामिन करवा लिया जाए और वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाए। अगर वह स्टेडियम करनाल में बने तो उसका नाम कल्पना चावला रखा जाए जिससे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं ताकि आने वाले एशियाड और औलम्पिक्स में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरी पुरजोर प्रार्थना है कि इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी बात कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, दूसरे मन्त्रीगण तथा माननीय वित्त मन्त्री जी मोहाली क्रिकेट स्टेडियम देख चुके हैं। आज का समय इस प्रकार का है कि हम क्या-क्या फेसिलिटीज दे सकते हैं ? सिर्फ गुड़गांव ही हरियाणा में एक ऐसी जगह है जहां हम ऐसी फैसिलिटीज दे सकते हैं। फरीदाबाद में हमारे पास स्टेडियम है but because of pollution that has gone out of date. Now even the countries which are playing cricket like Australia and England, they object to play their matches in Faridabad. इसलिए सरकार से मेरी यह भी प्रार्थना है कि क्रिकेट स्टेडियम के लिए गुड़गांव में हमें उपयुक्त जगह दी जाए ताकि उसके लिए हम अपनी कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को संसदीय मामलों के मन्त्री माननीय श्री रणदीप सिंह जी ने हाउस को आश्वासन दिया था कि भविष्य में कोई गलत टैक्स नहीं लगेगा और मैं भी यह समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी और आज जो मंत्री हैं वे माननीय गवर्नर साहब से मिले थे उन्होंने तब यह कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो गलत टैक्स नहीं लगेगा। यह गल्त टैक्स न खानक में लगेगा, न गुड़गांव में और न फरीदाबाद में लगेगा। तीन दिन पहले ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि खानक में वही पहले वाले लोग एक बार फिर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर गल्त टैक्स किसी दूसरे रूप में लगाया जाए। इसलिए मेरी यह पुरजोर प्रार्थना है कि अगर इस तरह की बात किसी दूसरी स्थिति में लागू होती है तो इससे कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा और लोगों को इस बात का मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी श्री ओम प्रकाश चौटाला से मिली हुई है। क्योंकि गल्त टैक्स आज भी लगा हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्री जी से और हाउस से मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई गल्त टैक्स न लगाया

जाए। इन लोगों ने पिछले पांच साल में अरबों रुपये कमाए हैं और अब वे इस बात की दुहाई देते हैं कि उन्हें स्टेट को रॉयल्टी देनी है। क्या रॉयल्टी पर इन्होंने ठेका लिया था। उस समय यह फैसला किया गया था कि गलत टैक्स का प्रावधान होगा और गल्त टैक्स देना पड़ेगा। स्पीकर सर, आम जनता का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर कोई आदमी आज शराब का ठेका लेता है तो वह यह सोच कर लेता है कि उसको फायदा होगा अगर उसको फायदा नहीं होता है तो उसके लिए पब्लिक जिम्मेदार नहीं है और सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। मेरी यह प्रार्थना है कि गलत टैक्स किसी भी हालत में न लगाया जाए, चाहे वह रोड पर हो या चाहे वह पहाड़ पर हो। (विघ्न) स्पीकर सर, कम से कम 150 गांव ऐसे हैं जिनमें मिनी स्टेडियम की प्रपोजल है। पहले ऐसा होता था कि 50% पैसा सैंट्रल गवर्नमैंट का होता था 25% पैसा हरियाणा सरकार और 25% पैसा उस गांव का होता था जहां ऐसा स्टेडियम बनना होता है। कहा जाता है कि इसके लिए सैंट्रल गवर्नमैंट ने एड देनी बन्द कर दी है। स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट के पास कम से कम 150 ऐसी ऐप्लीकेशन्ज इन मिनी स्टेडियम्ज़ के लिए पैंडिंग पड़ी हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इस मामले को वे सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ भी टेकअप करें और दोबारा से इस स्कीम को लागू करवाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात और कहूंगा कि संविधान के 73वें अमैंडमैंट का मैंने जो जिक्र किया था, उसमें एक और बात हो सकती है, इसमें अधिकारीगण शायद इस बात को पसन्द नहीं करेंगे। क्योंकि इससे उनके हाथ से पावर निकल जाती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी राजनीतिक सूझ-बूझ का प्रयोग करते हुए 73 वीं अमैंडमैंट के लिए अपने प्रयास करने की कृपा करें। स्पीकर साहब, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं विशेषकर इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया । नमस्कार।

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : माननीय स्पीकर सर, सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्तमंत्री जी को बधाई देती हूं कि इन्होंने इतना अच्छा बजट हरियाणा की जनता को दिया है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। चाहे वह किसान है, चाहे महिलाएं हैं और चाहे व्यापारी हैं बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस सरकार को बने हुए अभी कम समय ही हुआ है फिर भी लोग अपने आपको हरियाणा में भयमुक्त महसूस करने लगे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने उनकी सरकार के आते ही महिलाओं के प्रति अच्छी सोच रखकर टीचर्ज की भर्ती में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत का आरक्षण रखा है। यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो गरीब लड़कियों की शादी के लिए 5100 रुपए दिए जाते थे उस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया है। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। इस बजट में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। जो ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस थी उसको माफ कर दिया गया है। किसानों के ऊपर जो गलत मुकदमें बनाए गए थे उनको भी वापिस ले लिया गया है। जिन किसानों की फसल ओला लगने की वजह से खराब हुई थी उनका मुआवजा भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा किसानों की भूमि अधिग्रहण करने पर जो मुआवजा था, उसको भी निर्धारित किया गया है और ऐसा करके इस सरकार ने किसानों के साथ न्याय किया है तथा उनको राहत दी है। स्पीकर सर, व्यापारियों का भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। मण्डी टैक्स माफ किया गया है। और इस सरकार ने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है उसमें भी व्यापारी वर्ग का ध्यान रखा गया है। व्यापारी इस नीति से बहुत खुश हैं। जहां तक हैल्थ का सवाल है, इसके लिए जो बजट

[श्रीमती सुमित्रा सिंह]

एलोकेट किया गया है वह टोटल बजट का 2.9 प्रतिशत है। मेरा वित्त मंत्री जी को सुझाव है उनको इस बारे में थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। 1990-91 से लेकर 2003-04 तक स्टेट में 35 हास्पिटल्ज़ थे। हैल्थ सैन्टर्ज 2866 से बढ़कर 2916 हो गए हैं । इसमें सिर्फ 1.7 प्रतिशत की इन्क्रीज है। जो बड़े हास्पिटल्ज़ हरियाणा में हैं वे 1991 में 8 थे और आज भी 8 ही हैं जबकि हमारी आबादी कितनी बढ़ गई है। जो स्टरलाईजेशन आप्रेशन थे वे 89,498 से बढ़कर 90,805 हुए हैं। इसके अलावा जो लूप और आई०ओ०डी० हैं उसमें 1,56,279 से घटकर 1,52,528 की फिगर हो गई है, इसमें कमी आई है। स्पीकर सर, हमें हैल्थ की तरफ ध्यान रखकर इसके बजट को इन्क्रीज करना चाहिए और हरियाणा में अच्छे हास्पिटल बनवाए जाने चाहिएं। अगर हम स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखें तो हमारा जो बर्थ रेट, डैथ रेट है, इनफैंट मोरेटेलिटी रेट है, पोपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है इसमें कमी आ सकती है। स्पीकर सर, मेरे हल्के के लोगों ने बजट के बारे में काफी कुछ कहा है और मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से इस बजट का समर्थन करती हूँ।

स्पीकर सर, मैं अब अपने हल्के के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगी। करनाल में एक सरकारी हास्पिटल है जो कि ब्रिटिश राज के समय का बना हुआ है। जब से यह हास्पिटल बना है तब से लेकर आज तक सरकार की तरफ से न तो इसकी कोई मरम्मत की गई है, न ही वहां पर कोई सुविधा दी गई है और न ही उस बिल्डिंग की देखभाल की गई है। सरकार की तरफ से उस हास्पिटल में किसी भी प्रकार की इम्प्रूवमैंट नहीं की गई है। कुछ वर्ष पहले करनाल के लोगों ने स्वयं पैसा इक्ट्ठा करके वहां पर एक नया ब्लाक बनवाया था तथा वहां पर दो नए ब्लाक बी०एण्ड सी० बनाने के लिए भी विचाराधीन थे लेकिन आज तक उन दोनों ब्लॉकस की न तो कोई नींव रखी गई है और न ही उनके बारे में कोई सोच-विचार किया गया है। स्पीकर सर, वहां पर सी०एम०ओ० का आफिस जिस बिल्डिंग में है उसको भी कंडम डिक्लेयर किया गया है, लेकिन वह वहां पर ऐसे के ऐसे ही चल रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि इस होस्पीटल में जो महिलाओं का प्रसूति गृह है, जहां पर डिलीवरीज होती हैं वह भी सैकैंड फ्लोर पर है लेकिन वहां पर लिफ्ट नहीं है जिसकी वजह से महिलाओं को वहां पर दिक्कत होती है। इसी तरह से वहां पर बजुर्गों को भी सैकैंड और थर्ड फ्लोर पर जाना पड़ता है, लिफ्ट न होने की वजह से इनको भी दिक्कत आती है इसलिए उस होस्पीटल में एक लिफ्ट लगायी जानी चाहिए। इसी तरह से करनाल में एक ट्रॉमा सैंटर बनाया गया था। इसका इस्तेमाल एक इमरजैंसी वार्ड की तरह हो रहा है न तो वहां पर कोई न्यूरोसर्जन है और न ही वहां पर कोई सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है । अभी करनाल में एक बिल्डिंग गिरने से चार बच्चों की मौत हो गयी। जो सीरियस बच्चे थे जब उनको ट्रॉमा सैंटर में लाया गया तो काफी देर तक तो वहां पर डाक्टर्ज ही अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद जब इन बच्चों के हैड में इंजरी की वजह से सीटी स्कैन करवाने की बात आयी तो वहां पर यह सुविधा उपलब्ध न होने की वजह से वहां पर काफी दूर इन बच्चों का सीटी स्कैन प्राईवेट अस्पताल में करवाने के लिए ले जाना पड़ा। लेकिन रास्तें में ही बच्चे की मौत हो गयी। उस एरिया में वहां पर और कोई ट्रॉमा सैंटर नहीं है, इसलिए वहां पर एक न्यूरोसर्जन और एक सीटी स्कैन की सुविधा जरूर उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। करनाल एक बहुत ही इम्पोर्टैन्ट सैंटर है। वहां पर आस-पास के इलाकों जैसे जुंडला और नीलोखेड़ी आदि जगहों से लोग आते हैं इसलिए वहां पर अलग से साइक्रैट्रिक वार्ड की भी सुविधा

होनी चाहिए। वहां पर काफी जले हुए केसिज आते हैं। कहीं पर महिलाएं जलायी जाती हैं या कहीं पर वे अपना काम करते हुए जल जाती हैं। इसमें इंफैक्शन होने का खतरा रहता है लेकिन वहां पर इसके लिए अलग से सुविधा नहीं है जहां पर जले हुए लोगों का इलाज किया जा सके। मैं चाहूंगी कि वहां पर अलग से यह सुविधा होनी चाहिए। इसी तरह करनाल में काचवा में फ्लाई ओवर बनाने की भी योजना है। काफी लोग वहां पर दूसरी तरफ रहते हैं जिसके कारण रोड पर ऐक्सीडैंट्स होते हैं । पिछली सरकार ने इस बारे में बहुत कागजी कार्रवाई की और कहा कि यहां पर फ्लाई ओवर बनाया जाएगा और तो और जाने से पहले उस समय के मुख्यमंत्री ने सिम्बोलिक तौर पर वहां पर उसका एक पत्थर भी रखा था इसलिए मैं चाहूंगी कि इस फ्लाई ओवर को जल्द से जल्द बनाया जाए। करनाल का बस स्टैंड पुराने शहर में स्थित है। ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि पुराने शहर में मेन बाजार में यह बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड को सैक्टर 12 में शिफ्ट करने की योजना थी जिसको पिछली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मेरी मांग है कि इस बस स्टैंड को जल्द से जल्द सैक्टर 12 में शिफ्ट किया जाए ताकि करनाल में ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। मैं चाहती हूं कि हरियाणा के जो बच्चे हैं, छात्र हैं वह खेलकूद में आगे जाएं। हरियाणा के हर जिले में शायद स्वीमिंग पूल बनाये गये थे ताकि हरियाणा में अच्छे तैराक बन सकें। हमारे करनाल में बहुत से बच्चे नेशनल लैवल या स्टेट लैवल पर प्रथम या द्वितीय स्थान लेकर आते थे लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है और इस बात का खेद भी है कि पिछली सरकार के जाते-जाते स्वीमिंग पूल के ठेके कहीं पर तीन साल के लिए और कहीं पर चार साल के लिए दे दिए। आज हालात यह हैं कि खिलाड़ी जो गांवों से आते हैं उनको इस स्वीमिंग पूल में केवल तीन से चार बजे तक एक घंटे का ही समय दिया जाता है और बाकी के समय को पैसा कमाने का साधन बना दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इन ठेकों को रद्द किया जाए और हमारे खिलाड़ियों को इन पूल्स में ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए ताकि हमारे खिलाड़ी अच्छे तैराक बन सकें। आज शिक्षा में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। करनाल जिले में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनके कमरों की हालत बहुत खराब है। इनकी इतनी खस्ता हालत है कि कई बार तो इनको देखकर डर लगता है कि कहीं ये गिर न जाएं और कहीं पर कोई इमरजैंसी न हो जाए। जो इस तरह के स्कूल हैं इनके लिए बजट में पैसे का खासतौर से प्रावधान किया जाए और नये कमरे बनावाए जाएं। कुछ ऐसी ही व्यवस्था बहुत सी बाल्मिकी बस्तियों की भी है। इन बस्तियों में बाल्मिकी भाई तीस साल से या चालीस साल से काफी संख्या में रह रहे हैं परन्तु न वहां पर पानी की व्यवस्था है, न वहां पर सीवरेज की व्यवस्था है और न ही वहां सड़क की व्यवस्था है। जब हम इस बारे में डिपार्टमैंट वालों से बोलते हैं तो वे कहते हैं कि यह कब्जे की जगहों पर बैठे हैं जब वे इतने सालों से बैठे हैं तो जो उनकी यह बेसिक नैसेसिटीज हैं उनको कम से कम सीवरेज,

13.00 बजे पानी और बिजली की सुविधा तो जरूर देनी चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे तो उन्हें कहीं बाहर अलग से बिल्डिंग जरूर खड़ी करने की व्यवस्था करके देनी चाहिए। करनाल में बहुत सी अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं जहां पर न सड़क है न पानी है और न सीवरेज है। इन कालोनीज को अप्रूव करके वहां के लोगों को बेसिक नैसेसिटीज देनी चाहिएं। मुझ से पहले बोलते हुए कर्ण सिंह दलाल साहब ने जो हाउस टैक्स के बारे में कहा उससे मैं भी ऐग्री करती हूं। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब हाउस टैक्स रैंटल वैल्यू पर लगाया जाता था पिछली सरकार ने डी०सी० रेट और जितनी आपकी कंस्ट्रक्शन है उस पर लगा दिया जो कि हमारी सरकार के समय से 10 टाईम आगे चला गया है इसके बारे में सोच-विचार करने की आवश्यकता

[श्रीमती सुमिता सिंह]

है। ऑक्ट्राय जो बंद की गई थी उससे किसी भी आम नागरिक को कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑक्ट्राय हटाने के बाद किसी चीज की कीमत में भी कमी नहीं आई। या तो हाउस टैक्स हटा दिया जाए और चुंगी लगा दी जाए या जो पहले हाउस टैक्स की पॉलिसी थी उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए। इसके अलावा जो लड़कियों की संख्या हरियाणा प्रदेश में कम होती जा रही है यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं मुख्यमंत्री जी की आभारी हूं कि उन्होंने इसके लिए नयी स्कीम लागू की है। इसके साथ-साथ हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम लोग, हमारे सरपंच व एम०सी० लोगों को इस बारे में जागरुक करें। एक चीज और कहना चाहूंगी कि म्युनिसिपल कमेटी के रिटायर्ड इम्प्लौयीज को पेंशन नहीं मिलती है उसको जरूर रैगुलराइज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज्यादा समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

श्री बलवंत सिंह (सढौरा, एस०सी०): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिए नहीं कि मैं विपक्ष में हूं। बजट भाषण देने की चीज नहीं होती है, बजट तो आंकड़ों का खेल है इसमें 2 और 2 चार होते हैं । जो सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है मैं इसमें सारे मुद्दों पर बात न करते हुए सिर्फ चार-पांच मुद्दों को ही टच करना चाहूंगा। बजट में प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जिसमें बिजली, पानी, सड़क और परिवहन आदि शामिल होते हैं उसके लिए 1180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पहले किसी भी सरकार ने बजट पेश किया तो इस काम के लिए कम से कम 45 फीसदी बजट का प्रावधान किया गया जब कि इस सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मात्र 39.34 प्रतिशत बजट का प्रावधान रखा। इससे एक बात साफ झलकती है कि एक तरफ तो सरकार बड़े बलंगबांग दावे करती है कि हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, पुल और सड़कें बनाएंगे और बजट में इसके लिए केवल 39.34 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है जो साफ एक तस्वीर सामने आती है कि सरकार का उस और कोई ध्यान नहीं। आज बहुत अच्छा है कि सरकार अच्छे काम करती है अगर सरकार अच्छे काम करती है तो हम हाउस में भी और हाउस से बाहर भी सरकार का समर्थन करेंगे। सरकार ने ओलावृष्टि के लिए किसानों का जो मुआवजा बढ़ाया है ठीक है पर यह तो 25 से 30 प्रतिशत ही है जबकि 17 अप्रैल 2001 को जो मुआवजा 600 रुपये प्रति एकड़ था, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला की सरकार ने उसे 2000 रुपये किया था और उसे 233 प्रतिशत बढ़ाने की बात की थी। आज पांच साल बाद 25 से 30 प्रतिशत बढ़ाते हैं और उसके बदले महंगाई नहीं देखते कि डीजल का क्या हाल है दवाई का क्या हाल है और बीज की क्या कीमत है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि सरकार ने उचित मुआवजा नहीं बढ़ाया। सरकार मुआवजा बढ़ाने का प्रचार रात-दिन करती है। अगर बढ़ाना ही है तो कम से कम दस हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा करना चाहिए ताकि हर किसान को राहत मिल सके और फायदा मिल सके। बदकिस्मती से इस महंगाई के युग में तीन हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की राशि मिले और आपका नुकसान 5-6 हजार का हुआ हो तो तबाही आपके सामने है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इसे और बढ़ाने का काम यह सरकार करेगी। आज स्वर्गीय राजीव गान्धी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर बनाने की बात बजट में कही गई है यह बहुत अच्छी बात है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिलने के बाद

वे अच्छे कम्पीटिशन में भाग लें और अच्छे आफिसर बनें, एकेडमिशियन बन सकें। यही हमारी इच्छा है लेकिन जब हम बजट देखते हैं तो बजट भाषण में यह प्रावधान किया गया है कि न्यू एक्सपैंडीचर स्कीम के नाम से उसमें केवल 5 लाख रुपये रखे गए हैं क्या 5 लाख रुपये में यूनिवर्सिटी बन जायेगी। इतनी राशि में तो एक स्कूल के दो कमरे भी नहीं बनते। इससे इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। मैं वित्त मंत्री से चाहूंगा कि वे इस बात का खुलासा करें कि यूनिवर्सिटी के लिए कितने बजट का प्रावधान रखा गया है। आज बजट में मॉडल स्कूल बनाने की बात कही गई है कि हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनायेंगे। यह स्कीम कहें तो नई नहीं है क्योंकि वर्ष 2004 में पंचकूला में एक मॉडल स्कूल बनकर चालू हो चुका है और 18 जिलों में सरकार बनाने जा रही है और बजट में प्रावधान रखा गया है और वित्त मंत्री ने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस यह कहा है कि एक स्कूल के बनाने पर तीन करोड़ रुपये खर्चा आयेगा और बजट में इसके लिए प्रावधान केवल 2.75 करोड़ रुपये का रखा गया है क्या हर साल एक स्कूल बनेगा या एक साल में सारे स्कूल बनेंगे, वित्त मंत्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करें। अभी चौधरी धर्मबीर सिंह और भाई दान सिंह जी सम्मानित सदस्य और कैप्टन अजय सिंह जो हमारे माननीय मंत्री जी है जब विपक्ष में बैठते थे तो पांच साल तक लगातार एक बात की आवाज आती थी कि एस०वाई०एल० का पानी नहीं आया तो तबाही हो जायेगी, दक्षिणी हरियाणा खत्म हो जायेगा और आज वली वारिस कैप्टन को पता है कि 4 जून, 2004 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एस०वाई०एल० बनेगी और बननी चाहिए तब कैसे हालत थे जब कि पंजाब सरकार ने एक कानून पास कर दिया था मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा, इसके लिए बजट में केवल एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि एस०वाई०एल० बनेगी परन्तु आज मेरे सत्ता पक्ष के दोस्त चुप बैठें हैं। कहने के लिए उनके पास कोई नयी बात नहीं है। दादूपुर-नलवी नहर जैसा कि आप बात करते हैं कि उसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह दादूपुर-नलवी नहर का लाभ स्पीकर साहब के एरिया के गांवों को भी मिलेगा और इससे उनको पानी मिलेगा, इसके लिए बजट में 43 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है उसमें 11 करोड़ रुपये इस्टैब्लिशमैंट के लिए और नहर के लिए केवल 32 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर बजट में कोई प्रावधान नहीं है तो क्या नारों से SYL बनेगी इससे साफ झलकता है कि सरकार की मंशा काम करने की नहीं है बल्कि लोगों गुमराह करके, नारे लगाकर वोट बटोरने की है। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बिलों की एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछली सरकार ने बड़ा प्रयास किया लेकिन बात नहीं बन सकी। आज मुख्यमंत्री जी के ब्यान से, वित्त मंत्री महोदय के ब्यान से एक बात साफ झलक रही है कि सरकार बिजली के बिल माफ करेगी, होने भी चाहिएं पर आज बिजली के बिलों का बकाया 2500 करोड़ के लगभग है। यह कोई बुक एंट्री नहीं है, बिजली के बिल विद्युत प्रसारण निगम को कैश के रूप में देने पड़ेंगे और अगर 2500 करोड़ रुपये कैश देने पड़े तो बजट का क्या होगा, इसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से प्रार्थना यह करूंगा कि वित्त मंत्री जी अपने जवाब में इसका खुलासा करें। मानेसर, कुण्डली और पलवल एक्सप्रैस हाइवे पिछली सरकार के समय में विचाराधीन था और अब की सरकार इसको बनाने जा रही है उसके लिए 1200 करोड़ रुपये का खर्च होगा। वह तो चलो कर्जे से आएगा और आ जाएगा, इसकी जमीन ऐक्वायर करने के लिए 600 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जिसमें 50 प्रतिशत हरियाणा सरकार देगी, 25 प्रतिशत इंडस्ट्री डिपार्टमैंट देगा और 25 प्रतिशत HSIDC देगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : जो इनकी इन्फर्मेशन है वह सही नहीं है, उसकी लैंड एक्वीजिशन का खर्चा 50 प्रतिशत दिल्ली गवर्नमैंट देगी, यह तो ज्वायंट प्रोग्राम है, हरियाणा सरकार ने 25 प्रतिशत देना है । (विघ्न)

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली की सरकार उसमें कुछ हिस्सा देगी। बजट में इसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 2 करोड़ से कौन सी जमीन एक्वायर हो जाएगी और कौन सी एक्वीजीशन हो जाएगी। यह मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा। इंडस्ट्रीयल पोलिसी की बात यहां आई, सरकार ने बहुत बड़े-2 प्लान बनाए हैं कि हम इंडस्ट्रीयल पौलिसी देंगे और उसमें 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। नई पौलिसी आई, हमने पढ़ा और देखा, आज से पहले जो इंडस्ट्रीयल पौलिसी थी उसके अनुसार जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्लॉट ले लेते थे और 3 साल में उसका कम्पलीशन दिखा देते थे उनको लैंड रेट में 20 प्रतिशत की छूट होती थी, अब इस सरकार ने उस छूट को खत्म कर दिया है। आज जब हम राहत कोई नहीं दे सकते तो अगर हम इंडस्ट्री जोन देना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हिमाचल में बद्दी और काला आम्ब की तरह सैन्टर से स्कीम लेकर आएं जिससे सारे प्रदेश को लाभ भी हो सकेगा और सरकार की वाह-वाही भी हो सकेगी। आज किस्मत से सैन्टर में कांग्रेस की सरकार है और यहां भी कांग्रेस की सरकार है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कुछ विशेष इंडस्ट्री लेकर आएंगे तो इससे हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को राहत मिलेगी और हर आदमी को काम मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । आज सरकार कहती है कि कहीं कोई भय नहीं है । मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मार्च, अप्रैल और मई 2004 में कितने मर्डर, कितनी बैंक डकैतियां, कितनी लूट और कितने बलात्कार हुए और इस मार्च, अप्रैल और मई में कितने हुए, यह आन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस हमें पता चल जाए, उससे अन्दाजा लग जाएगा कि जनता भयमुक्त है या भयग्रस्त है।

श्री अध्यक्ष : सढौरा साहब, अब आप बैठो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको पांच मिनट बोलने के लिए और दिए जायें क्योंकि इनका भय भी बड़ी मुश्किल से निकला है। इनके नेता मनाली गये हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, डाक्टर इंदौरा जी और चौधरी बलवंत सिंह जी खड़े हैं। एक बात है वह शायद इन पर लागू होती है, मेरे ख्याल से इन्हें उसको अमलीजामा पहना देना चाहिए क्योंकि इनके पास पूरा मौका है। किसी शायर ने कहा है कि—

जुलमत के तलातुन से उभर क्यों नहीं जाते और
उतरा हुआ दरिया है गुजर क्यों नहीं जाते।

अब कर लीजिए कब्जा। अब क्या दिक्कत है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपना शेर पूरा कर दूं कि—

यों सरे राह तुम खड़े हो तो गये पर
किस-किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते

इसलिए अब आप कब्जा कर लीजिए क्योंकि भय तो गया हुआ है। हमारी केवल आपसे यही विनती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलबीर पाल शाह (पानीपत) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तो सोचता था कि आप मुझे सबसे पहले बोलने के लिए समय देंगे लेकिन आप मुझे आखिरी में बोलने के लिए समय दे रहे हैं इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज जो चर्चाएं बजट पर हुई हैं उसके बारे में मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। सिर्फ एक-दो बात ही कहना चाहता हूं कि हम श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव में उतरे थे और हमारा एक चुनाव मैनीफैस्टो था। उसके बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 9 जून को यहां पर वित्तमंत्री जी ने अपना भाषण दिया, वह इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार की और नेताओं की नीयत साफ है। क्योंकि यह बजट बड़ा पारदर्शी बजट है इससे पहले इतना अच्छा बजट कभी नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, सुधार करने में समय लगता है और हर चीज एक दिन में काबू में नहीं आती । जो कुछ पिछली सरकार हमारे लिए छोड़कर गई थी उसको ठीक करने में कुछ समय तो जरूर लगेगा ही। पुरानी परम्पराओं को तोड़ने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उनके स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं कि हम कहीं भी फिसले नहीं हैं जो कुछ हमने कहा है वह हम करके दिखायेंगे। यह बात मैं इस मंच से कह रहा हूं और यदि अपोजीशन का रोल करना पड़ा तो वह भी हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट के ऊपर प्वाईंटवाईज सभी ने बोला है जो बात मैं कहना चाहता हूं वह मेरे अपने शहर की है। वैसे तो एक ताव से हांडी परख ली जाती है लेकिन यह समझ लेना जो समस्याएं मैं बताने जा रहा हूं वे समस्याएं हरियाणा में कहीं न कहीं अवश्य खड़ी हैं। उनका हमने हल करना है। मैं सबसे पहले पीने के पानी की बात करूंगा क्योंकि पीने का पानी पानीपत में contaminated है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन पानीपत में किसी भी ट्यूबवैल में पानी पीने के योग्य नहीं है, चाहे टैस्ट करवाकर देख लें। वहां पर लोगों को मजबूरी में पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि पानी की बहुत कमी है उस कमी को दूर करने के लिए तुरन्त पानीपत में कम से कम 50 ट्यूबवैल लगाये जायें तथा जो पहले ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनको और डीप किया जाये क्योंकि उनमें पानी का स्तर नीचे चला गया है जिसके कारण कई ट्यूबवैल तो बंद हो गये हैं । अध्यक्ष महोदय, पानीपत में एक तरफ तो यमुना है और दूसरी तरफ मुनक हैड है। ये दो-दो नहरे हैं लेकिन ट्यूबवैल में पानी का स्तर दिन-ब-दिन नीचे जा रहा है। वह पानी कहां गया यह हमें समझ में नहीं आता है। मैं मुख्य मन्त्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब एक बार वहां पर जा कर सभी ट्यूबवैल का पानी चैक करवाएं और देखें कि संक्रामक रोग पानीपत में किस प्रकार से फैल रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं मेरे दूसरे भाईयों और बहनों ने भी कही है वह अनअथोराईज्ड कॉलोनियों के बारे में है। जो लाल डोरे के अन्दर जमीन नहीं आती म्युनिसिपिल लिमिट के अन्दर जमीन नहीं आती उस जमीन पर लोगों ने अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन की हुई है। एक किस्म से जिन गिरोहों ने यह बेची है वह एक क्राईम है यह मैं मानता हूं लेकिन चिड़िया को भी अपना घोंसला प्यारा होता है। पिछली सरकारों के वक्त में क्या होता रहा है कि अगर पांच घर हैं और दो घरों का स्टे होता था तो दो घरों को छोड़ देते थे और बाकी के तीन घरों को गिरा देते थे । अगर तोड़ना है तो सभी का स्टे तोड़ कर तोड़ो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच वाले तोड़ दो और बाकी को छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पानीपत से जो एक्सपोर्ट होता है हमारे गरीब भाई जो बाहर से आकर यहां पर बसे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने पानीपत को नाम दिया है। जो करोड़ों रुपया हम अर्जित करते हैं और विदेशी

[श्री बलबीर पाल शाह]

मुद्रा कमाते हैं वह पैसा उन्हीं गरीब लोगों की वजह से ही कमाया जाता है जो अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको साफ और स्वच्छ पानी, सड़कें तथा बिजली देने के लिए मैं शासन से अनुरोध करूंगा। मुख्यमन्त्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले एक फण्ड बनाया जाए क्योंकि एन०सी०आर० कैपिटल रीजन में पानीपत आता है। इससे पहले पानीपत इकोलोजीकल टाऊन भी डिक्लेयर हुआ था लेकिन वह स्कीम ठण्डे बस्ते में चली गई, ठप्प हो गई और वहां पर कोई सुधार नहीं हुआ। सैंटर से इसके लिए काफी पैसा लिया जा सकता है और पानीपत शहर को सबसे बढ़िया शहर बनाया जा सकता है लेकिन इसमें हमारे ब्यूरोक्रेटस और हमारे राजनीतिक साथी कहां तक उलझे रहे यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि उन गरीबों की ओर भी ध्यान दिया जाए तथा उनकी दुआएं भी ली जाएं। उनकी बददुआओं की वजह से पिछली सरकार लंगड़ाती हुई चली गई। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि पानीपत में ऐजूकेशन के लिए इंस्टीच्यूट बहुत कम हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर लड़कियों का एक कॉलेज होना चाहिए। पानीपत में अगर कोई मैडिकल कॉलेज बन सके तो उसके लिए मैं मुख्यमन्त्री जी का बहुत आभारी हूंगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे शहर में सिविल हॉस्पीटल है वह बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है उसके अन्दर एक्सपैंशन का बड़ा स्कोप है। वहां पर न पूरे डॉक्टर्ज मिलते हैं और न दूसरी फेसिलिटीज मिलती हैं। डॉक्टर्ज का एक ही काम होता है कि अगर कोई सीरियस केस आ जाए तो उसको रैफर टू रोहतक। पानीपत जी०टी० रोड़ पर पड़ता है, वहां पर प्राईवेट वार्ड भी चाहिएं, उचित डॉक्टर्ज की सेवाएं भी चाहिएं और बढ़िया डॉक्टर्ज भी चाहिएं, यह सब बहुत ही जरूरी हैं। लोग यहां पर सड़क पर आते-जाते हैं और कई बार एक्सिडैंट्स होते हैं और घायलों को नजदीक के हॉस्पीटल में शिफ्ट करना पड़ता है। पानीपत इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी वहां पर मैडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं। मेरे ख्याल से किसी और शहर से इतना सेल्ज टैक्स नहीं जाता होगा जितना पानीपत से जाता है लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार ये आंकड़े चैक किये जाएं और पिछले 9-10 सालों में हमें जो कुछ नहीं मिला उसको आप एक बार हमारी झोली में डाल दीजिए हम इसके लिए आपके बहुत आभारी होंगे। इसके साथ ही साथ पानीपत में फ्लाई ओवर और मिनी सैक्रेटेरियेट बनाने के लिए आधारशिला चौधरी भजन लाल जी के जमाने में रखी गई थी और उसके बाद चौटाला साहब ने उसको उखाड़ कर अपने नाम की शिला लगा दी लेकिन वह आधारशिला वहीं की वहीं है। वहां पर अभी तक मिनी सैक्रेटेरियेट का कोई काम नहीं हुआ केवल नाम ही नाम हुआ है लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ। मुख्य मन्त्री जी, मैं आपको निमन्त्रण दे रहा हूं कि इस आधारशिला को उखाड़ कर दोबारा अपने नाम की शिला लगाओ और उसके लिए फण्ड्ज रिलीज किए जाएं ताकि वहां पर काम शुरू किया जा सके। हमें यह उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी स्पष्ट छवि वाले हैं, ऐसी सुथरी छवि वाले हैं और ऐसी ईमानदार छवि वाले हैं कि अगर कहीं पर कोई स्टोन रख दिया गया तो वहां पर काम होकर ही रहेगा इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर स्टोन रख दें। स्पीकर सर, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर साहब हमारे यहां पर गए थे और कह कर आए थे कि लैफ्ट और राईट पर बाईपास बनाएंगे और फ्लाईओवर भी बनवाएंगे। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि पानीपत की समस्या तभी हल हो सकती है जब यह फ्लाई ओवर और दोनों बाईपास बन जाएंगे। स्पीकर सर, यह जो पानीपत बस स्टैन्ड की जगह है बहुत ही मंहगी है। लेकिन विडम्बना यह है कि बस स्टैण्ड की अलग साईट सलैक्ट की गई थी

और डिपो की अलग साईट सलैक्ट की गई थी। वहां पर इतना ट्रैफिक हो जाता है कि रास्ता क्रौस करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरा मुख्यमंत्री जी से और ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर जी से निवेदन है कि उस बस स्टैण्ड की जगह को बेचा जाए और उसको बेचने से जो पैसा आए वह ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट में ही रखा जाए ताकि 6 महीने में ही नया बस स्टैंड बनाया जा सके और वर्कशाप बनाई जा सके और इसकी वजह से जो जी०टी० रोड की कंजैशन की समस्या है उसका हल हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा बात न करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time be extended upto 2.00 P.M.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The House is extended upto 2.00 P.M.

अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत

Transport Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, I want to seek your permission to inform the House that Shri Anil Bhardwaj, Legislator from Delhi and Shri Jai Parkash, M.P. are sitting in Speaker's Gallery. I welcome them on behalf of the House.

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रमेश गुप्ता (कुरुक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट 2005-2006 का सदन में पेश किया गया है उसका मुख्य तौर पर सभी जगहों पर स्वागत किया गया है। इस बजट में हर वर्ग का और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। खास कर के इण्डस्ट्री और पानी के वितरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बहुत ही काबिले तारीफ बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुरुक्षेत्र के विकास की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर कुरुक्षेत्र का विकास मानेसर की तरह किया जाएगा तो कुरुक्षेत्र का नाम भी दुनिया के नक्शे में लिया जाएगा। यह बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट क्षेत्र बन जाएगा। यहां पर दूसरे देशों से भी टूरिस्ट आने लग जाएंगे। मैं विशेष तौर पर वित्तमंत्री जी से कहूंगा कि वे कुरुक्षेत्र का ध्यान रखें। यहां पर इण्डस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, रेडियो स्टेशन है। अगर यहां पर एक पी०जी०आई० मैडिकल कालेज रोहतक की तरह खोल दिया जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। कुरुक्षेत्र रोहतक और चण्डीगढ़ के बीच में पड़ता है। इसके साथ ही यहां पर पंचायतों की जमीन लेकर एक एरोड्रम भी बनाया जाए। इस सरकार ने पानी को हरियाणा के हर कोने में पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन साऊथ हरियाणा में इसकी ज्यादा जरूरत है। एम०एल०एज० साहेबान ने वहां पर ज्यादा पानी देने का प्रस्ताव किया है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय, हमारे यहां पर जो पानी का स्तर है वह नीचे चला गया है। इसके

[श्री रमेश गुप्ता]
ऊपर अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो जो हमारा पैडी का उपजाऊ एरिया है इसका भी नुक्सान हो सकता है क्योंकि आज टयूबवैल्ज का पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है। दादूपुर-नलवी नहर का जिक्र शर्मा जी ने भी अपने भाषण में किया तो इसके लिए ज्यादा फंड्ज देकर इसका निर्माण किया जाना चाहिए। लाडवा क्षेत्र में जो बरसाती नाले चलते थे जो कि राजस्व रिकार्ड में भी कायम है अगर सिंचाई मंत्री ध्यान दें तो कोई भूमि भी नहीं लेनी पड़ेगी और इनको फिर से शुरू भी किया जा सकेगा। वहां पर राक्षी और सरस्वती नाले को यदि खोल दिया जाए तो इससे जल स्तर भी ऊपर हो जाएगा और सरकार को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से यमुनानगर में बनने वाले थर्मल पावर प्लांट से जो 600 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी तो इसका हम स्वागत करते हैं सारे क्षेत्र में इसका स्वागत हो रहा है क्योंकि इससे बिजली की कमी पूरी हो जाएगी। मेरा सुझाव है कि जो गांव हैं उनके लिए बिजली की अलग लाईन होनी चाहिए। आज गांवों में केवल 6-6 घंटे ही बिजली मिलती है जिसके कारण गर्मी के मौसम में सभी ग्रामवासियों को बहुत दिक्कत आती है इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि किसी योजना के तहत गांवों को बिजली की पावर लाईन के साथ जोड़ा जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे गांववासियों को बड़ी राहत मिलेगी और मुख्यमंत्री जी का जो इस बारे में सपना है वह भी पूरा हो जाएगा । मेरा अनुरोध है कि पैडी सीजन में हमारे इलाके को ज्यादा बिजली दी जानी चाहिए क्योंकि सारा दारोमदार ही बिजली पर निर्भर है। जो इंडस्ट्रियल पौलिसी घोषित की गयी है इसका भी हम स्वागत करते हैं। जो कुरुक्षेत्र जिला है इसमें अध्यक्ष जी पेहवा आपका इलाका भी है इसी तरह से शाहबाद और थानेसर का इलाका भी इसी जिले में आता है। मेरी मांग है कि इस जिले को भी बैकवर्ड जिला घोषित किया जाए ताकि जो सुविधाएं बैकवर्ड इलाकों को मिलती हैं वह हमारे जिले को भी मिल सकें। इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे हमारे जिले को भी फायदा होगा। जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी लड़की की शादी पर अब 5100 रुपये के बजाए 15000 रुपये देने की जो घोषणा की गयी है उसका भी हम स्वागत करते हैं। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यह सुविधा दूसरे वर्गों के जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको भी प्रदान करवायी जानी चाहिए क्योंकि दूसरे वर्गों में काफी लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। हाउस में भी यह डिसकशन हुई है कि यह सर्वे ठीक नहीं किया गया था इसलिए जो लोग इससे वंचित हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि इनका सर्वे और बुजुर्गों की पेंशन का सर्वे दोबारा से करवाया जाना चाहिए ताकि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। व्यापारियों के लिए जो घोषणाएं की गयी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज माननीय सुरजेवाला जी ने राईस मिलर्ज के बारे में बात की थी। मुख्यमंत्री जी जब कुरुक्षेत्र आये थे तो हमने उनसे इस बारे में बात की थी। जो हमारे राईस मिलर्ज का माल एक्सपोर्ट होता है उनको पहले एच फार्म का लाभ नहीं मिलता था लेकिन अब यह लाभ एक्सपोर्टर्ज को ही नहीं बल्कि राईस मिलर्ज को भी मिलेगा। जो राईस मिलर्ज का चावल है अगर वह एक्सपोर्ट होगा तो उसका भी टैक्स सरकार ने माफ किया है इसका भी लोगों ने स्वागत किया है क्योंकि राईस इंडस्ट्रीज को इससे लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही राईस इंडस्ट्रीज की कुछ और मांगें भी हैं जो हमने मुख्यमंत्री जी को दी थीं। मेरा अनुरोध है कि इनके बारे में कोई कमेटी बननी चाहिए जो मंडियों से और राईस से संबंधित हमारी मांगें हैं उनके बारे में भी गौर किया जाए और इनको पूरा किया जाए। मंडियों में जो ठेकेदारी प्रणाली है, जो सरकार खरीद करती है और जो ठेकेदार काम करवाते हैं वह कच्चे आढ़ती के द्वारा किया जाता है लेकिन बाद में

पेमैन्ट में दिक्कत हो जाती है। आज भी हमारे लाडवा में जो एफ०सी०आई० का ठेकेदार है वह अभी-अभी मंडी से काम करवाकर गया है उसकी पेमेंट अभी भी बकाया है। मेरा अनुरोध है कि डायरेक्टली कच्चे आढ़ती को इसकी पेमेंट सरकार द्वारा की जानी चाहिए ताकि इस तरह की पेमेंट में दिक्कत न रहे। अध्यक्ष महोदय, एक जो हाउस टैक्स के बारे और एस०टी० 38 फार्म के बारे में घोषणा पत्र में भी रखा गया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हाउस टैक्स पर विचार करेंगे और एस०टी० 38 फार्म को खत्म किया जाएगा क्योंकि चौटाला सरकार ने इसको कई गुना बढ़ा दिया था और खासकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 15-20 गुना बढ़ा दिया था। जो हमारे साथियों ने इस बारे में सुझाव रखे हैं अगर ये खत्म हो जाए तो इससे तो अच्छी बात नहीं होगी और चुंगी लग जाए तो इससे आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता। हाउस टैक्स खत्म होना चाहिए और एस०टी० 38 फार्म भी खत्म होना चाहिए यह मेरा अनुरोध है। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

डॉ० कृष्णा पंडित (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने एक स्वच्छ छवि का और भयमुक्त प्रशासन दिया है और जो पिछले दिनों में उप चुनाव हुआ उसमें न सरकारी पैसा खर्च हुआ, न सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया न सरकारी मिनिस्टर गए न वहां बैनर इस्तेमाल हुए, न पोस्टर लगे, न कटाउट लगे और न पुलिस ज्यादा लगी। ऐसा इलैक्शन दिखाता है कि हमारे सी०एम० साहब इंसानियत के कितने धनी हैं कि वे मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही पिछली सरकार के मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी को देखने व उनका हालचाल पूछने गए और स्पीकर साहब भी उनके साथ गए। अर्जन सिंह जी जो कि मेरे इलाके के साथ लगते छछरोली से एम०एल०ए० हैं उनका एक बात में मैं धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने जो यहां हाउस में अपनी स्पीच दी है उससे उनका मुख्यमंत्री महोदय में बहुत ज्यादा विश्वास झलकता है। कोई अच्छा काम किसी ने किया हो तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए। पिछले पांच साल में जो इन कुर्सियों पर बैठे थे और सामने वाली कुर्सियों पर बैठे थे उनमें काफी फर्क इन्दौरा साहब को भी दिखाई दे रहा होगा, मुख्यमंत्री महोदय कैसे उनके साथ जफ्फी डालकर मिलते हैं कैसा अपनापन दिखाते हैं इस बात की इंदौरा साहब को भी सराहना करनी चाहिए। स्पीकर साहब भी विपक्ष के साथियों को पहले मौका देते हैं। मैं पिछले तीन दिन से समय मांग रही हूं अब जाकर समय दिया है। स्पीकर साहब की इस बात में जितनी सराहना की जाए, कम है। जो विपक्ष के एम०एल०ए० हैं उनके हल्कों में काम न हों तो वे हमसे आकर कहें । अभी तक किसी हल्के के साथ सी०एम० साहब ने भेदभाव नहीं किया है। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर और सारे मंत्री किस तरीके से सबके साथ मिलजुलकर बात करते हैं, सबका साथ देते हैं इस बात के लिए जितनी सराहना की जाए, कम है। फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने जो बहुत ही बैलैंस्ड बजट पेश किया है उससे लोगों का मन मोह लिया है। वार्षिक योजना का आकार 2200 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपये किया है यह एक सराहनीय कदम है। जितनी भी योजनाएं दी हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूं। 442 करोड़ रुपया सोशल वैलफेयर के लिए रखा गया है इससे हैंडीकैप्ड और विधवाओं और वृद्धों को समय पर पेंशन मिल सकेगी और घरों में जो विधवाएं और वृद्ध बैठे रहते हैं उनको किसी पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। 280 करोड़ रुपया वाटर सप्लाई के लिए रखा है यह एक बहुत बड़ी जरूरत है जिससे काफी बीमारियां दूर हो जाती हैं। विपक्ष के साथियों को एक ही

[डॉ० कृष्णा पंडित]

बात देखने को मिलती है कि पानी नहीं है, सीवरेज सिस्टम खराब है और बिजली नहीं हैं। हमने देखा है कि इतना हैल्दी बजट जनता को देने का काम गरीब आदमी से जुड़कर और उसकी जरूरतों को पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है जिसके लिए हम अपने फाईनैंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब को बधाई देते हैं। जो कैलैमिटी फण्ड रखा है, कैलैमिटी एक ऐसी चीज है जिसको कभी नहीं रोका जा सकता । कैलैमिटी से गरीब आदमी पर जब बिजली गिरती है तो आप सोच सकते हैं कि उसका कोई प्रावधान अचानक नहीं कर सकते हैं। दूसरा पानी के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने बहुत की अच्छा कार्य किया है जिसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। राजीव गान्धी ऐजूकेशनल कालेज का प्रोपोजल, मॉडल स्कूल की बहुत बड़ी प्रतिबद्धता हमारी ऐजूकेशन को सुदृढ करेगी। आज हमारी ऐजूकेशनल पौलिसी है, आज हमारी ऐजूकेशन है जहां स्कूलों में जाते है, जितने दोरों पर हम गये हमने टीचर से पूछा कि उनके पास खाने के लिए क्या है। उस समय टीचर ने हमें बताया कि चावल हैं, दाल हैं, हमने बनाया नहीं तीन महीने और छ: महीने का आर्डर है कुछ नहीं बनाया क्योंकि आटा नहीं है। यहां क्रीटीसिजम करने का मतलब नहीं है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी और एजुकेशन मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम स्कूल के गरीब बच्चों को खाना और राशन देते है लेकिन वह टाईम पर नहीं मिलता। उनको राशन-पानी इतना जुटाया जाये कि उनको सामान वहां समय पर मिल सके क्योंकि गरीब आदमी के घर में चूल्हा इसलिए नहीं जलता क्योंकि राशन नहीं है, चावल नहीं है, आटा नहीं है अगर उनको स्कूल में खाना मिल जायेगा तो उन बच्चों का पेट भर जायेगा। स्पीकर साहब, हमें मुआवजा ज्यादा मिले। एक पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत स्कीम सबसे अच्छी है। स्पीकर सर, जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण किया है वह कमाण्डेबल है। अब दूसरा गरीब लड़कियों की शादी में 5 हजार की बजाये 15 हजार रुपये का कन्यादान देंगे, यह स्वागत योग्य है। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि जो लड़कियों के लिए इतना ध्यान किया है और सरकार ने तय किया है कि ऐसे कालेज खोलेंगी जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही होंगे आजकल लड़कियां पढ़ी-लिखी होती हैं। एक गरीब घर की लड़की भी यह चाहती है कि उसको नौकरी मिले और अच्छे स्थान में रहे। हमारे विल मंत्री जी ने एक ऐसा बैंक जिसमें सिर्फ लड़कियां ही काम करेंगी, खोलने की घोषणा की है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इम्प्लायमेंट यूथ स्कीम सबसे अच्छी स्कीम है। हमारे बेरोजगार युवकों की जो हर घर में प्रौब्लम है कि, जी नौकरी नहीं है, नौकरी न मिलने के कारण युवक भटक रहे हैं, रोज लड़ाई-झगड़े करते हैं और थाना कचहरी होते हैं जबकि उनके पास पैसा देने के लिए नहीं है। अगर उनको नौकरी मिल जाये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। स्वतंत्रता सेनानियों की पैंशन 1400 से बढ़ाकर 3500 रुपये की है इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। सबसे बड़ी चीज जो बिजली की है इसके बारे में कहा गया है कि We are committed to provide assured, reliable and affordable power supply to all categories of consumers in the State and segregation of agriculture load from rural domestic load. जब घर में जाते हैं तो रिलीफ नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा तो जब दोपहर का समय होता है तब बिजली नहीं होती और आराम नहीं मिल पाता। बिजली फैक्ट्रियों में चली जाती है अगर 2-4 घण्टे मिल जाये तो औरतों को आराम करने का समय मिलता है, बिजली का सेग्रेगेशन किया है यह सराहनीय कार्य है। माननीय स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगी कि हमारे यमुनानगर में जैसा कि पलाका साहब ने और भाई

अर्जुन सिंह जी ने कहा कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यमुनानगर से इन्द्री के रास्ते में कार टूट जाती है और सड़कें वैसी की वैसी ही हैं। दूसरी जो मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहूंगी वह यह है कि हमारे वहां पर जो रेलवे फाटक बना हुआ है उसकी सदियों से यह डिमांड रही है कि उस पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। एक साल पहले जब हमारे एम०पी० श्री नवीन जिंदल जी बने थे उस वक्त भी यह डिमांड हुई थी कि उस पर ओवर ब्रिज बनाया जाए क्योंकि रोज कई एक्सीडैंट होते हैं और वहां कई-कई घण्टे ट्रैफिक रुका रहता है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि इस ओवर ब्रिज को बनावाया जाए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। एक और चीज जो यमुनानगर के लिए सबसे जरूरी चीज है वह है ट्रांसपोर्ट जो हमारे सहारनपुर रोड को जाती है वहां सारे ट्रक और सारी ट्रांसपोर्ट खड़ी रहती है। वहां से निकलने वालों के डेली 2-3 एक्सीडैंट होते हैं और वहां घायलों को हौस्पिटल लाते-लाते अगर बच्चा हो तो वह रास्ते में ही मर जाता है। कोई बड़े आदमी को भी लाएं तो वह भी ऐसी हालत में होता है कि उसको PGI भेजा जाए तो वह वहां पहुंचने से पहले ही मर जाता है क्योंकि वहां ट्रौमा सैंटर तो है नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगी कि यमुनानगर में एक ट्रौमा सैंटर बनाया जाए। जो हमारा जगाधरी का सिविल हौस्पिटल है वह 30 बैडिड है और यमुनानगर सरकारी अस्पताल 50 बैडिड है। 50 बैडिड हौस्पिटल डेढ़ लाख की आबादी को कैप्चर करने के लिए थोड़ा है और उसमें सारे स्पैशलिस्ट भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि हमारे सिविल हौस्पिटल यमुनानगर और जगाधरी में सारे स्पैशलिस्ट लाए जाएं ताकि ये पता लगे कि हरेक गरीब आदमी के लिए वह हौस्पिटल इजली एप्रोचेबल है। गरीब आदमी प्राइवेट हौस्पिटल में जा नहीं सकता। सिविल हौस्पिटल में स्पैशलिस्ट का प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी और मैंने पहले भी उनसे रिक्वैस्ट की थी कि आप यह देखकर जल्दी से जल्दी इसका प्रावधान करें ताकि हमारे जो गरीब विलेजर्स हैं वे वहां जाकर सुविधाएं ले सकें। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगी जो कि सबसे जरूरी है। वित्त मंत्री जी जब पहले हमारे मील डे में यमुनानगर आए थे तो मैंने उनसे रिक्वैस्ट की थी कि हमारे यहां एक सीटी स्कैन और एक MRI की सख्त आवश्यकता है यमुनानगर और जगाधरी में सिटी स्कैन का कोई प्रावधान नहीं है, अगर किसी को हैड इंजरी हो जाती है तो हैड इंजरी के लिए उसको वहां से ट्रौमा के लिए जाना पड़ता है इसके लिए उनको चण्डीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है और वहां पर 4000 या 5000 रुपये फीस है जो कि नॉर्मल आदमी ऐफोर्ड नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो वायदा हमको किया था उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रावधान करवाएं। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा जरूरी चीज एक और है, मैडीकल कालेज की जो कि आप सब जगह खोलने के लिए कह रहे हैं। एक मैडीकल कालेज की हमारे यहां सख्त जरूरत है। वहां पर एक मुलाना में मैडीकल कालेज है और एक डैंटल कालेज है। डैंटल कालेज और मुलाना मैडीकल कालेज दोनों ऐसे हैं कि उसी को आप मैडीकल कालेज में कंवर्ट कर दें तो डिस्ट्रिक्ट अम्बाला के आस-पास , यमुनानगर और जगाधरी को वह सारा प्रैजैंट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप मेरी इस डिमांड पर जरूर ध्यान देंगे क्योंकि यह बहुत जरूरी है और हर आदमी के लिए इतनी दूर जाना आसान नहीं है। एक चीज अध्यक्ष महोदय मैं और कहना चाहूंगी कि यमुनानगर किसी टाइम में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन होता था। पेपर इंडस्ट्री, शूगर इंडस्ट्री, मैटल की इंडस्ट्री और प्लाईवुड की वहां फैक्ट्रियां हैं। पिछली दफा हमारे कई डैपुटेशंस माननीय मुख्यमंत्री

[डॉ० कृष्णा पंडित]

महोदय को मिले और वित्त मंत्री जी को भी मिले जिन्होंने यह रिक्वैस्ट की कि वर्ष 2000 के बाद जितनी फैक्ट्रियां बनी हैं उनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में नहीं लिया गया, इसलिए उसको ध्यान में रखा जाए क्योंकि इन फैक्ट्रियों के खत्म होने से सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि जितने भी पेड़ हैं, इनको फोरैस्ट से न जोड़कर ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से लिया जाए तो ये इंडस्ट्रीज भी चलती जाएंगी क्योंकि यमुनानगर और जगाधरी को इंडस्ट्रीज की वजह से जाना जाता है इसलिए मैं आशा करती हूं कि आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि हम किसी तरीके से इंडस्ट्रीज को चालू रख सकें। अध्यक्ष महोदय, एजूकेशन के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी। आज स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं और कई-कई जगह तो इतना बुरा हाल है कि बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। कई स्कूलों में तो बच्चे 100 हैं और वहां टीचर्स केवल 3 हैं इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में पूरे टीचर्स का प्रबन्ध करवाने की कृपा करेंगे। मैं आशा करती हूं कि इस पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए स्थान लेती हूं।

प्रो० दिनेश कौशिक (पुण्डरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस विधान सभा में, इस सम्मानित सदन में हमारे जिले से तीन बार अध्यक्ष की कुर्सी पर सदस्य चुने गये हैं। आदरणीय चट्ठा साहब मेरे जिले से ही बिलोंग करते हैं दो दफा तो चट्ठा साहब आप स्पीकर चुने गये हैं और एक दफा चौधरी ईश्वर सिंह जी स्पीकर के पद पर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को कांग्रेसी मैन मानता हूं क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेसी रही है लेकिन मैं आजाद कैंडीडेट के रूप में जीतकर यहां पहुंचा हूं। मेरे रोम-रोम में कांग्रेसी विचारधारा है और मैं पूरी तरह से सरकार को समर्थन दे रहा हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और वित्तमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बैलैंस्ड बजट हरियाणा प्रदेश की जनता को दिया। वित्तमंत्री जी द्वारा चारों तरफ चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता के उत्थान के लिए सभी पहलुओं की तरफ गंभीरता से ध्यान रखकर यह बजट दिया गया है ताकि पूरा स्टेट प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं । मुझे उम्मीद है कि हमारी यह सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी। मैं इसे हमारी सरकार इसलिए कह रहा हूं कि एक आध निर्दलीय सदस्य को छोड़कर सभी निर्दलियों ने सरकार को समर्थन दे रखा है। इसलिए यह सरकार हमारी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर दें क्योंकि कई दफा आपका हमारी तरफ ध्यान नहीं जाता । हमें बैठाया ही ऐसी जगह पर गया है जहां अपोजीशन वाले बैठते हैं। लेकिन हम तो सत्ता पक्ष के साथ हैं और उनको अपना भाई मानते हैं । (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि सदन में पहुंचने के लिए सभी साथियों ने कोई न कोई रास्ता अपनाया है मैंने भी अपना रास्ता अपनाया है। मैं बजट पर आना चाहूंगा कि हमारे वित्तमंत्री जी ने पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बजट के माध्यम से हमारे सामने रखी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राज्य में बहुत बड़ी तबदीली होगी, बहुत बड़ा चेंज होगा और उस चेंज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं यदि उन्हें शामिल कर लिया जाये तो मैं अपने आपको भाग्यशाली समझूंगा । वित्तमंत्री जी ने बजट के माध्यम से एजूकेशन के बारे में जो कुछ कहा है वह बहुत अच्छा है। मैं भी शिक्षा से संबंध रखता हूं इसलिए इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं । गांवों के अंदर जो शिक्षा स्तर

है वह दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है और यह इसलिए हो रहा है कि हमारे जो अध्यापक हैं वे गांवों में जाना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं वित्तमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बजट में उनके लिए ऐसा प्रावधान किया जाये कि हमारे अध्यापक गांवों में जाना पसंद करें। क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं यदि उनकी ड्यूटी शहर में रहती है तो उनको एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है। जिनकी ड्यूटी ए क्लास सिटी में होती है उनको उसी सिटी के हिसाब से भत्ता मिलता है और जिनकी डयूटी बी क्लास सिटी में होती है उनको उसी सिटी के हिसाब से भत्ता मिलता है तथा जिनकी ड्यूटी गांव में होती है उनको रूरल के हिसाब से भत्ता मिलता है। अगर गांव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों और अध्यापकों को भी ए क्लास सिटी के हिसाब से भत्ते दिए जायेंगे तो शायद वे गांव में ड्यूटी करना पंसद करेंगे। हमारे कई गांव ऐसे हैं जो कि रिमोट ऐरियाज़ में हैं जहां पर सुविधाएं नहीं हैं और जहां पर बहुत कम अध्यापक टिक पाते हैं क्योंकि उनके बच्चे अच्छे कॉलेजों में, अच्छी जगहों पर पढ़ना पसन्द करते हैं इसलिए वे गांव में नहीं रहना चाहते। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में दूसरे सदस्यों ने भी कहा हैं कि अध्यापकों के लिए तथा डॉक्टरों के लिए यह कम्पलसरी किया जाये कि पूरी सर्विस में कम से कम पांच या सात साल उनकी सर्विस किसी गांव में होनी चाहिए। आजकल जब हम सर्विस और ट्रांसफर की बात करते हैं तो शहरों के नजदीक के जो गांव हैं वहां पर तो सैंकड़ों की तादाद में छोटे से स्कूल में लोग जाना पसन्द करते हैं लेकिन जो रिमोट एरिया के स्कूल्ज़ वहां पर कोई भी अध्यापक यह नहीं कहता कि मुझे उस स्कूल में एप्वॉइंट किया जाए। माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे गांवों के लिए जो रिमोट एरियाज में हैं वहां का विशेष ध्यान रखें और ऐसा प्रावधान करें कि जो रिमोट एरिया में जाएगा उसको उतना ही पैसा ज्यादा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं सड़कों की बात करना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे अपने जो भाई हैं, हमारे जो सम्मानित साथी हैं वे डिटेल में ऐजूकेशन के बारे में काफी बात कह चुके हैं। इस बारे में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कई स्कूल्ज़ ऐसे हैं जहां पर 50 से भी कम स्टूडैंटस हैं। यदि उन स्कूलों का रिजल्ट ओरिऐंटिड किया जाए और उन अध्यापकों के ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी इम्पोज हो तो स्थिति में सुधार हो सकता है। यदि उन अध्यापकों को किसी प्रकार का डर हो कि अगर उनका रिजल्ट गन्दा आएगा तो उनकी इन्क्रीमैंट रोक दी जाएगी या सर्विस में कोई और रुकावट आएगी तो इससे शायद उनके काम में कुछ इम्प्रूवमैंट आए। माननीय वित्त मन्त्री जी से मेरी विशेषतौर पर प्रार्थना है और मुख्यमन्त्री जी से भी विशेष प्रार्थना है कि ऐजूकेशन की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि शिक्षा ही हमारा आधार है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे सड़कों की बात है। सड़कों की आज बहुत अधिक जरूरत है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसमें सड़कों के लिए भी बजट का प्रावधान रखा है लेकिन आज के समय में जहां हम उन्नति और तरक्की की बात करते हैं उसमें सड़कों का बहुत बड़ा महत्व है। सड़कों में जहां सुधार की बात आ रही है वहां कई जगह पर सड़कों पर ब्लाइंड मोड़ हैं और अगर कोई व्यक्ति पहली बार उस तरफ जाए तो उसको उन मोड़ों का पता नहीं लगता। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से पुण्डरी की बात कहना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति पहली बार इस सड़क पर जाता है तो उसको पता नहीं होता कि सड़क पर आगे क्या आ रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि आगे क्या आ रहा है। मोड़ इतने टेढ़े हैं कि आगे से आने वाले व्हीकल का पता नहीं चलता। वहां पर न कोई सिम्बल्ज़ हैं, न कोई निशान हैं और न ही कोई इस तरह की बात है जिससे हम लोग ऐक्सीडैंट को एवॉइड कर सकें। पुण्डरी में दो किलो मीटर का एक ऐसा एरिया है जिसमें हर दूसरे महीने एक मौत होती है। एक ऐसा ही मोड़ है जो पुण्डरी के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। एक बार तो वहां पर लगभग 18 लोग

[प्रो० दिनेश कौशिक]

मर गए थे। वह कौल का मैडिकल स्टाफ था, वे लोग जीप में जा रहे थे जिसमें 4-5 डॉक्टर्ज थे, नर्सें थी और दूसरा स्टाफ था वह पूरे का पूरा स्टाफ उस मोड़ पर सीधे नहर में जा गिरा और उन सब का देहान्त हो गया। जो ब्लाईंड मोड़ हैं वहां से लगभग 50 गज तक की रेंज में जो पेड़ हैं उनको काटा जाए ताकि आने वाले जो भी साधन हैं उनको सामने से आते हुए दूसरे व्हीकल्ज़ दिखाई दे सकें। इन सड़कों पर ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जिनका पता नहीं चलता और मोटर साईकल या दूसरे सवार जो पहली बार उधर जाते हैं जब वहां पहुंचते हैं तो वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ये स्पीड ब्रेकर्ज स्पीड कम करने के लिए हैं जान लेने के लिए नहीं हैं। अगर पहले ही पता हो कि स्पीड ब्रेकर आने वाला है तो सवार पहले ही सम्भल जाता है। वहां पर कोई निशान हों या किसी प्रकार के सिम्बलज़ बनें हुए हों तो वहां पर अनेकों जानों को बचाया जा सकता है। ऐसी अनजान सड़कों पर जा कर बहुत से लोगों की जानें जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि बजट के अन्दर ऐसे प्रावधान रखे जाएं जिसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

प्रो० दिनेश कौशिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का 14.00 बजे धन्यवादी हूं कि उन्होंने 10 मिनट और इन्तजार करना मान लिया। स्पीकर सर, हम विकासशील देशों से संबंधित हैं लेकिन स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि जो विकासशील देशों के लोग हैं वे हमसे बहुत आगे हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे हमारे सदन के साथियों को और आफिसर्ज के डैलिगेशन को विकासशील देशों का दौरा करवाएं ताकि हम वहां से वहां की बातों को सीख कर हरियाणा में अमल में ला सकें। **(इस समय मेंजें थपथपाई गई।)** स्पीकर सर, मुझे 35-36 बार विकासशील देशों में जाने का मौका मिला है। वे लोग हमारे से बहुत आगे हैं । हम जो कुछ भी आज अमल में ला रहे हैं वे लोग उसको हमारे से बहुत पहले ही अमल में ला चुके हैं। हम सभी सदस्यों को एक बार मुख्यमंत्री जी आपको बाहर ले जाना चाहिए। उसमें हमारे आफिसर्ज और डैलिगेशन भी जाएं। वहां का दौरा करने से हम यहां पर मैडिकल फैसिलिटी, ऐजुकेशन और कृषि के क्षेत्र में बहुत चेंजिज़ ला सकते हैं। हम अगर कोई रिसर्च करते हैं उसमें 10 साल लग जाएंगे और आज हम वहां पर जाते हैं तो आकर उनकी चीजों को यहां पर इम्पलीमैंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे समय की बचत होगी।

स्पीकर सर, दूसरे हमारे यहां अन-एम्पलाईमैंट की प्रौब्लम आज बहुत बड़ा मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और वित्तमंत्री जी से अनुरोध है कि जो आपने

टारगेट रखा है और जो बहुत अच्छी योजनाएं रखी हैं उनमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि हरियाणा में जो भी पढ़े-लिखे ग्रैजुऐट हैं उनको एक लाख रूपया डिग्री प्राप्त करते ही बिना इन्ट्रस्ट के दिया जाए ताकि वे अपने आप को सैटल कर सकें, स्वयं अपना काम कर सकें और अपने परिवार की आजीविका चला सकें। स्पीकर सर विकासशील देशों में ऐसा ही किया जाता है। स्पीकर सर, अगर किसी को बैंक से यह पैसा दिया जाएगा तो उसको पैसे लेने में काफी समय लग जाएगा। सरकार को ऐसा कोई प्रबन्ध करना चाहिए। ताकि उसको यह पैसा प्राप्त करने में कोई दिक्कत न आए और वह 5 या 6 साल में जब चाहे वह पैसा सरकार को बिना इन्ट्रस्ट के वापस कर दे। स्पीकर सर, इसके अलावा हरियाणा में प्राईवेट बसों की बहुत भारी समस्या है और वे जिस रूट पर फायदा देखते हैं उस रूट पर चल लेते हैं। ये प्राईवेट बसों वाले इंटीरियर एरियाज में नहीं जाते, जिससे वहां के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये बसों वाले तो एक-दो साल में नई बसें डाल लेते हैं मेरी सरकार से गुजारिश है कि जो अनपढ़, बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उन रूटों पर जाने के लिए अलाउ करें जिन पर बसें नहीं जाती हैं। जैसे पहले मैक्सी कैब चलती थी उसी तरह से इन बेरोजगार बच्चों को इन्टीरीयर रूटों पर आटो आदि चलाने की इजाजत दें। बसों के न आने से जिन लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता था उनकी मुश्किल हल हो जाएगी और अनपढ़ बच्चों को भी रोजगार मिल जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है सरकार ऐसी व्यवस्था भी करे कि उन बच्चों को पुलिस वाले तंग न करें और उनके चालान न काटें। वे बच्चे हेराफेरी करने की बजाए और चोरी करने की बजाए मेहनत से अपना तथा अपने परिवार वालों का पेट पालेंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार रिक्शा चलाने वालों, रेहड़ी लगाने वालों को और जो गांव के किसी भी कोने में काम करते हैं उनको भी लोन देने की सुविधा प्रदान करे। लेकिन अभी तक यह सुविधा उन तक नहीं पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्यमंत्री जी से और वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इस तरह का कोई प्रावधान अनएम्प्लायड यूथस के लिए जरूर होना चाहिए ताकि वे रास्ता न भटक जाएं। ऐसे लोगों को अपना रोजगार चलाने के लिए कोई फाईनैंशियल हैल्प भी दी जानी चाहिए ताकि वे अपना रोजगार चलाकर अपने बच्चों का पेट भर सकें। अध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथियों ने कहा है कि रूरल डिवैल्पमैंट होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रूरल डिवैल्पमैंट के लिए तो कोई भी फाईनैंशियल मदद नहीं की जा रही है। गांव में अगर किसी ने मकान बनाना हो तो उसको इसके लिए लोन नहीं मिलता। शहर में मकान बनाने के लिए तो लोन मिल जाता है लेकिन गांव में मकान बनाने के लिए लोन कहां मिलता है। आप देखें कि कितने गांवों में मकान ऐसे बने हैं जिनको बनाने के लिए बैंकों ने फाइनेंस किया हो या और किसी और इंस्टीच्यूशन ने फाईनैंस किया हो क्योंकि सबसे पहले उनको नक्शे की जरूरत होती है, सबसे पहले उनको जरूरत होती है म्यूनिसिपल कमेटीज की और वह गांवों में नहीं होती है। आज लोग गांवों से पलायन करके शहरों में आ रहे हैं। लोग इस तरह से शहरों में पलायन न करें तो मेरा अनुरोध है कि ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि गांवों में भी मकान बनाने के लिए लोन मिलने की सुविधा हो जाए जो कि अभी तक नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वह भी गांवों के लोगों को दी जानी चाहिएं चाहे वे किसी भी तरह की सुविधाएं हों। इसके अलावा मेरा एक अनुरोध यह भी है कि गांवों में एक बहुत बड़ी समस्या तहसील की और पटवारी की भी होती है। अगर लोग पटवारी के पास फर्द मांगने जाते हैं तो वह पैसे की मांग करता है। चाहे कोई फर्द लेनी हो या चाहे कोई इंतकाल चढ़वाना हो उसके लिए पटवारी बहुत ज्यादा पैसे मांगता है और दो-दो तीन हफ्ते तक चक्कर कटवाता है। जो लोग

[प्रो० दिनेश कौशिक]

उसको पैसे दे देते हैं उनका तो काम हो जाता है और जो पैसा नहीं देते हैं उनका काम नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके लिए भी टाईम बाउंड प्रावधान होना चाहिए कि जब कोई फर्द या इंतकाल चढ़वाने के लिए पटवारी को ऐप्लाई करे तो एक दिन या दो दिन में उसका यह काम हो जाए। मेरा एक अनुरोध यह भी है कि जो पैसा पटवारी की जेब में जाता है अगर वह पैसा कुछ एक सीमा में सरकार के पास रैवेन्यू के रूप में आ जाए तो शायद इसमें कोई बुराई भी नहीं होगी क्योंकि जो फीस पांच, दस, या बीस रूपये है जो सरकारी फीस होती है उसके बजाए यदि आप उसको बढाएं और यदि आप टाईम बाउंड कर दें तो ठीक रहेगा। अगर ज्यादा पटवारी हों, ज्यादा लोग रोजगार में हो तो शायद गांवों वालों को भी इससे राहत मिलेगी क्योंकि एक फर्द लेने के लिए कई सौ रुपये या हजारों रुपये उन्हें रुपये देने पड़ते हैं तो इस तरह का कोई न कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए और लोगों को इनके चुंगल से छुटकारा दिलवाया जाना चाहिए ताकि लोगों को इनसे राहत मिल सके और वे अपनी जमीन की समय पर फर्द ले सकें। अध्यक्ष महोदय, जो भी हमारे इलाके में काम हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कौशिक साहब, अब आप वाईंड अप करें।

प्रो० दिनेश कौशिक : मैं एक बात और सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि एक ऐडोप्शन सिस्टम है। आम तौर पर जब हम बाहर जाते हैं तो वहां पर सड़क के किनारे लिखा होता है adopt a mile तो we can say adopt ten miles. तो एक रिसपौंसिबिलिटी हो। सड़कों की सुरक्षा के साथ-साथ सड़कों के रख-रखाव की रिसपौंसिबिलिटी वहां की पी०डब्ल्यू०डी० की और दूसरे लोगों की होनी चाहिए। जो सड़कों के किनारे वृक्ष खड़े होते हैं और उन वृक्षों से जो पानी टपकता है वह सड़कों को तोड़ देता है इसलिए इन सड़कों को उन वृक्षों से दूर रखा जाना चाहिए और समय-समय पर इनकी कटायी करवायी जानी चाहिए ताकि सड़कों पर इनसे जो गढ्ढे बन जाते हैं उनसे इनको बचाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 15th June, 2005.

14.10 Hours (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 15th June, 2005).